हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 15 मार्च, 2016 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

15/03/2016/1100/RG/AG/1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक 10 मार्च, 2016 को नियम-67 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया था और आज पांच दिन बीत गए हैं, उस पर कुछ नहीं हुआ। न केवल मात्र कुल्लू-मनाली बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन से जुड़े हुए लोगों के लिए यह एक जबरदस्त झटका है। वे लोग वहां से पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं।----(व्यवधान)---दिनांक 6-2-2014 के बाद कुल्लू-मनाली में लोग बेरोजगार हो गए हैं। आज होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों की लगभग 55% तक बुकिंग कैंसिल हो गई है। आज पैराग्लाइडिंग वाले बेरोजगार हैं, रिवर राफ्टिंग वालों को समस्या है, कोट-बूट बेचने वालों का कारोबार बंद है। वहां उनके ढाबे, खोखे इत्यादि तोड़े गए हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने वीरवार को नियम-67 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के दिशा-निर्देश के कारण से कुल्लू-मनाली में जो अराज़कता का वातावरण फैला हुआ है उस सबको दूर करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार न तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल में और न ही सुप्रीम कोर्ट में ठीक प्रकार से जनता का पक्ष रख पा रही है। जिसके कारण आज लोग इस हद तक बेरोजगार हो गए हैं कि आज टैक्सी कारोबार भी बंद होने के कगार पर है।

अध्यक्ष : आप स्टेटमेंट बंद कीजिए और अपनी बात रखिए। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप बैठ जाइए।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष : आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप तो पूरा विषय ही बोलने लग पड़े। अभी तक प्रश्नकाल आरम्भ भी नहीं हुआ। मैं यह कह रहा हूं कि जब यह मामला यहां आएगा, तो आपको बोलने दिया जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार किसी भी तौर पर कहीं भी

15/03/2016/1100/RG/AG/2

केस को नहीं ले रही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने वीरवार को नोटिस दिया है और नियम-67 के अन्तर्गत दिया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष : अगर आपने नोटिस दिया है, तो आप उसका जवाब सुनिए। एक मिनट आप बैठिए।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपूर्ण विषय पर यहां चर्चा नहीं होगी, तो कहां इस विषय पर चर्चा होगी?

अध्यक्ष : श्री गोविन्द ठाकुर जी, वह हमने सरकार को टिप्पणी के लिए भेज दिया है। जब उसका जवाब आएगा, तो आप उस पर बोलिए।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अब पांच दिन बीत रहे हैं,जवाब कब आएगा?
अध्यक्ष : जब उसका जवाब आएगा, तो कंसीडर करेंगे, उसको टेक अप करेंगे, मैं उस पर विचार करुंगा।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में कई बार प्रतिनिधि मण्डल माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बार नहीं, हर बार एक ही आश्वासन दिया है कि हम इस विषय में एस.एल.पी. करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए कोई वरिष्ठ अधिवक्ता करेंगे, लेकिन लगभग इसको तीन साल बीत रहे हैं, न तो कोई एन.जी.टी. में गया और न ही सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए कोई एस.एल.पी. की गई है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर सरकार की टिप्पणी आने दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि जब कोई व्यक्तिगत केस होते हैं तब तो पी.चिदम्बरम और कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता

यहां आते हैं और जहां हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं वहां पर कोई वरिष्ठ अधिवक्ता नहीं आ रहा।

Speaker : Not to be recorded. देखिए, this is wrong.

15/03/2016/1100/RG/AG/3

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है इस समय नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा नहीं हो सकती। आपने इनको बोलने की अनुमति दे दी। यह प्रश्नकाल का समय है।

अध्यक्ष : देखिए, आपने नियम-67 के अन्तर्गत नोटिस दिया है। उस पर हमने सरकार की टिप्पणी मंगवाई है। जब वहां से टिप्पणी आएगी, तो उस पर मैं विचार करुंगा। मैंने आपको कह तो दिया। ---(व्यवधान)---श्री पवन काजल जी का प्रश्न है।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को नोटिस दिए हुए आज पांच दिन हो गए हैं इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस पर तुरन्त चर्चा कराइए।

अध्यक्ष : मैंने कह दिया कि इस पर सरकार से टिप्पणी मंगवाई है, यह नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल का मामला है और जब सरकार से इस पर टिप्पणी प्राप्त होगी, तो उस पर विचार करेंगे। अब बात खत्म हो गई। ---(व्यवधान)---आप बैठ जाइए।

एम.एस. द्वारा अगले वक्ता शुरू

15/03/2016/1105/MS/AG/1

अध्यक्षः धूमल जी बोलिए।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के तहत पांच दिन पहले एक नोटिस दिया गया है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि मैंने सरकार को टिप्पणी के लिए भेजा है।

नियम-67 का प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हों उन पर तुरन्त सदन की कार्यवाही सस्पैंड करके चर्चा की जाए। हम मान सकते हैं कि आप बजट में व्यस्त थे लेकिन पांच दिन के बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं कि सरकार से उत्तर ही नहीं आया है? विधायक महोदय या अन्य जो उस जिला के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको वहां पर लोग घेरते हैं कि सरकार ने हमारी सहायता ही नहीं की, सरकार ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। इसलिए सरकार ने उस पर क्या किया है, इसमें चर्चा करने के लिए नियम-130 या अन्य किसी भी नियम के तहत आप चर्चा तो अलाऊ करते। मैं मानता हूं कि नियम-67 के तहत आप बजट सत्र में जब तक बजट पास नहीं हो जाता, चर्चा अलाऊ नहीं करेंगे लेकिन नियम-130 के तहत तो चर्चा अलाऊ कर सकते हैं ताकि इनकी बात भी आ जाए। आप नियम-63 या नियम-130 के तहत, जिसमें भी उचित समझें, चर्चा अलाऊं कीजिए ताकि माननीय सदस्य का पक्ष भी आ जाए और सरकार का पक्ष भी आ जाए तथा जो वहां पर हजारों लोग बेरोज़गार हो गए हैं उनकी समस्या का भी कुछ समाधान हो जाए। वास्तव में सरकार के माध्यम से केन्द्र में NGT के पास या उच्चतम न्यायालय में अगर मामला जोरशोर से उठेगा तो निश्चित तौर पर इसका समाधान होगा। श्रीश्री रवि शंकर के मामले में भी NGT ने ऐसा ही किया। यह एक ऐसी संस्था बन गई है जो बहुत महत्वपूर्ण भी है लेकिन कई मामलों में इस तरह का दखल भी देती है। अब वहां हजारों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। स्वाभाविक है कि जब माननीय विधायक वहां जाते हैं तो वे इनको घेरते हैं कि हमारी समस्या का क्या समाधान निकला। मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी भी नियम के तहत इस पर चर्चा अलाऊ कीजिए ताकि सबकी बात आ जाए। इसमें सरकार का पक्ष भी आ जाए और सरकार पक्ष ही न रखे बल्कि उच्चतम न्यायालय तक केस भी लड़े।

15/03/2016/1105/MS/AG/2

अध्यक्षः माननीय धूमल जी, मैं आपसे यह बात कहना चाहता हूं कि जो मामला आप नियम-67 या अन्य किसी नियम के अंतर्गत देते हैं उस पर टिप्पणी आने पर ही मैं विचार कर सकता हूं, उसको रख सकता हूं, वह चाहे किसी भी नियम के तहत हो। लेकिन जहां तक इस मामले का सवाल है, इसको हमने सरकार को भेजा है। यह NGT का मामला है इसमें सरकार एक्शन ले रही होगी। मुझे इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है इसलिए इसके लिए मैं चर्चा अभी अलाऊ नहीं करूंगा।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य और मान्य सदन को यह अवगत करवाना चाहता हूं कि NGT ने जो भी कार्रवाई मनाली या मनाली से आगे रोहतांग यात्रा पर की है, उसका हमने हर कदम पर विरोध किया है और अपने सुझाव दिए हैं। यह कहना कि सरकार ने NGT में जनता की तरफ से पैरवी नहीं की, यह गलत है। हमने अच्छे-से-अच्छे वकील देकर वहां पर हर पेशी में मनाली की जनता का पक्ष रखा है और जो उनको असुविधा हो रही है उसके बारे में जोरदार तरीके से बात उठाई है। अब यह जो फैसला है, यह अंततः NGT ने करना है और जब तक NGT फैसला नहीं करती, तब तक हम उसके फैसले के विरोध में उच्चतम न्यायालय में भी नहीं जा सकते हैं। फैसले के बाद ही वहां जा सकते हैं।

15/03/2016/1105/MS/AG/3

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष जी, जो माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं, उसके बारे में मेरा यह कहना है कि सरकार ने कभी भी ठीक प्रकार से वहां अपना पक्ष नहीं रखा है। सरकार ने अपने हाथ काटकर दे दिए हैं। इनके एडवोकेट जनरल और सरकारी अधिकारियों ने वहां पर बिना किसी बहस के एफेडेविट दिया है कि जो-जो गाईड-लाइन्ज आपकी हैं हम उन सबको मानते हैं। एक तरफ तो ये जनता में जाकर कहते हैं कि हम जनता का पक्ष रखेंगे लेकिन इन्होंने अपने हाथ काटकर NGT में दिए हैं। अध्यक्ष जी, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि दिल्ली में NGT की चैम्बर मीटिंग में इनके एडवोकेट जनरल ने यह कहा कि हम रोहतांग के लिए सी0एन0जी0 बसिज चलाएंगे।

जारी श्री जे0के0 द्वारा---

15.03.2016/1110/जेएस/एएस/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः--------**जारी**--------

हम गैसकिट से वहां पर सी0एन0जी0 पहुंचाएंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश में सी0एन0जी0 आई नहीं है और सरकार की नालायकी के कारण

दो बसें दिल्ली से लेकर आए और रोहतांग तक ट्रायल किया, उसमें 60 लाख रूपया खर्च किया। जो दिल्ली में 35 रूपये किलो मिलती है वह रोहतांग के लिए 70 रूपये किलो मिलेगी। यह 60 लाख रूपया कहां से खर्च किया? सरकार के अधिकारी कहते हैं कि हम वहां सेगैसकिट से और टैंकर के माध्यम से लेकर आएंगे। सरकार ने अभी तक भी किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट में .....(व्यवधान).....

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप जिस विषय पर बोल रहे हैं, विषय का समाधान करने के लिए इसे सरकार के लिए भेजा है।.....(व्यवधान)..... आपकी जो समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए इसको सरकार को भेजा है। सरकार को इसका समाधान करने दीजिए।

Chief Minister: He is interested party. शुरू में जो मामला बिगड़ा है वह इन्होंने जो लोगों को बहकाया और स्थानीय लोगों को कोर्ट तक पहुंचाया, उसकी वजह से हुआ है। बजाए मामले को सुलझाने के He is trying to make political capital out of it. आपका बेसिक इन्ट्रस्ट है कि मनाली में आग सुलगती ही रहे वहां का फैंसला न हों और लोगों को एक्सप्लॉयट किया जाए। मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूं। जहां तक मामला है .....(व्यवधान)..... हम आपसे बात नहीं करेंगे। .....(व्यवधान).....

अध्यक्षः माननीय सदस्य एक मिनट रुकिए। .....(व्यवधान)..... एक मिनट रुकिए। गोविन्द सिंह ठाकुर जी प्लीज बैठिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप जो समस्या बता रहे हैं, उस समस्या का समाधान सरकार करेगी। हमने यह मामला सरकार को भेज दिया है। .....(व्यवधान).....आपने अब क्या बात करनी है? इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। This is not the time for discussion. यह डिस्कशन मैंने अलाऊ नहीं किया है। अभी तक हमारे पास यह विषय ही नहीं आया है।

15.03.2016/1110/जेएस/एएस/2

आप किस चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं? जब तक मेरे पास कोई विषय नहीं आएगा मैं चर्चा के लिए अलाऊ नहीं कर सकता हूं। यह गलत बात है । Not to be recorded. .....(व्यवधान).....

मुख्य मंत्रीः यह गलत बात है। अगर मैं अपना मुकद्मा लड़ता हूं उसके लिए मैं वकील सरकारी खर्चे पर नहीं ले जाता हूं। मैं वकीलों को अपने खर्चें पर ले जाता हूं। आप क्या बात कर रहे हैं? What is this non-sense? ...व्यवधान).....

अध्यक्षः बैठ जाईये। देखिए इस चर्चा पर मैंने कोई टाईम नहीं दिया है। अगर टाईम देंगे तो चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो चर्चा का टाईम नहीं है। अभी विषय भी मेरे पास नहीं है। आप बोल रहे हैं लेकिन कोई विषय तो मेरे पास आना चाहिए। जब विषय आएगा मैं तभी अलाऊ करूंगा। यह गलत बात है। हमने इसे सरकार को भेजा हुआ है। सरकार का जब ज़वाब आएगा तब उस पर चर्चा के लिए विचार किया जा सकता है। This is not the time to discuss the thing without subject. मेरे पास कोई विषय नहीं है आप यहां पर समस्या बता रहे हैं उसके समाधान के लिए मैं सरकार को बोलूंगा। .....(व्यवधान).....प्लीज, यह गलत बात है। प्लीज, धूमल साहब आप क्या बोलना चाहते हैं? धूमल साहब आपसे निवेदन है कि इस बात का विषय जब तक नहीं आएगा तब तक चर्चा के लिए अलाऊ नहीं किया जा सकता है

15.03.2016/1110/जेएस/एएस/3

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, इस विषय को आप ही हल कर सकते हैं। जैसे कि हमने सजैस्ट किया कि नियम-63 या 130 में आप चर्चा को अलाऊ करें। सरकार का पक्ष भी आ जाएगा। सरकार क्या कदम उठाएगी पता लग जाएगा? मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से कहूंगा कि इन्होंने विधायक को कहा कि इन्ट्रस्टिड पार्टी है। विधायक सबसे ज्यादा इन्ट्रस्टिड पार्टी है और हम सभी इंट्रस्टिड पार्टी हैं, क्योंकि हजारों बेरोज़गारों का सवाल है। इनके चुनावक्षेत्र का सवाल है। आपके चुनाव क्षेत्र में भी होगा तो आप भी इंट्रस्टिड पार्टी होंगे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

15.03.2016/1115/SS-AS/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल क्रमागतः

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन रहेगा कि in the heat of exchange of arguments में इस तरह का माहौल हो गया है। लेकिन जो माननीय विधायक पांच दिन से आपकी डायरैक्शन का इंतजार कर रहे थे, स्वाभाविक है कि वे उत्तेजित हैं। वहां के लोग उत्तेजित हैं। मैंने पहले ही निवेदन किया कि जब विधायक वहां जाता है तो लोग पूछते हैं कि क्या करके आए हो। पिछले सप्ताह ये व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली वकील करने के लिए गये जो केस वहां हो रहा है। सरकार भी इसको वैरिफाई करे कि अगर एडवोकेट जनरल ने कहा है कि Whatever you have said we agree with that..अब सी0एन0जी0 ला पायेंगे या नहीं ला पायेंगे और कितनी बसें सम्भव हैं तथा बाली जी बैठे-बैठे सिर हिला रहे हैं कि नहीं ला पायेंगे। यह सम्भव नहीं है। इसलिए ऐसी इम्पॉसिबल सुजैशन्ज़ को डिस्कस करने का कोई लाभ नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा कि समस्या बहुत गम्भीर है। हज़ारों लोगों की रोज़ी-रोटी का सवाल है। उन्होंने कर्ज़ा लेकर टैक्सियां ली हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आपके चाय-बागान का इश्यु आयेगा तो आप भी ऐसे ही ऐजीटेटिड होंगे क्योंकि आप उनको रिप्रैजैंट करते हैं और ये अपनी कांस्टीचुऐंसी को रिप्रैजैंट करते हैं। इसका हल यही है कि इस विषय पर चर्चा हो और सरकार एश्योर करे कि जब तक एन0जी0टी0 में ज़रूरत है तो वहां और अगर सुप्रीम कोर्ट में ज़रूरत पड़े तो वहां सरकार अपने लोगों का पक्ष ठीक ढंग से रखेगी।

15.03.2016/1115/SS-AS/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को चर्चा करने में कोई गुरेज़ नहीं है। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उन्होंने जो रोहतांग के बारे में कदम उठाये हैं मैं एक नागरिक के रूप में कहना चाहता हूं कि They are totally uncalled for and unnecessary.जो पर्यावरण है वह बचना चाहिए। क्या अगर मनाली से रोहतांग तक ही गाड़ियां जाएं तो उससे पर्यावरण खराब होगा? रोहतांग से आगे भी दुनिया है। रोहतांग से आगे लोग लाहौल को जाते हैं और उधर से स्पिति को भी रास्ता है। कश्मीर को जाते हैं। लद्दाख को जाते हैं तो महज मनाली और रोहतांग के बीच में ही कौन-सा ऐसा पहाड़ टूट

गया, जिससे कि गाड़ियां चलने से वहां पर पर्यावरण खराब हो जायेगा? रोहतांग के अंदर कोई ग्लेशियर नहीं है। Glacier are very far away. गाड़ियां चढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे, यह बात नहीं है। I have all respect for the Green Tribunal, but I don't agree with the conclusion drawn and the action taken by them. ये मैं कहना चाहता हूं। हमने हमेशा वहां जनता का पक्ष रखा है चाहे वह टैक्सी चलाने की बात है या चाहे वहां पर लोगों को सहूलियत देने की बात है। हर पेशी में हम वहां पर जनता का पक्ष रखते हैं और मैं समझता हूं कि जनता का जो सही पक्ष है उसको हमने जोर-शोर से रखा है परन्तु ट्रिब्यूनल की जो रूलिंग है the Government cannot ignore it. --(व्यवधान)-- एडवोकेट जनरल ही नहीं है और भी कई वरिष्ठ वकील वहां लड़ते हैं और एडवोकेट जनरल ने कभी अंडरटेकिंग नहीं दी कि आप वहां पर सी0एन0जी0 की बसिज़ चलाईये। He has never given any such undertaking.

15.03.2016/1115/SS-AS/3

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक सी0एन0जी0 की बसों का मामला है ए0सी0एस0 (फॉरैस्ट) और ए0सी0एस0 (ट्रांसपोर्ट) ने बार-बार अपना पक्ष एन0जी0टी0 के पास रखा है। उन्होंने हमें सी0एन0जी0 बसें चलाने के आदेश दिये थे । एक बार टैस्ट करवाने के लिए 25 लाख रुपये का खर्चा हुआ। वहां पर सारी सी0एन0जी0 वगैरह लेकर गये, टैस्ट ड्राइव करवा दी मगर उसके बाद हमने यह कहा कि हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं हैं कि हम सी0एन0जी0 लेकर आएं, ट्रांसपोर्ट करें फिर वहां बसें चलाएं। हमने यह कहा कि वहां हमें सी0एन0जी0 उपलब्ध करवा दें तो हम सी0एन0जी0 बसें चलाने को तैयार हैं। सी0एन0जी0 जिस दिन उपलब्ध हो जायेगी, ट्रांसपोर्ट महकमा सी0एन0जी0 बेसड बस-सर्विस चालू कर देगा। मगर एक या दो बसें चलने से इनका काम नहीं होगा। अगर वहां चार-पांच या दस बसें भी चलेंगी तो भी उससे पूरा टूरिस्ट ऊपर नहीं जा पायेगा। समस्या फिर वही रहेगी। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सरकार ने अपना पक्ष एन0जी0टी0 के पास पूरी ताकत से रखा है और अब यह एन0जी0टी0 के पाले में गेम है कि वे अपना क्या निर्णय देते हैं। उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही चली हुई है जैसे ही उनके क्लीयर आदेश आयेंगे तो उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी।

अध्यक्ष जारी श्रीमती के0एस0

15.03.2016/1120/केएस/डीसी/1

अध्यक्षः एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्नकाल है और जो आपने अभी विषय उठाया, यह आप समस्या बता रहे हैं। अभी मेरे पास यह विषय नहीं आया है। मैंने सरकार को टिप्पणी के लिए भेजा हुआ है । जब वह मेरे पास आएगा तो मैं देखूंगा कि किस रूल के अंतर्गत चर्चा होगी। धूमल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको किसी और रूल के अंतर्गत रख सकते हैं लेकिन वह विषय तो मेरे पास आना चाहिए। तभी तो मैं उसको देखकर कह सकता हूं कि किस रूल के अंतर्गत यह चर्चा आपको दे दी जाएगी। मेरा मत यह है लेकिन आप अभी बिना नोटिस के, मेरे पास विषय नहीं है, आप चर्चा करना चाहते हैं उसके लिए मैं अलाऊ नहीं करूंगा। इसके लिए जब सरकार से टिप्पणी आ जाएगी, उसके लिए टाईम दिए जाने पर विचार करूंगा।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत अलाऊ करना तो आपके अधिकार क्षेत्र में हैं। जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने भी कहा कि 130 के अंतर्गत चर्चा अलाऊ कर दो । सारी बातें उसके अंतर्गत आ जाएंगी।

अध्यक्षः पहले मैं टिप्पणी तो ले लूं। मेरे पास कोई कागज़ तो आएं, कोई विषय तो आएं। स्पीकर के पास जब तक कोई विषय नहीं होगा वह किसी रूल के अंदर नहीं रख सकता।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, जब सदन के नेता चर्चा के लिए मान रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है?

अध्यक्षः पहले मामला है क्या, वह तो मेरे पास आए। कृपया आप लोग बैठ जाएं। This is not the time for discussion. प्रश्नकाल को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप प्रश्नकाल के बाद बोल लीजिए।

15.03.2016/1120/केएस/डीसी/2

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय सदस्य ने नियम-67 के अंतर्गत आज से पांच दिन पहले नोटिस दिया और आपके सचिवालय में वह नोटिस गया है। प्रॉपरली आपने उसको सरकार को भी भेजा है, बाकी लोगों को भी भेजा है। पांच दिन तक उसको माननीय सदस्य ने नहीं उठाया कि शायद आप खुद अलाऊ करेंगें

लेकिन जब नहीं हुआ तो आज इन्होंने इसको उठाया। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसके कारण हजारों लोग मनाली में प्रभावित हैं तो मेरा सुझाव यह है कि जैसा माननीय विपक्ष के नेता और माननीय सदन के नेता ने भी एग्री किया है कि इस पर हम चर्चा करने को तैयार है तो किसी भी नियम में, नियम 63 के अंतर्गत दो घण्टे की चर्चा होती है उसके अंतर्गत आप अनुमति दे दीजिए कि इस दिन यह चर्चा होगी। आप दिन फिक्स कर दीजिए या अगर नहीं तो मैं उससे भी आगे जाने के लिए तैयार हूं, नियम 62 में कभी भी लग सकता है। नियम 62 के लिए कल के लिए दे दें। उसमें बाकी सदन चर्चा नहीं करेगा। जिसने नोटिस दिया है, वह और मुख्य मंत्री जवाब देंगें तो ठीक है। सारी बात यह है कि क्या एन.जी.टी. में एडवोकेट जनरल ने एफिडेविट दिया है या नहीं दिया है, यह सारी बातें वहां आ जाएगी ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं यह कह रहा हूं कि जो आपने अभी विषय रखा है उसमें अभी तक मेरे पास कोई कागज़ नहीं आए हैं। .....(व्यवधान)..... सुनिए, एक मिनट सुनिए। चर्चा तभी शुरू होती है जब मेरे पास मटिरियल हो और उसी नियम के अंतर्गत मैं आपको अलाऊ कर सकता हूं। चाहे वह नियम 63 है या नियम 130 है लेकिन आप सरकार की टिप्पणी तो आने दीजिए। चर्चा के बारे में तब विचार किया जाएगा। मैं तो कह रहा हूं। हम चर्चा के लिए मना नहीं कर रहे हैं। चर्चा करिए लेकिन मेरे पास कोई मटिरियल तो आए। मैं किस रूल के अंतर्गल उसको अलाऊ करूंगा?

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, सरकार नियम 62 के तहत कल चर्चा के लिए तैयार है। ____(व्यवधान)____

15.03.2016/1120/केएस/डीसी/3

अध्यक्षः ठीक है, अब फैसला हो गया। ____(व्यवधान)____ अब क्या करना है? अब क्या है?

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री सिर्फ सजैस्ट कर सकते हैं लेकिन ये तो यहां पर घोषणा कर रहे हैं। ____(व्यवधान)____

अध्यक्षः अगर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जय राम जी कृपया आप बैठ जाएं।

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सजैशन सुरेश भारद्वाज जी ने दी है। हमने उसको स्वीकार किया है और अध्यक्ष जी को रूलिंग देनी है। जय राम जी,आप बाल की खाल खींच रहे हैं। सुरेश भारद्वाज जी ने सजैशन दी कि नियम 62 के अंतर्गत चर्चा करें और हमने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं, अध्यक्ष महोदय रूलिंग देंगें। ____(व्यवधान)____ अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल का समय है और 25 मिनट हो चुके हैं, सरकार अपना पक्ष दे चुकी है।

अध्यक्षः जय राम जी, आप बैठिए। Kindly finish the matter please. जब सरकार ने मान लिया है ।। allow to take up this matter tomorrow. जब गवर्नमैंट ने मान लिया है तो उसके बाद कोई ऑर्गुमैंट्स नहीं होना चाहिए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

15.3.2016/1125/av/dc/1

अध्यक्ष : जारी

The Government has agreed for discussion. पहले आप कह रहे थे कि सरकार चर्चा नहीं कर रही है, अब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप फिर से शोर करने लगे। (---व्यवधान---) No arguments please, चर्चा कल रखी जायेगी। सरकार ने मान लिया है इसलिए चर्चा कल रखी जायेगी। (---व्यवधान---) आप बैठ जाइए।

15.3.2016/1125/av/dc/2

प्रश्न काल आरम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या : 2884

श्री पवन काजल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के 'क' भाग के उत्तर में बताया है कि कांगड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विकास खण्ड, कांगड़ा में कुल 36 पंचायतें आती हैं। मैंने प्रश्न के 'ख' में पूछा था कि क्या कांगड़ा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो विकास खंड, रैत में आती है। इसी तरह प्रश्न के 'ग' भाग में पूछा था कि ये पंचायतें जैसे दुधियारी, बेदी, भडियारा, सनोरा, भेड़ी, मेहरना विकास खंड, रैत में आती है और गग्गल पंचायत विकास खंड, धर्मशाला में आती है। कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र में 42 पंचायतें हैं और ब्लॉक में 36 हैं। जो रैत ब्लॉक में 5-6 पंचायतें आती हैं क्या ये भविष्य में कांगड़ा ब्लॉक में आ सकती है? जो गग्गल पंचायत विकास खंड, धर्मशाला में आती है क्या इसको आने वाले समय में एक ही विकास खंड, कांगड़ा में कर सकते हैं ताकि कांगड़ा विकास खंड में जो 42 पंचायतें हैं वे एक ही विकास खंड के अंतर्गत रहें?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य जानना चाहते हैं यह प्रक्रिया वास्तव में पंचायत चुनाव से पहले होती है। अभी हाल ही में हुए पंचायत चुनाव से पहले भी हमने इस प्रकार की प्रक्रिया की थी तथा जहां-जहां से इस तरह के सुझाव आए थे हमने उस पर पूरी कार्रवाई की थी। अब अगले पंचायत चुनाव वर्ष 2020 में होंगे तथा उस चुनाव से पहले इस बारे में कार्रवाई की जा सकती है। (---व्यवधान---) पंचायत के चुनाव पांच साल के बाद करवाये जाते हैं। जब पांच साल के बाद पंचायत चुनाव होंगे तो उस समय ही इस पर विचार किया जा सकता है।

15.3.2016/1125/av/dc/3

श्री पवन काजल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने इस बारे में आपको पंचायत चुनाव से दो महीने पहले प्रार्थना पत्र दिया था। मैंने उसमें कहा था कि ये जो कुछ पंचायतें रैत में चली गई हैं उनको विकास खंड, कांगड़ा के अंतर्गत रखा जाए और

जो नगरोटा-बगवां की चली गई हैं उनको नगरोटा-बगवां में जोड़ दिया जाए। मेरा मूल प्रश्न यह है कि अगले पंचायत चुनाव से पहले क्या ये पंचायतें कांगड़ा विकास खंड में आयेगी?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव से पहले भी जहां-जहां ब्लॉक्स से सुझाव आए थे हम उनको केबिनैट में ले गये थे। अब अगले चुनाव से पहले इसको दोबारा ऐग्जामिन करने की बात नहीं हो सकती। हमने चुनाव से पहले 57 पंचायतों को इधर से उधर शिफ्ट किया था और उस वक्त हमारे लगभग 20 ब्लॉक्स प्रभावित हुए थे। जहां पर किसी प्रकार का गतिरोध पैदा हो गया है तो उसको अब हम दूर नहीं कर सकते।

15.3.2016/1125/av/dc/4

<u>प्रश्न संख्या : 2885</u>

श्री सरवीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहती हू कि दी गई सूचना में रेहलू से बौड़ू सरना सड़क के बारे में कोई डेट नहीं दी गई है कि सैकिंड फेज़ का कब भेजा गया। इसके अतिरिक्त, ठम्बा-मनोह तथा ललेटा महादेव सड़क पिछली सरकार के समय की विधायक प्राथमिकता की सड़क है। आपने दिनांक 6.8.2015 को विभाग को एफ.सी.ए. केस बनाकर भेजा है।

टी सी द्वारा जारी

15.03.2016/1130/TCV/AG/1

प्रश्न संख्या: 2885- क्रमागत

श्रीमती सरवीण चौधरी----- जारी।

मैं यह जानना चाह रही थी कि यह केस हिमाचल प्रदेश वन विभाग के पास है या प्रक्रिया पूरी होकर आगे फॉरेस्ट की क्लीयरेंस के लिए केन्द्र सरकार तक पहुंच गया है। दूसरा, आपने इन दोनों सड़कों में मैंशन किया है कि थम्बामनो में डी.पी.आर. मु0 448.32 लाख

रूपये की है और ललेटा-महादेव की डी.पी.आर. 286.68 की आपने भेजी है। लेकिन आपने इसमें कहा है कि वन स्वीकृति आने के बाद इसका कार्य शुरू हो जाएगा। अभी वन स्वीकृति भी नहीं हुई और पैसा भी सैंक्शन नहीं हुआ है। इस तरह से पिछली सरकार का आश्वासन आप आज दे रहे हैं। ये फॉरेस्ट क्लीयरेंस का केस कहां है और इतनी ढ़ीली चाल से आपका लोक निर्माण विभाग और वन विभाग क्यों चल रहा है? क्या यह डिले टैक्टिस है, टाईम पास करने की। आपने इसको अभी दिनांक 6.8.2015 को भेजा है, तो इन सड़कों के लिए कब पैसे आएंगे और कब काम शुरू होगा? जबकि यह पिछली सरकार की एम.एल.ए. प्रायोरिटी है।

मुख्य मंत्रीः इस प्रश्न का उत्तर बहुत लम्बा-चौड़ा है। अगर आप डिटेल्ज़ में जाना चाहती है कि वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है और पीछे क्या-क्या काम हुए हैं, तो इसका सारा जवाब आपके सामने हैं। आपने कोई स्पेसिफिक क्वैश्चन मेरे से नहीं पूछा है। इसके जवाब में दिया हुआ है कि ये सड़कें कब शुरू हुई, इसमें कौन-सी रूकावटें आई, कब उनका फॉरेस्ट क्लीयरेंस हुआ और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? इसके बारे में सम्पूर्ण सूचना आपको बड़े विस्तार से मैं दे चुका हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो आपका कंसर्न है, कि जल्दी से जल्दी ये काम हो, तीव्रता के साथ ये काम किया जाये। इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं कि we will take speedy action in this matter. इस पर अभी काम हो रहा है। इसमें जो फॉरेस्ट क्लीयरेंस बगैरह आनी थी, वह आ चुकी है। अब इस पर अमल हो रहा है।

15.03.2016/1130/TCV/AG/2

प्रश्न संख्याः 2886

श्री बी0के0 चौहानः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभापटल पर रखी गई है, उससे जाहिर है कि 2004 में इस बस स्टैंड का निर्माण करने के लिए स्थल का चयन किया गया था। यहां पर काम शुरू भी हुआ। लेकिन उसको दूसरी बार बन्द करके 2010 में जहां अभी बस स्टैंड का काम शुरू हुआ है, उसका चयन किया गया और शिलान्यास किया गया। अब यह बस अड्डा तीसरे जगह पर बनाया जा रहा है और काम फिर भी धीमी गति से हैं। ये आश्वासन

देते हैं कि 2017 में इसका काम पूरा कर लिया जाएगा क्योंकि 2016 में काम शुरू कर रहे हैं और 2017 में लगभग एक साल में काम कम्पलीट करने का ये आश्वासन दे रहे हैं, जिससे मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि ये कार्य मेरे अनुसार वर्कएबल नहीं होगा। इसके साथ-साथ एक प्रश्न इनसे पूछना चाहता हूं कि जो बस अड्डे का कार्य पहले 2010 में शुरू हुआ था, उसमें एक शॉपिंग कंप्लैक्स का भी प्रावधान था। वह इसलिए था कि जो स्थल है, उसके आस-पास पहले एच.आर.टी.सी. की वर्कशॉप्स थी। उनको हटाया गया और वह परिसर खाली करवाया गया। उनको हटाने के एवज़ में उनको दुकानें उपलब्ध करवाने का प्रावधान था। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या यह वही पहले वाला नक्शा है, जिसमें शॉपिंग कंप्लैक्स का भी प्रावधान था या

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी ।

15.03.2016/1135/RKS/AG/1

प्रश्न संख्याः 2886...क्रमागत

श्री बी0 के0 चौहान द्वारा... जारी

या कोई नया नक्शा बनाकर अब छोटा-मोटा बस स्टैंड का स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात यह कह रहे हैं जब वर्ष 2004 में माननीय श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्य मंत्री थे और ट्रांसपोर्ट महकमा मेरे पास था। हमने बी.ओ.टी. के तहत बस अड्डे का निर्माण किया था। उसके बाद वर्ष 2010 में, जब आपकी सरकार वर्ष 2008 के शुरू में आ गई थी तो तकरीबन पौने 3 साल के बाद उसका स्थान बदला गया। अभी आते ही हमने वर्तमान स्थान में फाऊंडेशन स्टोन रखा था। उस वक्त माननीय धूमल जी मुख्य मंत्री थे और श्री महेन्द्र सिंह जी मंत्री थे। जहां फाऊंडेशन स्टोन रखा था, हम वहीं इसे बना रहे हैं। बी.ओ.टी. के ऊपर हम दो बार टैण्डर करवा चुके हैं। जो हमने इस बस स्टैंड को बड़ा बनाने का प्रयास किया था, उसमें कोई भी

पार्टी नहीं आई। मैंने कल भी कहा था कि यह बस स्टैंड छोटा-मोटा नहीं होगा। यह बस अड्डा10 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। यह एक प्रोपर बस अड्डा बनेगा, जिसमें तकरीबन 20-25 गाड़ियां स्टेशन रहेगी और सारी आधुनिक सुविधाओं से इस बस अड्डे को सुसज्जित किया जाएगा।

अध्यक्षः श्री हंस राज

श्री हंस राजः माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो विस्तृत उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है। हमारी क्वायरी इतनी है कि जब चम्बा में हम सभी लोग जाते हैं, जिसमें पांचों विधायक आते हैं, चाहे जिस भी दल विशेष से हों। हर बार चम्बा की जनता यही प्रश्न पूछती है कि बाकि जिलों में एक भव्य बस अड्डे का निर्माण हो चुका है, लेकिन हमें

15.03.2016/1135/RKS/AG/2

यह सुविधा कब तक मिलेगी? आज मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि वहां पर बसों को शिफ्ट करने की बात कही गई है। क्या मंत्री जी आश्वसत करेंगे कि जब तक बस अड्डे को पूर्ण तरीके से तैयारा नहीं किया जाता, जो टारिंग, सोलिंग इत्यादि का काम वहां पर चल रहा है तब तक इसमें बसिज शिफ्ट न की जाए। दूसरी बात यह है कि जो एच.आर.टी.सी. की वर्कशॉप बनी हुई है और अगर यह बनी हुई है तो उस वर्कशॉप को वहां शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष जी, यह सब लोग जानते हैं कि एच.आर.टी.सी. मुश्किल दौर से गुजर रही है। जो डैड माइलेज पड़ती है उसको हम एवॉयड करते हैं। अगर वर्कशॉप 5 किलोमीटर दूर होगी, तो पहले बस 5 किलोमीटर जाएगी फिर 5 किलोमीटर वापिस आएगी। डीजल जोकि 40 रुपए लीटर है अगर एक-एक बस 200 रुपए का डीजल खाने लगेगी, तो जो बसें चलती हैं वह भी बंद हो जाएगी। यह डे- टू -डे मनेजमैंट है। अगर बस पास में खड़ी है और वहीं से चलनी है तो उससे हमारा डीजल बचता है। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष जी यह है कि इस बस अड्डे के

लिए अभी साढ़े 3 करोड़ रुपया हमने एन.एच.पी.सी. से हिमुडा में जमा करवाया था। अब हिमुडा उस पैसे के ऊपर बैठ गई है कि हमने ये पैसा कहीं और समायोजित कर लिया। ये सारे विषय एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। इनका समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बस अड्डे के लिए हम पैसे की कमी नहीं आने देंगे और जो मानीनय चौहान साहिब ने कहा I will ensure it personally कि 2 वर्ष के अंदर वर्ष 2017 के अंत से भी पहले इस बस अड्डे का उद्घाटन करेंगे और बढ़िया भव्य बस अड्डा बनाकर आपको दे दिया जाएगा।

15.03.2016/1135/RKS/AG/3

अध्यक्षः श्री हंस राज जी।

श्री हंस राजः माननीय मंत्री जी हिमुडा का डिस्प्यूट हमारे जहन में आया था। मूलतः इस प्रश्न को उठाने का हमारा मकसद यही था कि पैस की कमी नहीं आने देंगे। यह तो आपने स्पष्ट कर दिया।

श्री एस.एल.एस द्वारा जारी

15.03.2016/1140/SLS-AS-1

प्रश्न संख्या : 2886 ...जारी

श्री हंस राज ...जारी

आपने कहा कि अगर हम वर्कशॉप को शिफ्ट करते हैं तो वहां बसों के आने-जाने का ख़र्चा आएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हमने वहां गाड़ियों को शिफ्ट ही नहीं करना था तो फिर वह वर्कशॉप बनाई ही क्यों? अगर वहां से बसिज को शिफ्ट नहीं करेंगे तो वह भी फिर पुराने बस अड्डे की तरह एक छोटा-सा ही बस अड्डा होगा। हमारी सबसे बड़ी चिंता यही है। माननीय मंत्री जी से हमारा मूल प्रश्न यही है कि जो बात इन्होंने कही है, वह उस पर कायम रहें। चम्बा के लोगों के हित तथा आगामी 10-15 सालों की ज़रूरतों को ध्यान में

रखते हुए उस वर्कशॉप को शिफ्ट करना उचित है। वहां पर जो जेल परिसर खाली करवाया गया था वहां इतनी सफिशिएंट जगह नहीं है, वहां केवल 29-30 बसें ही खड़ी हो पाएंगी।

खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर वही कह रहा हूं कि जिन बसों को रिपेयर की ज़रूरत होगी, केवल वही वर्कशॉप में जाएंगी। जो अव्यॉयड हो सकती है उन्हें अव्यॉड करेंगे। आर.एम. इस पर डे-टू-डे वर्क करता है। उसको पता होता है कि जिस बस को वर्कशॉप भेजने की आवश्यकता नहीं है उसे नहीं भेजा जाए। जिन बसों को चैक होने के लिए जाना होता है, उनको जाना ही है; उनको चैकिंग के लिए भेजते ही हैं। जो वर्कशॉप बनी है उसका पूरी तरह से युटिलाईजेशन होगा। वहां रिपेयर होगी, मेंटेनैंस होगी, पेंटिंग होगी और जहां बड़ी रिपेयर की ज़रूरत होगी उसके लिए भी बसें वहां जाएंगी। अनावश्यक रूप से वहां बसों को नहीं भेजा जाएगा कि बस कहीं से आई और सीधे वर्कशॉप चली जाए। चैक करने के लिए और धुलाई के लिए तो बसें जाती ही हैं। मैंने कहा कि वहां 25-30 बसें खड़ी होंगी। वहां पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग वेटिंग हॉल होगा तथा रहने के लिए अलग और खाने के लिए अलग प्रबंध होगा। अगर आप कुछ और भी कहेंगे तो वह भी प्रबंध किया जाएगा।

15.03.2016/1140/SLS-AS-2

प्रश्न संख्या : 2887

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सूचना भाग 'क' के उत्तर में दी है, उसके अनुसार सचमुच पिछले 3 वर्षों से बड़ी अलार्मिंग स्थिति है। इसमें चोरी के 4038, हत्याओं के 342, बलात्कार के 779, अपहरण के 978, आत्महत्या के 394 और छुआछूत के 261 मामले बताए गए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें बहुत सारे केसिज शामिल हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं, और अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सुझाव भी होगा। यह प्रश्न सारा इकट्ठा कर दिया है लेकिन मैं केवल अपने जोगिन्द्रनगर थाना क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि वहां बहुत सारे चोरी, हत्या के

और दूसरे मामले रजिस्टर तो होते हैं लेकिन थानों में स्टॉफ पूरा न होने के कारण और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव तथा लॉ एंड ऑर्डर के ज्यादा कार्य होने के कारण इन मामलों में इनवैस्टिगेशन नहीं हो पाती है। जब भी कोई चोरी, ब्लातकार इत्यादि का केस रजिस्टर्ड होता है , वह कई दिनों तक इनवैस्टिगेशन में ही रहता है। कई बार अनट्रेस्ड हो जाता है जबकि कई बार इनवैस्टिगेशन चलती रहती है और वह सालों तक चलती रहती है। कोर्ट तक केस का चालान ही पुट अप नहीं हो पाता। जब चालान समय पर पुट अप नहीं होता तो सजाएं भी कम केसिज में ही हो पाती हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवदेन है कि क्रिमिनल केसिज की इनवैस्टिगेशन के लिए हर थाने में अलग से एजैंसी या सैल गठित करें ताकि जो केसिज किसी भी धारा के तहत रजिस्टर हों, वहां उनकी इनवैस्टिगेशन के लिए अलग से सैल हो ताकि वह उसी काम को निपटाएं; समय पर चालान बनें और समय पर कोर्ट में जाए ताकि जो अपराधी लोग हैं उनको सजा मिले। क्या आप इस प्रकार से हर थाने में अलग सैल का गठन करेंगे ताकि अपराध की रोकथाम हो सके?

मुख्य मंत्री ...श्री गर्ग जी के पास

15/03/2016/1145/RG/AS/1

प्रश्न सं. 2887---क्रमागत

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तीन वर्ष के आंकड़े मांगे हैं और अगर आप इस सूचना को गौर से देखेंगे, तो यह बहुत voluminous record आपके सामने उत्तर में दिया है। आप इस बात को पाएंगे कि अपराधों की संख्या में कमी हुई है, बढ़ौत्तरी नहीं हुई है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो भी केसिज़ दर्ज हुए हैं पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ, उनकी इनवेस्टीगेशन की है और जो दोषी पाए गए हैं, उनके चालान अदालतों में पेश किए हैं। कइयों में सज़ा हुई है और कई मुक़दमें अभी under consideration of the courts हैं। इसके पूरे आंकड़े यहां दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह बात है कि पुलिस एक तो मुक़दमा दर्ज करे और किसी की पकड़-धकड़ करे और इनवेस्टीगेशन करने के लिए अलग से एजेन्सी हो, तो अभी यह

प्रक्रिया हमारे प्रदेश में नहीं है। **<u>लेकिन माननीय सदस्य का यह सुझाव है, तो इस पर विचार किया जाएगा।</u>**

श्री बलदेव सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदय, जवाब में दर्शाया गया है कि पूरे जिला सिरमौर में मात्र चार मामले अवैध खनन के पाए गए और पूरे प्रदेश में मात्र 23 मामले पाए गए। जबकि पिछले बीस दिनों से जब से यह सत्र चला है, तो अकेले जिला सिरमौर में ही लगभग 15,00,000/-रुपये का फाईन पुलिस और खनन विभाग ने अवैध खनन करने वालों के ऊपर किया है। पूरे उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा चूने पत्थर का कारोबार मेरे विधान सभा क्षेत्र में होता है। लेकिन पिछले तीन वर्षों से लगभग सारी खानें बंद पड़ी हैं, मात्र 6 खानें चल रही हैं जो अभी पिछले दिनों माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था और 6 खानें चलने के बावजूद जो बाकी खानें बंद हैं, उन सबमें अवैध खनन हो रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह अवैध खनन हो रहा है क्या इसमें बड़े लोगों के चालान भी हो रहे हैं? इसमें मात्र छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है जोकि अपना रेत, बजरी इत्यादि का छोटा कारोबार कर रहे हैं और बड़े लोग इसमें बच रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि बड़े लोगों के ऊपर क्या कोई कार्रवाई होगी? इसके अतिरिक्त जो खानें बंद पड़ी हैं जिससे कि सारा रोजगार वहां बंद है जबकि ई.आई.ए. के लिए केन्द्र सरकार ने अब प्रदेश सरकार को आदेश दे दिए हैं और यहां भी लोगों को अप्लाई किए हुए

15/03/2016/1145/RG/AS/2

कई-कई महीने हो गए। लेकिन अभी तक उनको ई.आई.ए. नहीं हुआ है। तो क्या ये खानें जल्दी खुलेंगी जिससे कि अवैध खनन रुके?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक अवैध खनन का प्रश्न है इस शीर्षक के अन्तर्गत तीन वर्षों में वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक 23 मामले अवैध खनन के पंजीकृत हुए हैं और जबकि इसकी समरूप अवधि में वर्ष 2010 से वर्ष 2012 तक 51 अभियोग पंजीकृत हुए थे, जो विचाराधीन अवधि में 28 अभियोग कम पंजीकृत हुए हैं। कुल पंजीकृत अभियोगों में से 28 अभियोगों में अपराध साबित न होने पर cancellation Report तैयार की गई जो 7.7% बनती है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से माननीय सदस्य ने जो सिरमौर जिले का जिक्र किया है,

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

15/03/2016/1150/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः 2887 क्रमागत---- मुख्य मंत्री जारी----

इस जिले में भी जो अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, उनको वहां पर सरकार ने इविक्शन के नोटिस दिए हैं । आमतौर पर वहां काफी पहले बड़े पैमाने पर खनन होता था लेकिन अब उतना नहीं होता है। जिन लोगों के पास खनन के वेलिड परमिट्स हैं उनको खनन करने की अनुमति है लेकिन जिनके पास वेलिड परमिट्स नहीं हैं, उनको वहां से हटाया जाएगा।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसकी केवल एक बात को, जिसको तोमर जी ने उठाया है, के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, वास्तव में अवैध खनन के मामले बहुत हैं जिनमें से कुछ मामले यहां बताए गए हैं। हमारा यह कहना है कि सिरमौर में जो खनिज सम्पदा है उसका दोहन सरकार करे ताकि ऑथोराइज माइनिंग शुरू हो और अन-ऑथोराइज माइनिंग न हो, यह जरूरी है। हम कितने भी चालान कर लें परन्तु वह मटीरियल तो निकल ही रहा है। वहां प्रभावशाली लोग दनादन मटीरियल निकाल रहे हैं। चूना पत्थर भी निकल रहा है और नदियों का मटीरियल भी निकल रहा है। हम यह बताना चाहते हैं कि सिरमौर की जो खदाने हैं वे वर्षों से बन्द पड़ी हैं जबकि बाकी प्रदेश में चूना पत्थर निकालने और सीमेंट बनाने का काम चल रहा है परन्तु सिरमौर अकेला ऐसा जिला है जहां के खनिज का दोहन नहीं हो रहा है और उसके कारण यह अवैध खनन हो रहा है। उसकी दृष्टि से आप कदम उठाएंगे, हमारा इतना प्रश्न है?

मुख्य मंत्रीः माननीय सदस्य का अच्छा सुझाव है और सरकार स्वयं भी इस दिशा में सोच रही है तथा जल्दी ही कदम उठाएगी ताकि अवैध खनन को सख्ती से बन्द किया जा सके। वहां जो खनन की प्रक्रिया है उसको जारी रखने के लिए उसको ऑक्शन किया जाएगा

ताकि उसका राज्य को भी लाभ हो और यह खनन संयोजित तरीके से चले। इसमें हमारा विभाग उचित तरीके से कदम उठा रहा है।

15/03/2016/1150/MS/DC/2

यह भी कहना गलत है कि अब बड़े पैमाने के ऊपर सिरमौर में अवैध खनन हो रहा है। पहले वहां बहुत अवैध खनन होता था और जिसका जहां दिल चाहता था वहां से खनन करता था लेकिन आज उसके ऊपर बहुत हद तक प्रतिबन्ध लग गया है। मैं यह भी मानता हूं कि जो हमारा खनिज पदार्थ है उसका दोहन नियमित रूप से कानूनी तरीके से होना चाहिए ताकि उससे राज्य को भी लाभ हो और समाज में भी वह सामग्री प्राप्त हो।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि प्राचीन मूर्तियों और पुरातत्व विभाग की दृष्टि से जो अमूल्य वस्तुएं हैं, उसमें इस प्रकार के आठ मामले दर्ज़ हुए हैं। एक मामले में नेपाली मूल का व्यक्ति संलिप्त पाया गया है और दूसरे मामले में कनाडा का व्यक्ति है। इसके अलावा "ग" भाग के उत्तर में यह सूचना दी गई है कि एक मामले में चोरी बरामद हो गई है और जो व्यक्ति इसमें संलिप्त है, उसकी अनेकों केसिज में जांच पूरी करने के लिए पुलिस के सामने लाने की आवश्यकता है। वह अभी तक कार्रवाई चल रही है। मैं सबसे पहले मुख्य मंत्री जी को और विभाग को बधाई देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इसमें व्यक्तिगत रूचि ली गई और विभाग ने जिस कर्मठता से काम किया, उसके कारण जिन मूर्तियों का मिलना असम्भव था वह सम्भव हो गया।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

15.03.2016/1155/जेएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 2887:--------**जारी**-------

श्री महेश्वर सिंहः-------**जारी**------

परन्तु अभी भी इस अभियुक्त की आवश्यकता है। ग-भाग के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि जो एक्स्ट्राडिशन का ड्राफ्ट है वह हिमाचल सरकार के आग्रह पर होम मिनिस्टरी ने तैयार कर दिया है और उस ड्राफ्ट पर केवल हस्ताक्षर होने हैं। दूसरे, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यह भी आग्रह किया है कि प्रदेश ऐसे मामलों को जो उनका लिगल सैल है, आतंरिक सुरक्षा का उससे मामला उठाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि इस ओर अभी तक क्या कार्रवाई हुई और कब तक इसको अन्तिम रूप दिया जाएगा ताकि जो छानबीन चल रही है वह कम्पलीट हो सके?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि भारत और नेपाल के बीच में जो अपराधी हैं उनको एक मुल्क से दुसरे मुल्क को ले जाने की कोई ट्रीटी नहीं है। भारत का जो गृह मंत्रालय है अब इसके ऊपर सोच रहा है, गम्भीरता से सोच रहा है। हम भी इस बारे में गृह मंत्रालय के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो आंकड़ें दिए गए हैं पहला चोरी व गृह भेदन का है। इसमें 4,038 मामले कुल रजिस्टर्ड हुए लेकिन इसमें बहुत बड़ी संख्या 2, 320 लगभग 55 प्रतिशत से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो अनट्रेस्ड हैं। क्या विभाग इनकी ओर ज्यादा महत्व दे करके इन मामलों को ट्रेस करने की कोशिश करेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा चोरी और गृह भेदन के ही मामले हैं और सजा भी केवल 81 मामलों में हुई है?

दूसरे, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि सिरमौर में जो खनन हो रहा है उसमें पिछली सरकार के समय 51 मामले दर्ज़ हुए थे अब 23 ही मामले दर्ज़ हुए हैं, यानि कमी आई है। यह कमी कहीं मिलीभगत के कारण तो नहीं आई है? जो लोग

माइनिंग कर रहे हैं और माइनिंग हो भी रही है, इस बारे में आप भी जानते हैं। इसके लिए अच्छा है कि आपने आश्वासन दे दिया कि इसमें सरकार नीति बना करके सरकार के माध्यम से करवाएगी लेकिन पहला जो चोरी व गृह भेदन का मामला है इसमें क्या आप विभाग को आदेश देंगे कि इसमें शीघ्र अधिक से अधिक मामले ट्रेस किए जाएं?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक खनन का प्रश्न है,जैसे कि मैं कह चुका हूं कि किसी ज़माने में बड़े पैमाने पर सिरमौर के अन्दर अवैध खनन होता था। आज वह काफी कम हो गया है। ऐसा नहीं कि खनन नहीं हो रहा है मगर पहले की मात्रा में अब बहुत कम है। सरकार, पुलिस और जो हमारा उद्योग विभाग है वह भी उसके ऊपर कड़ी नज़र रखता है। हम चाहते हैं कि जहां खनन हो रहा है वह भी राज्य की सम्पत्ति है उसका दोहन किया जाए। कानूनी तरीके से दोहन किया जाए ताकि राज्य को भी लाभ हो और जो इसका दोहन करेगा उसको भी लाभ हो। इस खनन से जो प्राप्त होने वाला मटीरियल है उसका इस्तेमाल करने की काफी गुंजाइश है और लोग उसे खरीदते हैं। आखिर जो खनन करते हैं उसको भी कहीं पर बेचते हैं और उस मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से उसका भी व्यापार बढ़े।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मुख्य मंत्री महोदय, चोरी और गृह भेदन के जो मामले हैं वे 4,038 रजिस्टर्ड हुए लेकिन 2320 मामले यानि 55 प्रतिशत से ज्यादा अनट्रेस्ड हैं, क्या इसमें सक्रियता लाई जाएगी ताकि ये मामलें ट्रेस हों और चोर पकड़े जाएं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

15.03.2016/1200/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 2887 क्रमागत

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, पूरी कोशिश की जाती है कि चोर पकड़े जाएं। जैसे पुलिस ज्यादा होशियार होती जा रही है वैसे ही जुर्म करने वाले भी एक कदम आगे रहते हैं। फिर भी उन्हें पकड़ने की कोशिश की जायेगी। मैं कह सकता हूं कि अगर आप अपराध के सारे आंकड़ें पढ़ेंगे तो पायेंगे कि इन तीन वर्षों में पहले के मुकाबले अपराध बहुत कम हुए हैं और जो अपराध हुए हैं उनमें से काफी मात्रा में लोग पकड़े गये हैं।

प्रश्नकाल समाप्त

15.03.2016/1200/SS-AG/2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब कागज़ात सभापटल पर रखे जायेंगे। अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, अनुभाग अधिकारी, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)बी(2)-4/99 दिनांक 23.02.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.02.2016 को प्रकाशित;

ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षण एवं विदेशी समनुदेशन विभाग, सहायक आचार्य (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-।(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः का0(प्रशि0)बी(1)-1/2006-II दिनांक 08.02.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.02.2016 को प्रकाशित; और

iii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, अनुदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःका0(प्रशि0)बी(1)-1/2006-III दिनांक 17.11.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 24.11.2015 को प्रकाशित ।

15.03.2016/1200/SS-AG/3

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

उद्योग मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, सहायक खनन निरीक्षक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-II(बी)2-5/2010 दिनांक 13.12.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.01.2014 को प्रकाशित;

ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, खनन निरीक्षक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-II(बी)2-6/2006 दिनांक 09.06.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.09.2015 को प्रकाशित;

iii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी सहायक(भू-विज्ञान), वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-II(बी)2-2/2014 दिनांक 26.08.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.09.2015 को प्रकाशित; और

iv. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सर्वेक्षक, वर्ग-III(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-II(बी)2-3/2014 दिनांक

25.08.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.09.2015 को प्रकाशित ।

15.03.2016/1200/SS-AG/4

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। अब श्री खूब राम जी, सदस्य, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री खूब रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति (वर्ष 2015-16) का 132वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 115वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं।

अध्यक्षः अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर भी रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2015-16) का 54वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्या 4) के पैरा संख्या:4.7 की संवीक्षा पर आधारित है तथा हिमाचल प्रदेश राज्य उद्योग विकास निगम सीमित से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर भी रखती हूं।

अध्यक्षः अब श्री महेश्वर सिंह, सभापति, मानव विकास समिति, मानव विकास समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

15.03.2016/1200/SS-AG/5

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति (वर्ष 2015-16) के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूंः-

i. समिति का **16वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 14वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **युवा सेवायें एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का **17वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **तकनीकी शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है ।

15.03.2016/1200/SS-AG/6

<u>नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा</u>

अध्यक्षः अब नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा होगी। श्री किशोरी लाल, दिनांक 9 मार्च, 2016 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 2790 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे ।

श्री किशोरी लालः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय पंचायती राज मंत्री जी का ध्यान बैजनाथ विकास खण्ड अधिकारी के विरूद्ध जो समाचार-पत्रों के माध्यम से धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे की ओर दिलाना चाहता हूं। विभाग ने उस संबंध में अपने अधिकारियों से इंक्वायरी करवाई तथा उस इंक्वायरी में एक साल बीत गया। लेकिन उस अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।

अध्यक्ष महोदय, उस अधिकारी ने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करके कनिष्ठ लेखापाल मनरेगा के चयन के लिए एक कमेटी का गठन किया। उसमें जो पंचायत समिति का चेयरमैन था, वह उस कमेटी के चेयरमैन थे तथा वाइस-चेयरमैन व बी0डी0ओ0 उसमें मैम्बर थे। लेकिन चेयरमैन साहब ने उस एप्वाइंटमैंट को करने के लिए मना किया क्योंकि वर्ष 2011 में उस साक्षात्कार के लिए 528 व्यक्ति एपीयर हुए और इस बार जब उसने एप्वाइंटमैंट की तो केवल 9 व्यक्ति एपीयर हुए तथा अपनी मन-चहेती लड़की को उस पोस्ट पर रख लिया जोकि सरासर नियमों के खिलाफ है। यही नहीं, जिला परिषद् कांगड़ा से उस अधिकारी को ग्राम पंचायतों के लिए 23,72,928/- रुपये की राशि विकास खंड बैजनाथ को 51 पंचायतों के लिए प्रति पंचायतवार 44,528/- रुपये की दर से खेलों का सामान खरीदने के लिए पंचायत को वितरित करने के लिए जारी की गई। लेकिन विकास खंड अधिकारी ने ग्राम पंचायतों को राशि न देकर स्वयं खेलों का सामान खरीदा। न तो वहां कोटेशनें ली गईं और न ही परचेज़ कमेटी बनाई गई।

जारी श्रीमती के0एस0

15.03.2016/1205/केएस/एजी/1

श्री किशोरी लाल जारी----

अध्यक्ष महोदय, सरकार इन आदेशों के अंतर्गत 13वें वित्तायोग की जारी की गई राशि में से पंचायत समिति कुल आवंटन राशि का सोलर लाईट के ऊपर केवल 10 प्रतिशत खर्च कर सकती थी लेकिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति बैजनाथ ने 100 प्रतिशत लाइटें खरीद ली जिनकी संख्या 201 है। यही नहीं विकास खण्ड अधिकारी की जीप नं0- एच.पी.53-2424 है, उसका सोलन में मुरम्मत का बिल नं0- 2327 दिनांकः 13.09.2014 , राशि मु0 27,533/- का भुगतान गाड़ी के चालक द्वारा किया गया । गाड़ी की मुरम्मत सोलन में हुई और आर.टी.आई. के माध्यम से दर्शाया गया है कि गाड़ी का गीयर खराब था तो गाड़ी सोलन कैसे पहुंची यह एक बड़ा प्रश्न है? यही नहीं, सोलन में एक ही फर्म है जिसका नाम डी.डी. ऑटोराइज़ है और वे फैब्रिकेशन करते हैं, गाड़ियों की डैंटिंग-पेंटिंग करते हैं लेकिन गाड़ी का सामान वहीं से खरीदा गया और बी.डी.ओ. बैजनाथ ने मिस्त्रियों

के किट भी इसी फर्म से खरीदे जिसके बिल वाउचर्ज़ मेरे पास मौजूद है। यही नहीं उस अधिकारी ने डी.डी. ऑटोराईज़ जो सोलन के कंडाघाट में है, वहां से सारा सामान जैसे करंडी, हथौड़े और दूसरा सामान भी एक ही फर्म से खरीदा। यही नहीं उस अधिकारी ने जीप की मुरम्मत के लिए वर्ष 2015 में मु0 21,741/- रु0 का खर्चा दर्शाया है। वर्ष 2014-15 में मु0 12,080/- रु0 का खर्चा दर्शाया है। वर्ष 2014-15 में उस जीप की रीपेयर पर 85 हजार के करीब खर्चा दिखाया है। आर.टी.आई. के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए बिल वाऊचर मेरे पास हैं। यह गाड़ी हर वर्ष रीपेयर होती है और सोलन में और शिमला या चण्डीगढ़ से सामान खरीदा जाता है। उस अधिकारी के खिलाफ पुख्ता सबूत है और मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इतने भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ़ आज तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आदरणीय मंत्री महोदय, मैं यह दस्तावेज आदरणीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपको सौंप रहा हूं। कृपया उस अधिकारी को निलम्बित करिए या उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाएं क्योंकि यह मामला बड़ा संगीन है, वह अधिकारी लाखों रुपये खा गया है तो मैं ये कागज़ अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय को सौंपना चाहूंगा और

15.03.2016/1205/केएस/एजी/2

आश्वासन भी चाहूंगा कि उस अधिकारी के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जा रही है? अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री चर्चा का उत्तर देंगें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध सोलर लाईट, खेल सामान तथा फर्निचर खरीद के सन्दर्भ में माननीय विधायक श्री किशोरी लाल द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर निम्न प्रकार से हैंः-

खेल सामान खरीद में उपायुक्त, जिला कांगड़ा द्वारा जिला युवा एवं खेल अधिकारी कांगड़ा की गठित कमेटी की जांच में यह पाया गया है कि बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए खेल सामग्री क्रय कर ली गई जो कि व्यय राशि के हिसाब से घटिया स्तर की थी। इसके अतिरिक्त खेल सामग्री को क्रय करते समय जिला परिषद के सदस्यों को भी विश्वास में

नहीं लिया गया। खण्ड विकास अधिकारी बैजनाथ जिला कांगड़ा द्वारा फर्निचर का क्रय स्थानीय बाजार से ही किया गया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

15.3.2016/1210/av/as/1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री------- जारी

स्थानीय बाजार से ही किया गया है। उपायुक्त, कांगड़ा की जांच रिपोर्ट के अनुसार खंड विकास अधिकारी ने सोलर लाईट क्रय करने हेतु समस्त विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की है तथा इसके अतिरिक्त विभागीय दिशा-निर्देशों का भी उल्लघंन किया गया है। गाड़ी की मुरम्मत से सम्बंधित बिल प्राप्त किए जा रहे हैं। बिलों की छानबीन के उपरान्त उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपलेखापाल की नियुक्ति का मामला मान्य राज्य प्रशानिक प्राधिकरण, हि0प्र0 में ओ0ए0संख्या1952/2015, श्रीमती सविता कुमारी बनाम राज्य सरकार के तहत मामला विचाराधीन है। इस पर माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार ही कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त/परियोजना अधिकारी, जिला कांगडा की जांच रिपोर्टों के परीक्षण के उपरान्त खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्व अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल मे लाई जाएगी।

माननीय सदस्य ने जैसे बताया कि इसका ट्रांसफर का मामला भी उठाया था परंतु यह अधिकारी बहुत तेज है और इसने ट्रिब्यूनल का सहारा लिया। इस बारे में हाई कोर्ट से दिनांक 16 मार्च, 2016 को फैसला आना है। हमने पूरी जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट को सबमिट की है, इसका ट्रांसफर का मैटर आयेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

श्री किशोरी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने क्या उसको चोरी करने का ऑर्डर दिया हुआ है कि वह चोरी करता रहे? मैं यह चाहता हूं कि जल्दी-से-जल्दी कार्रवाई करके इसको सस्पैंड किया जाए। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं इस बारे में आश्वासन चाहूंगा कि उसके खिलाफ कब तक कार्रवाई की जायेगी?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष जी, मैंने यह कहा कि हाई कोर्ट में केवल ट्रांसफर का मैटर है जिसमें चार महीने से स्टे लगा हुआ है। मैंने कहा है कि विभाग सख्त कार्रवाई करेगा और कोई बख्शा नहीं जायेगा।

15.3.2016/1210/av/as/2

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमान

सामान्य चर्चा:

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा आरम्भ होगी। इस चर्चा के लिए मैं माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिन्दल जी को आमंत्रित करता हूं।

डॉ.राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016-17 के लिए जो बजट प्रस्तुत हुए और उसके बारे में माननीय प्रेम कुमार धूमल जी ने जो चर्चा प्रारम्भ की है मैं उसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

किसी भी प्रदेश या देश के लिए वह साल कैसा रहेगा; यह सरकार द्वारा दिए गए बजट के ऊपर निर्भर करता है। बजट को स्वाभाविक रूप से रूलिंग साइड के विधायक प्रशंसनीय बताते हैं और बजट की कमियां निकालना विपक्ष का काम है। परंतु यहां मैं जो बजट की स्थिति रखना चाहूंगा उसकी तरफ सरकार को गौर करना चाहिए। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने एक-एक चीज को बड़े विस्तार से रखने का प्रयास किया, पता नहीं सरकार ने उसको गम्भीरता से लिया या नहीं। यदि सरकार गम्भीरता से नहीं लेती है तो उसकी वजह से हिमाचल के जनमानस का भारी नुकसान होने वाला है। हमें जो बजट की किताबें दी गई उसमें वर्ष 2016-17 के ऐक्सप्लेनेटरी मैमोरैंडम के पेज नम्बर 42 के बारे में कहना चाहूंगा।

टी सी द्वारा जारी

15.03.2016/1215/TCV/AS/1

डा0 राजीव बिंदल ----- जारी।

इस एक्सप्लैनेटरी मैमोरन्डम का जो पेज-42 है, यह अपने आप में हिमाचल प्रदेश का क्या फिसकल स्टेट्स है, इसके बारे में बताने के लिए बहुत हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपर 2002-2003 में जो कुल कर्ज़ था, वह 13,209 करोड़ रूपये का था और 2014-15 में यह कर्ज़ बढ़कर 35,151 करोड़ रूपये का हो गया। यह कर्ज़ 13,209 से बढ़कर 35,151 करोड़ रूपया हो गया लेकिन इसमें अभी 2015-16 और 2016-17 का कर्ज़ जुड़ना बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी का अगर हम अगला वर्शन देंखे, तो 2013-14 में जब यह सरकार सत्ता में आई, तो एक पुस्तिका "Budget in brief आपने विधायकों को दी है, इस Budget in brief पुस्तिका के पेज़ नम्बर-14 पर सरकार ने 2013-14 में लोन लिया 4,050 करोड़, 2014-15 में 3,633 करोड़ रूपया, दोबारा 2014-15 में 9,649 करोड़ रूपये और वर्ष 2015-16 में 3,887 करोड़ रूपया। इस प्रकार 21,219 करोड़ रूपये का लोन लिया और 12,000 करोड़ रूपया इन्ही वर्षों में वापिस किया। वर्तमान सरकार ने 9,211 करोड़ रूपये का कर्ज़ पिछले तीन साल में हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर चढ़ाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बज़ट के अन्दर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं दिखाई गई है कि हम आय के साधन कहां से लाएंगे? इसमें खर्चों की कटौती के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्लानिंग की मीटिंग में हर बार हमको परफोंमा देते हैं कि सुझाव दो, खर्चों में कटौती कैसे करें? जो बज़ट इस मान्य सदन में प्रस्तुत किया गया है,उस बज़ट का जो टोटल खर्चा है, उसका अगर हिसाब लगाएं तो जनता की जेब में क्या गया, विकास के काम पर क्या खर्च हुआ? वह आंकड़ा बहुत कमज़ोर है। माननीय अध्यक्ष जी, जो एक्सप्लेनेटरी मैमोरन्डम का पेज़-39 है, इस पेज़ के हिसाब से तनख्वाहों के ऊपर खर्चा होगा 29 परसेंट, इसके अलावा बेज़िज़ है, ग्रांट-इन-एड है,सैलरी, ग्रांट-इन-एड कैपिटल है। ये मिला करके 38.65 परसेंट बनता है। इसके बाद पैंशन पर 12.89, ब्याज़ पर 10.43, मैंटेनेंस पर 6.80, लोन रि-पेमैंट पर 8.15, सबस्डिी पर 3 परसेंट, अन्य 7.05 परसेंट, ऐस्टैब्लिशमैंट पर 1.15 परसेंट और इसके बाद विकास के लिए बचा 12.39 परसेंट। यहां पर पूरा 32,593 करोड़ रूपये का जो बज़ट है, उसके अन्दर 13 परसेंट से भी कम विकास के लिए बचा है। आपने इसके अन्दर लिखा है कि बड़े कामों के लिए 8.69 परसेंट और बज़ट के बारे में बड़ी-

15.03.2016/1215/TCV/AS/2

बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे कि हम किसानों/बागवानों /बिजली/पानी/सड़कों और स्वास्थ्य को पैसा दे रहे हैं। लेकिन कहां दे रहे हैं? हमारा बज़ट बिल्कुल क्लीयरकट, साफ-साफ बोल रहा है कि जितना भी पैसा है, वह सारे-का सारा इधर-उधर जा रहा है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी ।

15.03.2016/1220/RKS/DC/1

डा0 राजीव बिन्दल द्वारा... जारी

और नेट डवेलपमेंट के अंदर कहीं पर खर्चा दिखाई नहीं दे रहा है। वास्तविकता भी यही है। इसलिए नीचे डवेलपमेंट दिखाई नहीं दे रही है। जब हम बार-बार बोलते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, तो आप बोलते हैं कि विकास हो रहा है। वह कहां से दिखाई देगा। 13 परसेंट, पौने 13 परसेंट के ऊपर हम विकास को लाकर खड़े हैं। 13 परसेंट और पौने 13 परसेंट के ऊपर जो सरकार का बजट है और जो यह लम्बी-चौड़ी स्पीच है, यह वास्तव में किसी भी प्रकार से काम की दिखाई नहीं देती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आय को बढ़ाने के लिए हमने क्या साधन दिखाए हैं? केवल एक ही साधन है शराब को बेच करके उससे आमदनी करना। शराब के ऊपर एक्साइज लगाओ, शराब की बिक्री बढ़ाओ। युवाओं को नशे में डालो। लोगों को बीमार करो, अस्पताल में पहुंचाओं फिर उसका ईलाज कराओ। पुलिस थाने में केसिज दर्ज कराओ। शराब पी के गाड़ी चलाओ, उसके बाद एक्सीडेंट कराओ। फिर पुलिस विभाग इस काम में लगे। पूरे प्रदेश को आमदनी प्राप्त करने के लिए केवल एक ही जरिया है और वह है 'शराब'। शराब के जरिये के अंदर मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भी

नई ऑक्सन करने के वजाय, एक बार फैसला होने के बाद आपने पुनः कैबिनेट की और पुराने लोगों को ठेका दे दिया। कितनी धांधली हुई, इस चीज का कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ। इस बार एक अन्य मामला आ गया है कि शराब बेचने के लिए एक नई कोर्पोरेशन बनाई जाएगी। एक्साइज विभाग ऊपर से लेकर नीचे तक, राजस्व विभाग, डिप्टी कमिश्नर जो इसकी हमेशा ऑक्शन करते थे, आप इस बार कौन सा नया गोलमाल करने की तैयारी में है कि कॉर्पोरेशन बनाई जाएगी। हमारा इस सरकार के ऊपर चार्ज है कि जहां पर विपक्ष के लोग हैं वहां पर चेयरमैनों की फौज खड़ी करने के लिए चेयरमैन, वाईस चेयरमैन बनाकर, बत्तियां लगाकर करोड़ों-अरबों रुपए का खर्चा करके प्रदेश की आमदनी

15.03.2016/1220/RKS/DC/2

को उस खर्चे के अंदर डूबोया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कॉर्पोरेशनज बंद करने की बात होती थी, कोई कोर्पोरेशन बंद नहीं हुई। घाटा पैदा करने के लिए सारी कॉर्पोरेशनज हैं। आमदनी बढ़ाने के लिए एक जरिया था, बिजली बेचने का। मेरे विधान सभा प्रश्न में बिजली बेचने का जवाब आया कि कोई रिटायर्ड आई.ए.एस. अधिकारियों की कंपनी है, जिसके माध्यम से 2 रुपए 12 पैसे प्रति यूनिट बिजली बेची गई। हरियाणा सरकार को 4 रुपये यूनिट बेची गई, यू.पी. सरकार को 5 रुपए यूनिट, पंजाब सरकार को शायद 3 रुपए 70 पैसे यूनिट बेची गई। अगर सरकारी क्षेत्र में बिजली 3रुपए 70 पैसे बेची जा रही है, 4 रुपए बेची जा रही है तो उस कंपनी के माध्यम से कम पैसों में बिजली बेचकर जो प्रदेश सरकार ने 2400 करोड़ रुपया कमाया है, वह ज्यादा कमाया जा सकता था। यह मेरा सरकार के ऊपर दोष है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अनिरूद्ध जी का एक प्रश्न लगा है, प्रश्न संख्याः 2902। इसमें पूछा गया है कि बोर्डों निगमों के चेयरमैन, वाईस चेयनमैन, अधिकारी विदेशी दौरों पर कितने गए और कितना खर्चा हुआ? अभी इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर धांधली है। वास्तव में हिमाचल प्रदेश किसान के ऊपर आधारित प्रदेश है। हमने इस बजट में किसान के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे किसान को लाभ मिल सके। अगर हम किसान के खेत को पानी दें, तो किसान सब कुछ कर लेता है। परन्तु इस वर्ष जो आपने हमारे को किताब उपलब्ध करवाई है, 'आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16'

श्री एस.एल.एस द्वारा जारी

15.03.2016/1225/SLS-DC-1

डॉ० राजीव बिन्दल ...जारी

उसके पेज नं. 3 और 4 के ऊपर पैरा संख्या 1.14 हैं जिसमें बड़ा क्लीयर लिखा है कि सिंचाई सुविधाओं के अभाव में हमारा किसान वर्षा के ऊपर निर्भर है, इसलिए हमारे किसान का उत्पादन लगातार घट रहा है। माननीय धूमल जी ने भी इंगित किया कि किसान का उत्पादन घट रहा है। माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी का एक प्रश्न लगा था - प्रश्न संख्या 2757 जो इसी सत्र में 4 तारीख को लगा था। उसके अनुसार भूमि का जलस्तर लगातार हर साल गिर रहा है। हमने इस जलस्तर को बढ़ाने के लिए कोई उपाए नहीं किए। प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि हमने भूमि का जल स्तर बढ़ाने के लिए 13.00 लाख रुपया ख़र्च किया। इसमें मिड हिमालयन प्रोजैक्ट, भू-संरक्षण इत्यादि का ख़र्चा कहां गया? वह भी तो ख़र्च कर रहे हैं। माननीय सुरेश कश्यप जी के प्रश्न के उत्तर में मिड हिमालयन प्रोजैक्ट का बड़ा लंबा-चौड़ा उत्तर आया है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में सब-कुछ गोल कर दिया। वॉटर कंजर्वेशन के लिए मिड हिमालयन प्रोजैक्ट में जो करोड़ों रुपया आया, वह कहां गया? हमारा जलस्तर लगातार घट रहा है। किसान के लिए इलाके के अंदर एक भी तालाब जिंदा नहीं दिखाई देता है। हमने किसान को पानी उपलब्ध नहीं करवाया उसे भगवान् भरोसे छोड़ दिया। किसान को हमने क्या-क्या दिया? हमने कहा कि हम सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देंगे और पॉली हाऊस पर सब्सिडी देंगे। धूमल सरकार ने यह पहले ही दी है। उस समय 90 परसैंट तक सब्सिडी दी गई और पंडित दीन दयाल किसान-बागवान समृद्धि योजना चालाई। अब उसका नाम बदल दिया गया। पिछले 3 सालों में सही में ही किसान के उत्पादन में गिरावट आई है; किसान के खेत को पानी नहीं दिया गया।

बंदरों और जंगली जानवरों का हिसाब-किताब क्या है? बंदरों को लेकर भी बड़ी चर्चा हुई जिसे मैं आपके सामने रखूंगा ।

हमने वैल्यु एडिशन के लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरमौर का किसान अदरक पैदा करता है। हमारे वहां से चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी महोदय यहां हैं। वहां पर ट्रकों के हिसाब से अदरक धोकर पानी गिरी नदी में बहाया जाता है। हमने आज तक अदरक की वैल्यु एडिशन के लिए एक भी प्लांट नहीं लगाया। इस

15.03.2016/1225/SLS-DC-2

साल टमाटर का रेट पहले दो महीनों तक 2 रुपये प्रति किलो था। हमने इसकी वैल्यु एडिशन के लिए कुछ नहीं किया। न पिछले तीन सालों में किया और न इस बजट में किया।

फूलों का उत्पादन चम्बा, सोलन और सिरमौर जिलों में हो रहा है। फूलों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने कोई व्यवस्था नहीं की। मशरूम का उत्पादन बढ़ाने के लिए और उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोल्ड चेन का कोई इंतजाम नहीं किया। हमने ठंडी गाड़ियों का इंतजाम नहीं किया जिनसे हमारा मशरूम, फूल, टमाटर और दूसरे पैरिशेबल प्रोडक्ट्स सीधे दिल्ली की मार्किट में जाकर बिकें। इस बजट के अंदर किसान के लिए कोई प्रावधान नहीं है। किसान को भगवान् भरोसे छोड़ा गया है।

माननीय धूमल जी ने दूध उत्पादन की बात कही। आज दूध उत्पादन किसान को 35 रुपये प्रति लीटर पड़ता है। हमने एक रुपया रेट बढ़ाकर नाखून कटाकर शहीद होने की बात की है। स्थिति यह है कि हिमाचल का धान, जो थोड़ा-सा निचले इलाकों में पैदा होता है, उसको बेचने के लिए भी हरियाणा के अंदर चक्कर काटने पड़ते हैं। इस बार मुझे व्यक्तिगत रूप से 3-4 बार धान बेचने के लिए हरियाणा की मंडियों में जाना पड़ा, तब जाकर हिमाचल का धान हरियाणा की मंडी में बिका। हिमाचल के धान का खरीददार भी हिमाचल सरकार के पास नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न संख्याः 2826 स्ट्राबेरी को लेकर लगा था। हम कहते हैं कि हम किसान के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। स्ट्राबेरी हमारे लिए बहुत कुछ

दे सकती है। लेकिन स्ट्राबेरी के लिए हमने क्या किया? पिछले 3 सालों में पूरे प्रदेश के स्ट्राबेरी उत्पादकों को 11,91,300 रुपये कुल सब्सिडी दी। फिर हम

कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। बेचारे उत्पादक मर रहे हैं। एकड़ों के हिसाब से उन्होंने स्ट्राबेरी लगाई, सड़कों के ऊपर रख दी या उखाड़कर फैंक दी और अब लोग उसे मुफ्त में लेकर जा रहे हैं।

जारी ...श्री गर्ग जी

15/03/2016/1230/RG/AS/1

डॉ. राजीव बिन्दल----क्रमागत

स्ट्रॉबेरी को बेचने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने इसके लिए किसान को कुछ नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बरसात के नुकसान की भरपाई, यह बहुत गज़ब की बात है। बरसात की किसान को सबसे ज्यादा मार पड़ती है। यहां प्रश्न संख्या 1160 है, किसानों को भरपाई के बारे में और मैं जरूर चाहूंगा कि यहां बैठे अधिकारी भी यह नोट करें और माननीय राजस्व मंत्री जी भी इसका नोटिस लें। मेरे प्रश्न संख्या 1160 का उत्तर है, पेज नं. 6 पर किसान को कितना मिला 1250-1250-1250/-रुपया, अब मैं और आगे चलता हूं, पेज नं. 16 पर किसान को मिला 250-250-375/-रुपया। एक दिन मैं Z TV और 'आज तक' देख रहा था उसमें बिहार के चैक दिखा रहे थे, 250/-रुपये का चैक, 500/-रुपये का चैक, लेकिन हम तो 250 और 500 से भी नीचे पहुंच गए। 250/-रुपये हमने किसान को दिए, ये इतने सारे पेज आपके उत्तर के भरे हुए हैं। किसान को राहत के नाम पर 'ऊंट के मुंह में जीरा' भी नहीं मिला। आपने किसान की हालत क्या की है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की चिन्ता नहीं की। किसान को पानी नहीं दिया, किसान को आपने ऐसी व्यवस्था नहीं की कि वह value addition कर सके। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न श्री महेन्द्र सिंह जी का है उसके उत्तर में लिखा है कि सिरमौर जिले में 5,019 बन्दरों की नसबन्दी तीन साल में की है और फिर कहते हैं कि हम किसानों को बन्दरों से निजात दिलाएंगे। 5,000 बन्दरों की नसबन्दी करके हम कौन सा तीर मार रहे

हैं? वास्तव में 5,000 में से सिर्फ 500 बन्दरों की नसबन्दी हुई होगी, लेकिन बाकी 4500 बन्दरों का पैसा कहां गया? इसकी भी जांच होनी चाहिए, मैंने पहले भी एक प्रश्न के माध्यम से यहां यह आरोप लगाया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा बजट न तो किसान के हित में और न ही प्रदेश के विकास के हित में है। हमारे लिए जनरेशन का साधन क्या है? बिजली है, तो बिजली हमने मुफ्त में बेच दी। इसके अतिरिक्त एक और साधन पर्यटन है, लेकिन पर्यटन के लिए अच्छी सड़कें चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप सिरमौर आए, केवल नाहन आकर चले गए। जिस समय आप नाहन आए थे उस समय तो हमारे नेशनल हाइवे में भी दो-दो फुट के गड्ढे थे। सिरमौर जिले की एक भी सड़क ऐसी

15/03/2016/1230/RG/AS/2

नहीं है जिसके ऊपर कोई पर्यटक आकर पैर रख ले। वहां सुन्दरतम वादियां हैं, परन्तु न हमने वहां सड़कें बनाईं और न ही इस बजट में कोई प्रावधान किया कि कोई way side amenities की सुविधा देंगे। पूरे बजट की किताब से यहां साढ़े तीन घण्टे का भाषण दिया गया। यह माननीय मुख्य मंत्री जी का 19वां बजट है, परन्तु way side amenities के नाम पर एक भी पैसा प्रदेश की सड़कों के रख-रखाव के लिए नहीं है। '**मर्ज बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की।**'

अध्यक्ष महोदय, हमने यहां गैर-सरकारी सदस्य संकल्प दिवस पर कहा कि सड़कें टूट रही हैं, पाईपें डालने के लिए सड़कें तोड़ी जा रही हैं। मेरी यहां पर चर्चा लगी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम सड़कें नहीं तोड़ने देंगे, अपना संकल्प वापस ले लो। हमने संकल्प वापस ले लिया। श्री महेश्वर सिंह जी का प्रश्न लगा, लेकिन ये फिर वहीं-के-वहीं हैं और अब सड़कें फिर टूटी हुई हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां सही उत्तर दिया कि 9,00,000/-रुपये प्रति किलोमीटर से 15,00,000/-रुपये प्रति किलोमीटर पैसा जमा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि यह पैसा कहां जा रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश में सड़कों हालत ठीक नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने किसान की बात की। किसान का माल ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? सेब ट्रांसपोर्टेशन की बात आई, रूलिंग पार्टी के सदस्य बहुत जोर से बोल रहे थे,

जनाब, आपके चुनाव क्षेत्र में यदि सड़क ठीक हो, तो सेब 40-40/-रुपये प्रति पेटी में जा सकता है, लेकिन आज 100/-रुपये प्रति पेटी जाता है। हमने मांग की कि सैंज से लेकर गिरीपुल, गिरीपुल से लेकर कुमारहट्टी और कुमारहट्टी से लेकर सीधे नारायणगढ़ हार्टिकल्चर रोड जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक भी पैसा नहीं रखा गया। किसान का माल कैसे जाएगा? दोगुणे पैसे में माल जा रहा है। ऐसी सड़कों पर न तो पर्यटक आता है और न ही किसान का माल ठीक से जा पाता है।

एम.एस. द्वारा जारी

15/03/2016/1235/MS/AG/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी-------

अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म कैसे आएगा? एशिया का सबसे बढ़िया फॉसिल पार्क हमारे विधान सभा क्षेत्र सुकेती में है। इस साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वहां हो रही है। वहां सड़क में गड्ढे हैं। हमने विधायक प्राथमिकता में सड़क को डाला था और डी0पी0आर0 भी बनी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है, अधिकारीगण भी नोट कर रहे होंगे। कहा गया कि खजूरना-सुकेती-कालाअम्ब सड़क को सी0आर0एफ0 में डाल दो, केन्द्र सरकार से पैसा मिल जाएगा। इसकी मु016.50 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 बनी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इनको इंटरनेशनल गैस्ट भी माना है । माननीय अध्यक्ष जी, हमारी लागत बढ़ रही है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए। अभी 20-22 माननीय सदस्य बोलने को हैं।

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार को सुझाव दे रहा हूं। हमारी जो लागत बढ़ रही है उसके बढ़ने का सिलसिला जब तक नहीं रूकेगा तब तक मामला ऐसे ही चलता रहेगा। एक प्रश्न संख्याः 1101 है। लागत कैसे बढ़ती है? माननीय मुख्य मंत्री जी इसको कन्ट्रोल करेंगे तो 50 प्रतिशत फायदा होगा। हमारे डिग्री कॉलेज संगड़ाह की बिल्डिंग का 8 करोड़ 18 लाख 22 हजार रुपये का प्रारूप था और जब बिल्डिंग पूरी हुई तो

उसके ऊपर 15 करोड़ 88 लाख 46 हजार 107 रुपए का खर्चा आया। विभागीय उत्तर में लिखा है, क्योंकि ठेकेदार ने काम देरी से किया इसलिए सरकार को 7 करोड़ रुपये की चपत लगी। सरकार का काम सरकार के पैसे को बचाना है या ठेकेदार के पैसे को बचाना है?

अध्यक्ष जी, हम इस बजट के माध्यम से चाहते थे कि सड़कें अच्छी हो जाएंगी लेकिन नहीं होंगी क्योंकि बजट के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से जो सड़कों का पैसा हमें केन्द्र से मिल सकता है उसमें हमारी फॉरैस्ट क्लीयरेंस नहीं है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में नाहन विधान सभा क्षेत्र की एक भी "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" की सड़क तैयार नहीं है जिसको केन्द्र सरकार को भेजा जा सके। जब यहां सड़क की डी0पी0आर0 ही तैयार नहीं है तो केन्द्र सरकार हमें क्या देगी?

15/03/2016/1235/MS/AG/2

माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य विभाग के बारे में मैं लम्बी चर्चा नहीं करूंगा परन्तु एक भी नई योजना स्वास्थ्य विभाग की इस बजट के अंदर नहीं है। वही पुरानी योजनाएं हैं जो आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार के समय की थीं; जैसे "बेटी है अनमोल योजना" चल रही है। "स्वास्थ्य बीमा योजना" भी पुरानी योजना है। "अटल स्वास्थ्य सेवा योजना" का आपने नाम बदल दिया लेकिन वही चल रही है। "जननी सुरक्षा योजना" भी वही चल रही है। "शिशु सुरक्षा योजना" वही चल रही है। "एनिमिया मुक्त हिमाचल योजना" वही चल रही है और डि-वर्मिंग योजना" भी वही चल रही है। आपने क्या लिखा है कि हम डी0एन0बी0 करवाएंगे? माननीय अध्यक्ष जी, एक भी हमारा जिला अस्पताल डी0एन0बी0 करवाने को तैयार नहीं है। कैसे होगा? आप जिस सब्जैक्ट में डी0एन0बी0 करवाना चाहते हैं उस सब्जैक्ट के अंदर सीनियर प्रोफेसर उस जिला अस्पताल के अंदर होना चाहिए। आपने बजट के अंदर किस आधार पर गुमराह करने का प्रयास किया है? ऐसा कौन सा जिला अस्पताल ऐसा है जिसके अंदर सीनियर प्रोफेसर डी0एन0बी0 का सर्टिफिकेट इशू करेगा? उसके लिए डी0एन0बी0 क्लीयरेंस ही नहीं देगा। माननीय अध्यक्ष जी...,

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आपको बोलते हुए 25-26 मिनट का समय हो गया है। बाकी माननीय सदस्यों ने भी बोलना है।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, मैंने कैंसर के इलाज की पहले भी चर्चा की है। आपने उत्तर दिया कि कैंसर के इलाज के लिए जो योजना है उसके अनुसार जिला अस्पताल के अंदर कैंसर का इलाज केवल बी0पी0एल0 वाले को मिलेगा जबकि उसको तो इसका कार्ड पहले ही मिला हुआ है परन्तु अन्य कैंसर के मरीजों के लिए आपके पास कोई प्रावधान नहीं है। आपने पत्र लिख करके और यहां विधान सभा में उत्तर द्वारा हमें मना कर दिया कि हम कैंसर के मरीजों का इलाज करने में सक्षम नहीं हैं। हम इलाज के उनसे चार्जिज लेंगे। पूरे देश के अंदर कैंसर सोसायटी आपको पैसा देने के लिए तैयार है लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार बाहर से पैसा लेकर कैंसर के मरीजों का इलाज करवाने के लिए तैयार नहीं है।

15/03/2016/1235/MS/AG/3

अध्यक्ष जी, पैरा-मेडिकल में आउट सोर्सिंग के तहत स्टाफ इनकी सरकार ने रखा और फिर उसमें 27 लोगों की सेवाएं इन्होंने समाप्त कर दी हैं। मैं इस पत्र को यहां ले कर रहा हूं। मैं उस पर लम्बी बात नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी धौलाकुआं में गए थे।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

15.03.2016/1240/जेएस/एएस/1

डॉ0 राजीव बिन्दलः------**जारी**------

प्राईमरी हैल्थ सेन्टर का ई0एस0आई0 बना दिया। आपने वहां पर घोषणा की कि यह पी0एच0सी0 तो पी0एच0सी0 ही रहेगी ई0ए0आई0 नहीं बनेंगी। हमने पत्र लिखे और आपको भी लिखे। आपने पत्र का ज़वाब नहीं दिया लेकिन आज तक वह पी0एच0सी0 नहीं बनी। वहां केवल ई0एस0आई0 डिस्पेंसरी है। वहां ई0एस0आई0 का कोई आदमी ही नहीं

है। सैंकड़ों, हजारों लोगों ने आपसे मिलकर प्रार्थना की और आपने घोषणा की परन्तु घोषणा का कुछ नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के पैसे, मैंने बार-बार कहा, आपने पत्र लिखा। डेढ़ करोड़ रूपया प्राईमरी हैल्थ सेन्टर और सब-सेन्टर्ज का आपने खुर्दबुर्द कर दिया। आप उस पैसे को गांव के विकास में नहीं लगाना चाहते हैं। मुझे आपने उसका उत्तर नहीं दिया। .....(घंटी)..... माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तीन मिनट में अपनी स्पीच खत्म कर दूंगा। एक बात मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। एक जसमत नाम का वॉर्ड ब्वाय है। उसकी पोस्टिंग नाहन में है। उसकी डेपुटेशन एक प्राईमरी हैल्थ सेन्टर में है, जहां पर न वॉर्ड है न ब्वॉय है और न बैड है। बार-बार रिक्वैस्ट कर दी और बार-बार चिट्ठी लिख दी परन्तु वह बड़ा प्रिय है। वहां पर वार्ड में सेवा नहीं करता । ऐसे ही नाहन से दगेहड़ा आपने डिप्यूट कर रखा है। सरकार की पोलिसी, आप उत्तर नहीं देना चाह रहे हैं। अभी आपने पूछा था कि सेम डिविज़न के अन्दर एक्सियन नहीं लग सकता है। एक बहुत ही चहेता मिस्टर नरेन्द्र है, वह जे0ई0 भी रोहड़ू में, एस0डी0ओ0 भी रोहड़ू में और एक्सियन भी रोहड़ू में। प्रश्न का उत्तर आता नहीं, वह इसलिए नहीं आता क्योंकि वह बहुत प्रिय होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आशा वर्कज़ का बहुत ही गम्भीर मामला है। 7000 आशा वर्कज़ हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि आशा वर्कज़ को 1000 रूपए का भत्ता देंगे। उनको नहीं मिल रहा है। आशा वर्कर को किसी को 400 रूपये महीना इन्सेंटिव पड़ रहा है, किसी को 500, किसी को 600 रूपये पड़ रहा है। यह बात नोट करने की है। गर्भवती की डीलिवरी के लिए 300 रूपया, जब डीलिवरी होगी। फैमिली प्लानिंग के लिए 150 रूपया जब फैमिली प्लानिंग होगी। जब एक बच्चे के 9 महीने तक सारे टीके पूरे करवाएगी तब 150 रूपये। साढ़ तीन

15.03.2016/1240/जेएस/एएस/2

सौ रुपया महीना फिक्स इन्कम पर हमने महिलाओं को उनके घरों से बाहर निकाल दिया। जो भत्ते का आश्वासन दिया था वह नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और बड़ा गम्भीर मामला है। फोरैस्ट मिनिस्टर यहां पर बैठे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी इसकी तरफ ध्यान दें। ईको टूरिज्म की पॉलिसी आपकी सरकार ने वर्ष 2005 में बनाई। सितम्बर, 2015 में आप ने फिर मॉडिफाई कर दी।

क्यों की, आप जानते होंगे। उसके बाद उसके ऊपर आपके वहां ऑब्जैक्शन्ज रेज़ हुए। फाईनांस डिपार्टमैंट में मामला गया। फाईनांस डिपार्टमैंट ने कहा कि यह पॉलिसी ठीक नहीं है। आपने 16 फरवरी, 2016 को पोलिसी दोबारा से नोटिफाई कर दी और दोबारा से माननीय मंत्री जी ने इस विधान सभा में स्टेटमैंट पिछले हफ्ते दी है कि हम इसको दोबारा से रिवाईज़ करेंगे। इसके पीछे क्या गोलमाल है, इसकी चिन्ता करने की जरूरत है? आप ही पॉलिसी बना रहे हैं आप ही ब्रेक कर रहे हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य बिन्दल जी अब आप अपनी स्पीच खत्म करो। Not to be recorded. आप अंडरटेकिंग दे दीजिए कि बाकी सदस्यों को मैं टाईम नहीं दूंगा। फिर मैं बाकियों को समय नहीं दूंगा। आप बैठ जाएं खुद ही समाप्त हो जाएगा।

डॉ0 राजीव बिन्दलः माननीय अध्यक्ष महोदय, खबर है कि एच0ए0एस0 के रिटन टैस्ट में टॉप मगर इन्टरव्यू में 150 में से 27 नम्बर। लड़का फेल हो गया बेचारा। क्या मामला है? राजनीति की इंतहा की मैं चर्चा नहीं करुंगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। जो पत्थरों की राजनीति, उद्घाटन, शिलान्यासों की चल रही है, तीन-तीन, चार-चार बार शिलान्यास और उद्घाटन केवल मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुए हैं। धूमल जी के सारे शिलान्यास उठाकर स्टोर में हैं और आजकल मिलते नहीं है परन्तु अब तो माननीय मुख्य मंत्री जी इंतहा हो गई कांग्रेस का जिलाध्यक्ष स्कूल का उद्घाटन कर रहा है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

15.03.2016/1245/SS-AS/1

डॉ0 राजीव बिंदल क्रमागतः

यह खबर और सूचना मैं जनाब को भेज रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। सिरमौर में खस्ताहाल सड़कें हैं। स्कूलों में मास्टर और पी0एच0सीज़0 में डॉक्टर्ज़ नहीं हैं। खनिज के दोहन के लिए आपने आश्वस्त किया, बहुत अच्छी बात है। आप इसमें आगे बढ़ेंगे। मेरा एक और कहना है कि कांग्रेसी ठेकेदारों की चांदी है। केवल उनको काम मिल रहे हैं। बाकी बेचारे ठनठन गोपाल हैं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी आग्रह है कि नाहन की वाटर सप्लाई स्कीम के लिए पैसा दें। उस स्कीम का काम चल रहा है। मैंने वित्त

सचिव से भी दो-तीन बार आग्रह किया है। वह स्कीम नाबार्ड में सैंक्शन है और दूसरी स्कीम के लिए भी पैसे की आवश्यकता है। उसके लिए पैसा उपलब्ध करवाया जाए।

उद्योग मंत्री जी, यहीं पर बैठ हैं। --(व्यवधान)--

Speaker: No recording now. I have to distribute the time. There are about are about 20 people have to speak. आपका एक-एक मिनट ही खत्म नहीं हो रहा। आप कितनी देर तक बोलेंगे? क्या सारा दिन बोलेंगे? I have to cut short the time of others. OK, finish it in one minute.

डॉ0 राजीव बिंदल: अध्यक्ष महोदय, कालाअम्ब औद्योगिक क्षेत्र में बस-अड्डा नहीं है। सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट नहीं है। वेस्ट वाटर ट्रीटमैंट प्लांट नहीं है। कॉमन एफ्लुऐंट ट्रीटमैंट प्लांट नहीं है। इंडस्ट्री के पांच हजार लोग बेरोजगार हो गये। ट्राईबल हैड का पैसा हमारे विधान सभा क्षेत्रों को नहीं मिल रहा। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने आय बढ़ाने के लिए कोई साधन नहीं किये और खर्चे घटाने का कोई प्रयास नहीं किया। शिक्षा में गुणवत्ता लाने का कोई प्रयास नहीं किया। गुणवत्ता चिकित्सा का प्रयास नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता का न देना वास्तव में बेरोजगारों के साथ धोखा है।

माननीय अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, धन्यवाद। इस बजट से सच में हम अपेक्षा करते थे कि यह 19वां बजट है, अनुभवी बजट है और हिमाचल को कुछ मिलेगा, विकास होगा लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो पायेगा। इतना कहते हुए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

15.03.2016/1245/SS-AS/2

अध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप बोलिये।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि मुझे अपने धान को बेचने के लिए हरियाणा की मंडियों में जाना पड़ा। ज़रूर जाना पड़ा होगा। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जिस जमीन से यह धान निकली, वह जमीन क्या डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, जहां पर आजकल ये इलैक्शन लड़ते हैं या कहीं और है? एक तो ये इस बात

का जवाब दें। दूसरा, क्या रेणुका डैम की लैंड एक्विजिशन में हेराफेरी हुई थी, ये वहां पर स्थित है या कहीं और है?

डॉ0 राजीव बिंदलः माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि मंत्री जी को जिस प्रश्न का जवाब देना चाहिए था कि 2 रुपये 20 पैसे बिजली क्यों बेची, उसका जवाब तो नहीं दिया। दूसरा, यह जो धान की बात है यह किसान की बात है और किसान का धान पांवटा के एरिया के अंदर होता है तथा उसकी चिन्ता करना सरकार का काम है। रेणुका जमीन की अगर धांधली हुई है, किसी ने धांधली की है तो उसको फांसी पर टांगना चाहिए। यह भी सरकार का काम है। अगर ये धांधली करने वाले को फांसी पर नहीं टांगते या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम भी यह मानकर चलेंगे कि कहीं-न-कहीं सरकार के लोगों की मिलीभगत है। उन लोगों को आप सज़ा क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? वे कौन लोग हैं जिन्होंने रेणुका डैम के अंदर धांधली की है? हम उनके बारे में जानना चाहते हैं। --(व्यवधान)--

मुख्य मंत्रीः जिन्होंने रेणुका डैम में धांधली की है आप उन लोगों से भलीभांति परिचित हैं।

डॉ0 राजीव बिंदलः माननीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने धांधली की है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जिन्होंने गड़बड़ की है उनके खिलाफ कार्रवाई करें।

जारी श्रीमती के0एस0

15.03.2016/1250/केएस/डीसी/1

डा0 राजीव बिन्दल जारी----

केवल इस बात को इंगित करके हमारे विषय को डाइल्यूट करने का जो प्रयास किया है, मैं सीधा-सीधा कह रहा हूं, बिजली बेचनी चाहिए थी । एक हजार करोड़ रुपये का नुक्सान बिजली के बेचने के अंदर हुआ है, उसका जवाब मंत्री जी क्यों नहीं देते हैं? मंत्री जी यहां किसान का मज़ाक उड़ाने के लिए बैठे हैं? उनका धान बेचने के लिए हरियाणा में 300 रुपये क्विंटल रेट ज्यादा था उसने वहां धान बेचा और आपको उसके लिए भी तकलीफ़ हो गई?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं उर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, किसान का कोई भला नहीं कर सकता जब तक किसान की जो प्रोडक्शन है, उसको जनरल प्राईस इन्डैक्स के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। जिस वक्त मैंने पहली बार इलैक्शन लड़ा था,मुझे एक हजार रुपये तनख्वाह मिलती थी और आज मेरी तनख्वाह विधायक के रूप में एक लाख पच्चीस हजार है और 125 गुणा बढ़ी है जबकि किसान की गेहूं की कीमत सिर्फ 100 रुपये से 1500 रुपये हुई है। यह मुद्दा मैंने पिछले साल केन्द्र में उठाया था और मैं वहां पर कांग्रेस का अकेला मंत्री था बाकी सारे के सारे इनके मंत्री थे। मुझे पर ऐसे टूट कर पड़े कि मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहां से निकला था। दूसरे दिन प्रधान मंत्री जी का प्रोग्राम सूरतगढ़ जाने का था। वे तो प्लेन के माध्यम से चले गए, मैं तो जा नहीं सकता था, मैं दिल्ली में रहा और ट्रिब्यून में खबर आई कि Smt. Vasundhara Raje Scindia left Shri Prakash Singh Badal red faced. उन्होंने कहा कि सरदार जी, पंजाब का पानी राजस्थान में आता है और वहां पर वह कैंसर फैलाता है। कहा उन्होंने और जिस वक्त मेरी मीटिंग वाली प्रोसीडिंग आई उसमें लिखा हुआ था कि Shri Sujan Singh Pathania, Minister, Himachal Pradesh said that Punjab water is coming to Himachal Pradesh and cancer is spreading in Himachal Pradesh.इससे ज्यादा मज़ाक नहीं उड़ाया जा सकता और उसको मैं यहां पर पुटअप करूंगा।

15.03.2016/1250/केएस/डीसी/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, गम्भीर समस्या को मज़ाक बनाकर उड़ाना यह मंत्री जी की पुरानी आदत है और जब आप पढ़ते थे, तब भी थी और जब मंत्री बन गए तब भी है। पहले तो माननीय सदस्य श्री बिन्दल जी ने जो बात कही थी, वह सिरमौर के किसानों के धान के बेचने के बारे में कही थी। इनका अपने धान बोलने का मतलब था कि अपने क्षेत्र के लोगों का धान, यह इनका अपने चुनाव क्षेत्र के साथ लगाव है कि वहां के जो किसान हैं वे अपने भाई हैं। दूसरे, मुझे आपसे हमदर्दी है कि आपको इतनी मूंछों के बावजूद वसुन्धरा बना दिया गया।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित की जाती है।

15.3.2016/1400/av/ag/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2.00 बजे अपराह्न उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

उपाध्यक्ष : अब माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री चर्चा में भाग लेंगी।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने मान्य सदन में इस बार 19वां बजट पेश किया है तथा यह हमारे लिए गौरव की बात है और यह एक रिकॉर्ड भी है। इस बजट में प्रदेश के चौतरफा विकास के लिए प्रावधान भी किया गया है। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि मैं जो कहूंगी उसमें आपको कुछ बातें काम की लगेगी और शायद कुछ आपको अच्छी नहीं लगेगी मगर हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर काम करें। लोकतंत्र में 19वीं बार बजट पेश करने का मतलब है कि हमारी पार्टी और माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रदेश के लोगों ने विकास करने का मौका दिया है। आज प्रदेश विकास की जिस मंजिल तक पहुंचा है यह माननीय मुख्य मंत्री जी के इन बजटों का परिणाम है। आज प्रदेश में मात्र 8 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे है और प्रदेश में आज प्रति व्यक्ति आय 130000 रुपये तक पहुंच गई है। हमारे प्रदेश में विकास दर 7.7 प्रतिशत है जो कि राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। यहां पर विपक्ष बार-बार आरोप लगाता है कि हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। मगर मैं यह कहना चाहती हूं कि यह सब बातें तथ्यों से परे हैं। प्रदेश में जी0एस0डी0पी0 रेशो 33 प्रतिशत के करीब है जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय यह 45 प्रतिशत से भी अधिक थी।

टी सी द्वारा जारी

15.03.2016/1405/TCV/AG/1

माननीय सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य मंत्री----- जारी।

यदि हमारा कर्ज़ प्रति व्यक्ति बढ़ा है तो हमारी आमदनी भी प्रति व्यक्ति बढ़ी है। इस तरह से यह विकास के क्षेत्र में एक रिकॉर्ड है । इससे पता चलता है कि यह हमारे प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को कोई सेंध नहीं लगा सके हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने इस बार बज़ट में सभी वर्गों का ध्यान रखा है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक संतुलित बज़ट पेश किया है, जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। यह बज़ट प्रदेश में चौतरफा विकास करेगा। समाज के पिछड़े वर्ग, गरीब महिला, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों के विकास पर विशेष ध्यान देना सुनिश्चित किया है। इस बात का हमें गौरव है कि सामाजिक क्षेत्र के लिए बज़ट में विशेष प्रावधान किया है। समाज के वंचित और असहाय वर्ग के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील हैं। इस बजट में 45 साल से नीचे विधवा मां के लिए सरकार ने पैंशन में इजाफ़ा किया है और उनको 600 रूपये के बजाय 1200 रूपये प्रतिमाह पैंशन देने का निर्णय लिया है। इन सब बातों से उनको काफी अच्छा लगेगा। इससे नौजवानों और विधवाओं को अपने बच्चों की देखरेख में बड़ी मद्द मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 400 रूपये से बढ़ाकर 800 रूपये कर दिया है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि हमने कुछ -न-कुछ लोगों के लिए दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने यह वायदा ही पूरा नहीं किया, बल्कि इस बज़ट में सामाजिक सुरक्षा पैंशन को बढ़ाकर 650 रूपये प्रतिमाह कर दिया है, जो हमारे अपने वायदे से एक कदम आगे हैं। 80 साल से ऊपर के बजुर्गों को 1200 रूपये प्रतिमाह पैंशन दी जाएगी। इसमें आमदनी की कोई सीमा तय नहीं की गई है। इसी तरह 70 प्रतिशत् अपंग लोगों को भी 1200 रूपये पैंशन दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पैंशन के तहत इस साल हमारी सरकार 3 लाख 63 हजार लोगों को पैंशन देगी, जोकि एक रिकॉर्ड है। इसके लिए मु0 368 करोड़ रूपये का बजट रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री, राजा वीरभद्र सिंह जी गरीब और असहाय लोगों के

15.03.2016/1405/TCV/AG/2

प्रति बड़े संवेदनशील हैं और इस वर्ग के लिए बजट में विशेष ध्यान देते हैं। मैं जानती हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है, जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में "हिमाचल प्रदेश युनिवर्सल हैल्थ प्रोटेक्शन स्कीम" लागू की जा रही है। इस बज़ट में इसका प्रावधान किया गया है और इस योजना के तहत प्रदेशवासियों को एक दिन में एक रूपये

या साल में 365 रूपये देने होंगे। इस योजना के अन्तर्गत अस्पताल में भर्ती रोगी को मु0 30,000 रूपये और गंभीर बीमारी हेतु मु0 1.75 लाख का क्रिटिकल देख-रेख पैकेज होगा। ये योजना 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' और 'मुख्य मंत्री स्टेट् हैल्थ' के अलावा होगी। इसी तरह से देश में महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है। केन्द्र सरकार ने राहत देने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। इसलिए हमको कई बार दिक्कत आती है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने महंगाई के लिए भी विशेष बन्दोबस्त किया है। प्रदेश के हर परिवार को 2 दालें, एक लीटर तेल और

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी ।

15.03.2016/1410/RKS/AS/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा... जारी

1 किलो नमक सस्ते दाम पर दिया जा रहा है। इस बजट में 210 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है जिससे प्रदेशवासियों को खाने की सस्ती चीजों तो मिलेगी बल्कि इसका मार्किट प्राइस भी स्टेबल रहेगा। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने इस बजट में घरेलू और कृषि उपयोग के लिए बिजली में 410 करोड़ रुपए की सब्सिडि का प्रावधान किया है। इससे जहां उपभोक्ताओं का बिजली पर आने वाला खर्च कम होगा वहीं उन्हें फायदा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बजट में ये दोनों कदम सराहनीय हैं। इससे आम-आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सरकार बेरोजगारी के ऊपर चिंतित है और हमने पिछले 3 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 27 हजार नौकरियां दी हैं। It is not a small thing, it is a very big thing. 27 हजार नौजवानों को काम दिया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और हमें इस बात का गर्व भी है। इस वर्ष बजट में 1300 नई नौकरियां देने का प्रावधान किया गया है। मंदी के इस दौर के बावजूद भी सरकार का यह बहुत सराहनीय कदम है और इस बात की हमें खुशी है कि हम अपने प्रदेश में अच्छा काम करवा रहे हैं जिससे लोग भी बहुत खुश हैं। इतना बड़ा रोजगार शायद ही किसी केन्द्र और प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाया होगा। इससे पहले कभी ऐसा कार्य नहीं हुआ है यह आप सब भी जानते हैं। सरकार जी जान से कार्य कर रही है। हम जानते हैं कि कृषि और बागवानी हमारे किसान और मजदूरों के लिए रोजी-रोटी का जरिया है। अगर इस क्षेत्र में उत्पादन

और उत्पादकता बढती है तो इससे किसानों का ही लाभ होगा। हमारी सरकार के 3 वर्ष के राज में विकास दर राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा है। चालू वित्तीय वर्ष में खास तौर पर बागवानी और कृषि उत्पादन में बहुत इज़ाफा हुआ है।

उपाध्यक्षः माननीय धूमल जी।

15.03.2016/1410/RKS/AS/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः मंत्री महोदया, आप जो बोल रही हैं यह भाषण आपका किसने लिखा है। इक्नॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार आपके होर्टीकल्चर की प्रोडक्शन डाऊन गई है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः आप आगे सुनिए, अभी हम शुरू कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो कुछ आप बोलते है वह सही बोलते हैं? आपके ज्यादा बोलने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो आप मुत सुनिए। आप चुपचाप बैठिए। और लोग तो सुन रहे हैं। यह आप लोगों की आदत है। अगर हम शराफत की बात करते हैं तो आपको भी शराफत की बात करना चाहिए। अगर आप गाली देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आप जो बोलना चाहते हैं वह आप अंत में बोल सकते हैं। हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। अगर प्रदेश में अच्छी प्रोडक्शन हो रही है तो आपको इस बात का क्या एतराज हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोगों को इसका एतराज हो रहा है। हमें इस बात का अफसोस है कि आप अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते और कभी खुश नहीं रह सकते। आप चाहते हैं कि कोई-न-कोई खुंदक की जाए, कहीं-न-कहीं बात टेढ़ी-वींगी की जाए। जब भी आप यहां आते हैं तो ऐसी ही बात करते हैं। आप कोई भी शुद्ध बात नहीं कर सकते हैं। आप शुद्ध हिन्दी जानते हैं लेकिन आप कोई शुद्ध बात नहीं करते। आप जो कुछ भी बोलना चाहे वह बोलिए। मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। बजट में ये दोनों कदम बहुत सराहनीय है।

श्री एस.एल.एस द्वारा जारी

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ...जारी

हमने आम आदमी को महंगाई से राहत दी है। सरकार बेरोज़गारी को लेकर चिंतित थी। उसके लिए पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 27000 नौकरियां दी गई हैं। आप सोचते हैं कि यह कैसे हुआ? आप सोचते हैं कि यह हुआ ही नहीं है और केवल जादूगिरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों, बागवानों और मज़दूरों के लिए रोजी-रोटी उपलब्ध करवाने की बात हमने की है। हम चाहते हैं कि कृषि और बागवानी में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ती जाए जिससे किसानों की आमदनी में इज़ाफा हो। हमारी सरकार के 3 वर्षों के राज में इस क्षेत्र में विकास दर राष्ट्रीय दर से ज्यादा है। यह बात भी आपको पसंद नहीं है क्योंकि हमारा काम अच्छा है जबकि उनका काम ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)...आप अपनी बात कहिए। कोई बात आपको पसंद नहीं है तो वह भी आप बोलिए। लेकिन इस तरह से किसी के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूं कि मज़दूरों के लिए रोजी-रोटी का ज़रिया तो होना ही चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हम जानते हैं कि हम-सब खाते-पीते लोग हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी उनके बारे में भी सोचा? ...(व्यवधान)...हम तो सोच सकते हैं। हम रात को भी सोचेंगे और दिन को भी सोचेंगे। मैं यह कहना चाहती हूं कि कृषि और बागवानी क्षेत्र में प्रदेश में बहुत इज़ाफा हुआ है, पिछले अढ़ाई सालों में हमने इसमें बहुत इज़ाफा किया है। खासकर बागवानी में हमने बहुत काम किया है। अभी आने वाला एक साल और है। उसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या-क्या होगा। बागवानी क्षेत्र में आपको इतनी वृद्धि देखने को मिलेगी कि हिमाचल इसमें सबसे आगे होगा। आप यह सब देखकर हैरान हो जाएंगे। ...(व्यवधान)...हमारा एक ही परिवार है और वह हिमाचल प्रदेश है। हम अगर पैसा लाए हैं तो उससे काम भी कर रहे हैं। आप उसकी तारीफ़ नहीं करना चाहते। लेकिन आपको सुनना तो चाहिए। आप हमारी बात सुन लीजिए।

बागवानी के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा हिमाचल प्रदेश में बागवानी विकास परियोजना को लागू करने की घोषणा की गई है। इससे बागवानी में हर क्षेत्र की तसबीर बदलेगी, यह आप आने वाले समय में देखेंगे। फल उत्पादन से लेकर फल मार्किटिंग तक किसानों को नई तकनीक और नई किसम के पौधों का प्रबंध किया गया है। हमने सेव व दूसरे फलों के पौधों का भी प्रबंध किया है। जहां-जहां पौधे चाहिए वहां हमने नई-नई किसमों का प्रबंध किया है। बागवानी में डाइवर्सिफिकेशन की बात की जा रही है ताकि फल उत्पादन का लाभ सबको मिले। उत्पादकों को भी अच्छा लगेगा कि यहां पर हर तरह का फल उपलब्ध हो। इसमें हम बड़ी तरकीब के साथ, चुस्ती के साथ और सोच के साथ काम कर रहे हैं। इसका सबको लाभ होगा। इससे बागवानों की आमदनी में भी इज़ाफा होगा और वह खुश होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

बागवानों के लिए नए उपकरण खरीदने के लिए बजट में 10.00 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। मौसम आधारित इंश्योरैंस योजना के तहत 15.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। हर पंचायत में अगले वर्ष 5-5 बेरोज़गार युवकों को प्रूनिंग और कलिपिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। आप जानते हैं क्योंकि आप सब बागवान हैं कि पौधों की बडिंग जो होती है उसक लिए नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह अपना काम स्वयं कर सकें या दूसरों के बगीचों में जाकर काम करें।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

इससे वह कुछ पैसा कमा सकते हैं। यह बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि बेरोज़गार युवकों को रोज़गार मिलना चाहिए। हम महसूस करते हैं कि बेरोज़गारों को किस तरह से नौकरी दी जाए। इसलिए वह बडिंग करना सीखें; इससे उनको फायदा होगा।

15.03.2016/1415/SLS-DC-3

कल मैंने किसी माननीय सदस्य को कहते हुए सुना था, मैं उस समय यहां पर नहीं थी। उन्होंने कहा कि हेल नैट के अंतर्गत 9 लाख वर्ग मीटर का क्षेत्र लाया जाएगा। इससे ओलों से होने वाले नुकसान से बागवानों को राहत मिलेगी। मेरा ख़याल है कि हमने पिछले समय में भी बागवानों को हेल नैट देकर नुकसान होने से बचाया है। जहां-जहां लोगों को इसकी ज़रूरत थी, इसके माध्यम से उनका बचाव हुआ है। शायद आप मशीनों की बात भी कर रहे थे कि हमने 3 मशीनें लाई थीं। वह बहुत अच्छा काम था। उन सभी का प्रयोग नहीं हो पाया, कुछ बेकार पड़ी हैं। जहां-जहां मशीनों का फायदा उठाया जा सका, उसकी हमें खुशी है। हम कभी नाराज नहीं होते।

जारी ...श्री गर्ग जी

15/03/2016/1420/RG/DC/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री-----क्रमागत

लेकिन कई लोगों को आसानी से काम करना मुश्किल हो रहा है। हेल नेट लेना बहुत आसान है। हर गरीब को, छोटे-से-छोटे बागवान या किसान को हेल नेट के लिए उनका परसेंटेज दे दिया जाएगा। यह आप सबको पता है।

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग में अगले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 1150 पद भरे जाएंगे। इसमें फिटर, पम्प ऑपरेटर, ड्राफ्टसमैन और सर्वेयर के पद शामिल हैं। क्योंकि हमारे पास नए बहुत सारे बेरोजगार थे जिनको काम करना नहीं आता था, लेकिन अब हम तैयार कर रहे हैं कि उनको लगाया जाए। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का रिकॉर्ड इतने नए पदों को भरने के लिए भी धन्यवाद देती हूं। हमेशा वे इस बात के बारे में चिंता करते हैं कि जल्दी करो और हर जगह काम होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज यहां पीलिया के मुद्दे पर जरूर कहना चाहूंगी। क्योंकि इस पर बहुत हल्ला हुआ है। पिछले लगभग एक महीने से यह बात सुनने में आ रही है और विपक्ष

बार-बार अंगुलियां उठाता रहता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत कुछ सुनते रहते हैं हम और आप। ये बीमारी फैलती है और उसके मुख्य कारण हैं, लेकिन इस पर पर्दा डाला जाता है। पीछे भी इस पर पर्दा डाला गया था। इसमें कोई नाराज़गी की बात उनको भी नहीं होनी चाहिए जो ये कहते हैं कि हमने तो इसमें कुछ नहीं किया और हमने यह पीलिया नहीं दिया। मैं यह किसी के बारे में क्यों कहूं? लेकिन इस बारे में सबको चिंता है। पिछले तीन साल से पहले क्या हुआ? वह आप सबको पता है। पीलिया की बीमारी जब फैलती है, तो आम तौर पर इसके मुख्य कारणों पर पर्दा डाला जाता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी हो। a, b, c, d चाहे कोई भी होगा, हम किसी को नहीं मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी पांच साल तक मामले को दबाए रखा था। इन्होंने शराफ़त से मामले को दबाए रखा, लेकिन हम लोग शराफ़त नहीं दिखा सके। लेकिन हमने कहा कि गलत तो गलत है और उसको गलत हमने कहा और हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस बारे में और भी कई प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में ऐसा काम न हो। बीमारियां फैलती हैं और उनके मुख्य कारणों पर पर्दा डाला भी जाता है, यह आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की

15/03/2016/1420/RG/DC/2

सरकार ने भी अपने पांच सालों के कार्यकाल में जो देखा है, वह इनको पता है। मुझे उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए और मुझे उस पर बोलने की जरूरत नहीं है, ये लोग समझ गए होंगे। लेकिन हमारी सरकार ने इस बीमारी की मुख्य वजह की हमेशा के लिए पूरी तरह से सर्जरी कर दी है। आने वाला समय आप यह सब देखेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी जनता को कोई कष्ट हो। हमारी सर्जरी ठीक से होनी चाहिए थी। जहां ऐसी बीमारी हो, चाहे आप हैं, बड़ा या कोई छोटा या गरीब है, लेकिन सबकी सर्जरी होनी चाहिए। सीवरेट ट्रीटमेंट प्लांट्स और वाटर ट्रीटमेंट प्लांसट्स को चलाने के लिए, उनको टैस्टिंग के लिए पूरे प्रदेश में स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्ज की घोषणा कर दी गई है कि उनको किया जाए। जो गल्ती एक बार की है, तो उसको ठीक भी करना है। यहां बैठकर बातें बनाने से तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग या आप लोगों ने पीछे कोई गल्तियां की हैं, तो उनको ठीक भी हमें ही करना है और उसके लिए कोई हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्ज की घोषणा कर दी है, उनको लागू कर दिया है और हमने

शुरू भी कर दिया है। अब मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि आने वाले समय में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की वजह से प्रदेश में पीलिया की बीमारी नहीं फैलेगी। मैं आपको यह यकीन दिलाना चाहती हूं, चाहे मैं यहां हूं या कहीं पर भी हूं। यह हमको सोचना ही पड़ेगा। हम अपनी शान दिखाने के लिए ही सोचते रहे, तो यह ठीक नहीं, हम किसी भी प्रकार की शान नहीं दिखाना चाहते। हम कहते हैं कि सच्चाई पर चलो और सच्चाई का इस्तेमाल करो। यह ऐसी कोई शान की बात नहीं है। हमने अच्छा काम किया, तो कोई बात नहीं, अच्छा काम सब कर सकते हैं। आप लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं, हम सब अच्छा काम कर सकते हैं। किसी से गल्तियां होती हैं, तो उसके लिए ऊधम मचाने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी और डेली वेजर्ज बेचारे बहुत गरीब होते हैं। इस बजट में उनके लिए भी पर्याप्त प्रावधान किया गया है। दिहाड़ी को 180/-रुपये से बढ़ाकर अब 200/-रुपये कर दिया है और डेली वेजर्ज को सात साल में नियमित कर दिया जाएगा, जिन कर्मचारियों को पांच साल कॉन्ट्रेक्ट पर हो जाएंगे उन्हें भी रैगुलर किया जाएगा। इस प्रकार गरीबों को आहिस्ते-आहिस्ते तनख्वाह ज्यादा मिलेगी जिससे उनका फायदा होगा। मुझे आप लोगों के अंदर मुस्कराहट नज़र आ रही है और लग रहा है कि आप लोग बहुत खुश हैं। क्या मैं गलत कह रही हूं?

15/03/2016/1420/RG/DC/3

क्योंकि आप लोगों को मुस्कराने की आदत नहीं है, आप मुस्करा नहीं सकते। क्योंकि अच्छी बात करना आपको कभी पसन्द नहीं है। आप दुःखी क्यों हो रहे हैं? खुश रहो, मैं कह रही हूं कि आप खुश रहो। आप चिंता में क्यों रहते हैं?

हमारे अध्यक्ष महोदय भी अभी आकर यहां बैठे हैं। मुझे इस बात का जरूर दुःख होता है कि विपक्ष विरोध की नीति अपनाने पर विश्वास करता है

एम.एस. द्वारा जारी

15/03/2016/1425/MS/DC/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जारी---------

और इस बार भी मुझे लग रहा है कि ये विरोध ही कर रहे हैं। मैं अंत में यही कह रही हूं, आप बुरा न मानें लेकिन विरोध के लिए विरोध की बात नहीं करनी चाहिए। मैं विपक्ष के साथियों से आग्रह करती हूं कि वे अपने नज़रिये में बदलाव लाए और सकारात्मक तौर पर बजट का अवलोकन करके सही को सही कहें। जैसा मैंने कहा कि यदि विपक्ष हमारा विरोधी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि विपक्ष के लोग 24 घण्टे हमारा विरोध ही करते रहें। यह बड़ी शर्म की बात है। यह हमारा परिवार है और हम सब एक हैं। क्यों आप लोग मिल-जुलकर नहीं रहते हैं? इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। अगर आप दिल से खुश हैं तो खुश हो जाओ। अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि जो आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने आगामी वर्ष के लिए बजट पेश किया है उससे प्रदेश के हर वर्ग का चौतरफा विकास होगा। ऐसा विकास पहले कभी नहीं हुआ है जैसा इन तीन वर्षों में हुआ है। इसी तरह से ये इस प्रदेश को सुख और समृद्धि की तरफ ले जाते रहें। अध्यक्ष जी, आपने मुझे चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

15/03/2016/1425/MS/DC/2

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य महेन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, इस विधान सभा के सदन पर प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने 08 मार्च, 2016 को वर्ष 2016-17 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, मेरा मुख्य मंत्री जी से और उस तरफ जो उनके मंत्रि-मण्डल के सहयोगी बैठे हैं जिनमें कुछ सी0पी0एस0 भाई लोग भी हैं -(व्यवधान)- मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि जो एक सामाजिक भाईचारा है आप उस भाईचारे को भी खत्म करने की तरफ कदम रख रहे हैं। धर्माणी जी, चाहे उस तरफ के माननीय सदस्य हैं या इस तरफ के माननीय सदस्य हैं, अगर हम बहन-भाई की तरह व्यवहार करेंगे तो मैं समझता हूं कि

अच्छा रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं देख रहा था कि तीन वर्ष वर्तमान सरकार के पूरे हो चुके हैं और इन तीन वर्षों के अंदर सरकार ने 08 मार्च, 2016 को अपना चौथा बजट प्रस्तुत किया है। जो तीन बजट पहले पेश किए हुए हैं अगर उन तीनों बजट भाषणों को बड़ी गहराई और गौर से पढ़ा जाए तो जो 14 मार्च, 2013 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्लानिंग का बजट प्रस्तुत किया, वह 4100 करोड़ रुपये का था। इसी तरह से 07 फरवरी, 2014 को 4400 करोड़ रुपये का और 18 मार्च, 2015 को 4800 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। हम माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहते हैं क्योंकि वित्त विभाग इनके पास है कि अगला वर्ष 2016-17 का जो बजट प्रस्तुत किया है, इससे पहले अगर हर वर्ष जो बजट बुक छपती है और उस बजट बुक को लेकर के,

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

15.03.2016/1430/जेएस/एजी/1

श्री महेन्द्र सिंहः-----**जारी**-------

अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी मंत्रियों को ले करके और मंत्रियों के इलावा विपक्ष के हम जो चुने हुए नुमाईंदें हैं हमारे साथ डिटेल में कोई चर्चा करते, अधिकारिगण उसमें बैठते। फिर एक-एक विभाग का कि कितनी-कितनी राशि प्रथम वर्ष में रखी गई थी, द्वितीय वर्ष में रखी गई थी, तृतीय वर्ष में रखी गई थी। क्या वह राशि केवलमात्र कागज़ों तक सीमित रही है या उस राशि से धरातल में काम हुआ है। उसके मुताबिक जो चौथा बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर प्रस्तुत करना था, उसको प्रस्तुत करते तो पता चलता कि वाकई में ही पीछे जो काम किया गया है, पीछे जो पैसा दिया गया है और इतनी बड़ी-बड़ी बजट बुक्स छपी हैं, उन पर काम हुआ है? माननीय स्टोक्स जी ने अभी अपना भाषण दिया। हमारा एक आरोप है कि इन तीन वर्षों में प्रदेश सरकार केवल एक विभाग में नहीं बल्कि सभी विभागों में काम करने में असफल रही है। किसी भी विभाग को ले कर आप हमसे चर्चा करें। आपने जो आंकड़ें इस बजट में प्रस्तुत किए हैं अगर हम उन आंकड़ों की तरफ जाएं तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह केवलमात्र आँसू पोंछने वाले आंकड़ें बजट बुक में देखे जाते हैं। चन्द एक क्षेत्र हैं। हमारे उस तरफ के मित्र जो हैं उनके भी सबके क्षेत्रों में

विकास नहीं हो रहा है। चन्द एक क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में केवलमात्र विकास का रथ दौड़ रहा है। मित्रो, इस बजट में जो लोक निर्माण विभाग का बजट है उसके अन्दर हमारी समझ में एक बात नहीं आती है कि हम पी0डब्ल्यू0डी0 में, आई0पी0एच0 में इतनी मोटी-मोटी किताबें उनकी अगर प्रिंटिंग की कॉस्ट ही लगाएं तो वह ही उतनी ज्यादा होगी अगर उस प्रिंटिंग की कॉस्ट को इन किताबों को छापने के बजाय अगर एक-एक चुनाव क्षेत्र के अन्दर आप 15 सड़कों को चिन्ह्ति कर दें। एक-एक चुनाव क्षेत्र के अन्दर आप आई0पी0एच0 की केवलमात्र 15 स्कीमों को चिन्ह्ित कर दें। आप स्वास्थ्य विभाग में

15.03.2016/1430/जेएस/एजी/2

केवलमात्र पांच पी0एच0सी0 भवनों के निर्माण के लिए अगर आप चिन्ह्ति कर दें। उसी तरह से आयुर्वेदा विभाग के अन्दर भी आप केवलमात्र पांच जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर है उनको चिन्ह्ित कर दें तो मैं समझूंगा कि यदि हम उन स्कीमों में ही काम करें तो उसके सकारात्मक परिणाम उन विधान सभा चुनाव क्षेत्रों के आएंगे और वह परिणाम पूरे प्रदेश के भी आ सकते हैं। लेकिन होता क्या है, मैं यहां पर पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग की थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। लोक निर्माण विभाग के अन्दर चार ज़ोन है। उन चारों में जो राशि रखी हुई माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि जो राशि मण्डी ज़ोन के लिए वर्ष 2015-16 के लिए रखी थी वह राशि 66,97,69,000 थी। यह राशि वर्ष 2015-16 के बजट में रखी हुई थी। लेकिन इस वर्ष का बजट और इस वर्ष प्लानिंग का साईज 4800 करोड़ से बढ़ करके 5200 करोड़ कर दिया गया है। समझ में हमारी यह नहीं आ रहा है कि क्या उस राशि को दर्शाने में प्रिंटिंग में कोई गलती हुई है या उस राशि में कोई कमी है केवलमात्र आंकड़ें ही इस हाऊस के अन्दर प्रस्तुत करने है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2016-17 के लिए जो बजट प्रावधान मण्डी ज़ोन के लिए रखा हुआ है वह पिछले वर्ष 66,97,59,000/- रूपये की तुलना में इस वर्ष 46,86,42,000/- रूपये रखा गया है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

15.03.2016/1435/SS-AG/1

श्री महेन्द्र सिंह क्रमागतः

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि मंडी जो हमारा केन्द्रीय जोन है क्या उसमें सड़कों को बनाने की आवश्यकता नहीं है? क्या वहां पर पुलों को बनाने की आवश्यता नहीं है? क्या वहां पर सारी सड़कें और पुल बन कर तैयार हो चुके हैं? इसी प्रकार से अगर हम हमीरपुर की तरफ देखें तो हमीरपुर में जो पिछली बार बजट रखा गया था, वह 46,44,10,000/- रुपया था और इस वर्ष का बजट 44,96,98,000/- रुपया है। इसकी क्या वजह है? एक तरफ सरकार और उसके मंत्री कह रहे हैं कि हमने इन तीन वर्षों में इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल दी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्लान का साइज जो बढ़ गया लेकिन जो आपने पैसा सड़कों/पुलों के लिए रखा, हमीरपुर क्षेत्र में रखा, हमीरपुर जोन में रखा और मंडी जोन के अंदर रखा उसमें क्यों कटौती की गई? मंडी जोन में आपने 66 करोड़ से घटाकर 44 करोड़ रुपया कर दिया। 20 करोड़ की कमी है। हमीरपुर क्षेत्र में आपने लगभग 2 करोड़ की कमी की है। हम एक बात जरूर जानना चाहते हैं कि शिमला के क्षेत्र में पिछली बार जो 2015-16 में सड़कों और पुलों के लिए पैसा रखा गया था, वह 68,81,80,000/- रुपया था। लेकिन इस वर्ष 68 करोड़ से बढ़ करके 79,82,29,000/- रुपया रखा गया है। हम एक बात पूछना चाहते हैं कि ऐसा मंडी और हमीरपुर क्षेत्र के साथ क्यों किया गया? वहां पर सड़कों की दुगर्ति है। अगर हम उसको देखें तो ऐसा लगता है कि वहां पर बहुत बुरी हालत है। मैं माननीय मंत्री जी के विभाग की तरफ इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, आई0पी0एच0 विभाग के अंदर क्या पॉजिशन रही है, मैं उसको भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आपने यहां पर अभी-अभी अपनी बात रखी है। हमारा जो हमीरपुर क्षेत्र है उसमें आई0पी0एच0 विभाग की तरफ से 2015-16 में 70,48,03,000/- रुपया रखा गया था। लेकिन इस बार आपने 70 करोड़ से घटा करके 62,35,65,000/- रुपया कर दिया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि हम चहुंमुखी विकास करते हैं, अगर हमारे आंकड़े गलत हैं तो मैं आपको पेज़ नम्बर दे रहा हूं। यह सारा आपकी बजट बुक में लिखा गया है। वहीं मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और पूछना चाहता हूं। 2015-16 में शिमला क्षेत्र के लिए 41,99,16,000/- रुपये रखे गये थे लेकिन वर्ष 2016-17 के लिए 41 करोड़ से बढ़ करके 77,47,01,000/- रुपया हो गया। क्या माननीय मंत्री

15.03.2016/1435/SS-AG/2

जी जो निचला क्षेत्र है उसमें सारी पीने के पानी की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं? जैसे आपने दर्शाया कि निचले क्षेत्र में जितनी भी हमारी पेयजल परियोजनाएं हैं उन पेयजल परियोजनाओं के अंदर जो फिल्टर बैड बनने हैं, ट्रीटमैंट प्लांटस बनने हैं, क्या वे सारे बन चुके हैं? क्या निचले क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की कमी नहीं है? क्या निचले क्षेत्र में विधायकों ने अपनी विधायक प्राथमिकता में यह लिखा नहीं है कि हमारी फलांनी पानी की स्कीम बननी चाहिए? निचले क्षेत्र के अंदर ऐसी कितनी पीने के पानी की परियोजनाएं हैं जिनके लिए हमारी सरकार के वक्त 65-65 करोड़ रुपया और 41-41 करोड़ रुपया लाया गया है? लेकिन उन स्कीमों को आप आज भी पूरा नहीं करने जा रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि पीने की पानी की व्यवस्था निचले क्षेत्रों में ऐसी चरमराई हुई है कि वहां पर 15-15 दिन के बाद पानी आता है। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? निचले क्षेत्र के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि आपने वहां पर जो पाइपों का क्रय की हुई हैं वे घटिया हैं। मैंने पिछले महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी कहा था कि ऐसी पाइपों की खरीद की है जोकि बहुत ही घटिया पाइपें हैं। वे घटिया पाइपें आई0पी0एच0 विभाग के अंदर लाई गई हैं। हम उसके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं। हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि जो बैकवर्ड एरिया सब-प्लान का पैसा है, जो शिडयूल्ड कास्टस कम्पोनैंट प्लान डिमांड नं-32 का पैसा है उस पैसे में जो स्वीकृत स्कीमें हैं उन स्वीकृत स्कीमों को भी आपके नीचे अधिकारी/कर्मचारी हैं चाहे एक्सियन लेवल है, एस0डी0ओ0 लेवल है या जे0ई0 लेवल है वह क्या कर रहा है कि बैकवर्ड एरिया सब-प्लान के अंतर्गत जो पाइपें क्रय की गई हैं,

जारी श्रीमती के0एस0

15.03.2016/1440/केएस/एएस/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी---

वह जहां बैकवर्ड एरिया में लगनी चाहिए थी, उस क्षेत्र में न लगकर दूसरे क्षेत्र में जनरल क्षेत्र में लग रही है, वहां पर उनको बांटा जा रहा है। क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में है? हमने आपसे पीछे भी निवेदन किया था और आज दोबारा से इस माननीय सदन में निवेदन

करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने तीन वर्षों में 27 हजार नौकरियां दी है। यह माननीय सदन आपसे जानना चाहता है, इस प्रदेश का बेरोज़गार नौजवान आपसे जानना चाहता है कि क्या आप उन 27 हजार का ब्रेकअप देंगें? क्या आप बताएंगें कि आपके विभाग में इन तीन वर्षों में कितने पद भरे गए? मैं दूसरे विभाग के बारे में नहीं पूछना चाहता, आपके विभाग की ही बात करना चाहता हूं। हमने आपको पीछे भी कहा था कि सेब, आम, किन्नू या दूसरे पौधे हैं, उद्यान विभाग आपके पास है, हम आपसे उद्यान विभाग के बारे में जानना चाहते हैं, हमने पीछे भी आपसे पूछा था कि प्राईवेट नर्सरियों में आपने इतने पौधे क्रय किए कि उन पौधों को अगर हिमाचल प्रदेश की प्राईवेट लैंड में प्लांटेशन कर देते तो शायद ही हिमाचल प्रदेश में इतनी जगह उपलब्ध है। क्या आपने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की? अगर नहीं की तो उसके क्या कारण है?

तीसरे, हम आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आपने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में इतने लाख स्क्वेयर मीटर के ऊपर एंटी हेलनैट बिछा दी गई है। माननीय मंत्री जी, हमारा आरोप है, इस माननीय सदन में इसके बारे में एक प्रश्न लगा था केवल मात्र उसका 95 प्रतिशत पैसा शिमला जिला के अंदर लगा हुआ है। क्या शिमला जिला के अलावा मण्डी या कुल्लू जिला के अंदर सेब पैदा नहीं किया जाता? क्या किन्नौर जिला में, चम्बा जिला या कांगड़ा जिला के ऊपर के क्षेत्रों में सेब पैदा नहीं किया जाता ? क्या वहां पर हेलिंग नहीं होती? क्या जहां आम पैदा करते हैं, उस क्षेत्र में आम को बचाने के लिए एंटी हेलनेट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती? अगर पड़ती है तो माननीय मंत्री जी क्या कारण है कि आम वाले क्षेत्र को आपने

15.03.2016/1440/केएस/एएस/2

वंचित कर दिया है? मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक सेब का बहुत बड़ा स्कैब स्कैंडल वर्ष 1988-89 में ऊपर के क्षेत्र में हुआ था उसी प्रकार का दूसरा स्कैंडल अगर होगा तो प्राईवेट नर्सरियों से जो पौधे लिए गए वह होगा और दूसरा स्कैंडल जो है वह एंटी हेलनैट का स्कैंडल आपके विभाग का होगा।

अध्यक्ष महोदय, कहा गया कि हम पीलिया के ऊपर हल्ला डालते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर इतने लोग किस वजह से मर रहे हैं? आपकी पीने के पानी की स्कीमों में जिस प्रकार से पानी की शुद्धता होनी चाहिए, जिस प्रकार से ट्रीटमैंट प्लांट बनने चाहिए, जिस प्रकार से सीवरेज का सिस्टम होना चाहिए, जिस प्रकार से आपके फिल्टर बैड बनना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए उस व्यवस्था में आपकी सरकार, आपका विभाग असफल है इसलिए हम आपके ध्यान में ला रहे हैं। इनको देखना आपका काम है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान डिमांड नं0-32 की ओर दिलाना चाहूंगा जो कि कर्नल शांडिल जी के पास विभाग है। मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे राष्ट्र में आज इतनी पारदर्शिता चल रही है कि अगर किसी को राशन में कोई सबसिडी देनी है तो डिज़िटल राशन कार्ड बनने जा रहे हैं। वह इसलिए बन रहे हैं ताकि उसमें पारदर्शिता रहे। आपके विभाग में सामाजिक सुरक्षा पैंशन जो पहले पोस्ट ऑफिस द्वारा बांटी जाती थी आज वह सीधी उनके अकाऊंट्स में जा रही है और गैस की सबसिडी भी सीधी कंज्यूमर्ज़ के अकाऊंट में जा रही है। इसी प्रकार से चाहे गृह निर्माण है, चाहे पंचायतों का बी.डी.ओ. का पैसा है, चाहे डी.सी. से सेंक्शन जा रही है, सारे का सारा ऑन लाईन सिस्टम है मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि यह जो डिमांड नं0 32 में राशियां दर्शाई गई हैं, पहले तो मैं उनकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और विशेष कर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने तीन करोड़ 17 लाख 92 हजार हैंड पम्प के लिए एक मुश्त राशि रखी है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

15.3.2016/1445/av/as/1

श्री महेन्द्र सिंह------- जारी

क्या आवश्यकता पड़ी? आप पारदर्शिता ला रहे हैं, आपकी सरकार जीरो टोलरैंस की तरफ चली हुई है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम जीरो टोलरैंस की तरफ चले हुए हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता ला रहे हैं फिर एक मुश्त का प्रश्न पैदा नहीं होता। आप एक मुश्त राशि क्यों रख रहे हैं? प्रदेश के 68 विधान सभा क्षेत्रों में कहां हैंड पम्प लगने हैं, हैंड पम्पों की कहां पर कितनी आवश्यकता है; आप उसका बाइफर्केशन क्यों नहीं

करते? यह केवलमात्र हैंड पम्पों की बात नहीं है। आपने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना में 32.60 करोड़ रुपये की राशि रखी हुई है। यहां पर प्रधान सचिव (वित्त) भी बैठे हुए हैं। मैं इनसे भी जानना चाहता हूं। इनका इस पीरियड के बीच में एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है। आप लगभग साढ़े 32 करोड़ रुपये की राशि एक मुश्त रख रहे हैं। आप आज इस प्रदेश के अंदर डिस्क्रिशनरी कोटा खत्म कर रहे हैं कि किसी के पास ऐसी ताकत न रहे कि वह अपनी इच्छा और मनमर्जी से किसी पैसे का दुरुपयोग कर सके। किसी को प्लॉट का आबंटन कर सके। पेज नम्बर 277 पर मल निकासी के लिए 12.80 करोड़ रुपये की राशि एक मुश्त रखी हुई है। आपको पता है कि हमारी सिवरेज की कितनी स्कीमें हैं। आपके पास जो सिवरेज की स्कीमें हैं आप इस पैसे को उसमें क्यों बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं? आप इसमें क्यों इंगित नहीं कर रहे हैं कि हम इतना-इतना पैसा फलां-फलां स्कीम के लिए दे रहे हैं। ऐसा करने से उस जोन में बैठा हुआ चीफ इंजीनियर और उस स्कीम के अंदर जो एक्सियन, एस0डी0ओ0 व जे0ई0 है उसको पता हो कि मेरी स्कीम के लिए इतना-इतना पैसा आया हुआ है इसलिए समय रहते मुझे इस पैसे को खर्च करना है। मैं डिमांड नम्बर 32 के अंतर्गत पेज नम्बर 278 पर नाबार्ड की बात करना चाहता हूं। नाबार्ड के अंतर्गत विभिन्न जिलों के लिए उठाऊ सिंचाई योजनाओं हेतु 2,54,93000 रुपये की एक मुश्त राशि गई है। हम यह पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस राशि को एक मुश्त क्यों रखा जा रहा है? आप इस राशि का योजनावार आबंटन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी

15.3.2016/1445/av/as/2

प्रकार से आपने स्टेट हाई-वे के लिए सी0आर0एफ0 का पैसा जो केंद्र से आया हुआ है। सी0आर0एफ0 का पैसा जो केंद्र सरकार ने विभिन्न सड़कों के लिए दिया हुआ है, आपने तो केंद्र सरकार के पैसे को भी अपनी पोकैट मनी बना दिया है। आप कहते हैं कि 7.56 करोड़ रुपये जो सी0आर0एफ0 का पैसा है उसको भी एक मुश्त कर दिया गया है। हम जो विपक्ष के विधायक है, हमारे निर्वाचन क्षेत्रों में सी0आर0एफ0 की सड़कों के लिए जो पैसा आया हुआ है वहां एक्सियन को कहेंगे कि स्लो डाउन। काम को स्लो डाउन कर दो। मेरी सी0आर0एफ0 में तीन योजनाएं हैं। मेरी एक योजना जिसके लिए 12.27 करोड़ रुपये की राशि आई हुई है उसके अगेंस्ट आपकी इस बजट बुक में केवल 10 लाख रुपये की राशि दिखाई गई है बाकी एक मुश्त रखा गया है। जब हम एक्सियन को पूछते हैं तो वह कहते हैं कि केवल 10 लाख रुपये की राशि है और हम इसी के मुताबिक काम करेंगे। आप कहां की

पारदर्शिता की बात करते हैं? मेरा सरकार के ऊपर आरोप है कि आपने इस प्रदेश में इस प्रकार का चलन शुरू किया हुआ है। इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक के प्रोजैक्ट है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड बैंक ने आपको लम्प्सम में पैसा दे दिया है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार इस देश या विश्व के अंदर एक ऐसी सरकार है कि उसको लम्प्सम में पैसा दे दो। उनकी जहां मर्जी करें वह वहां पैसा खर्च कर दें। वर्ल्ड बैंक का पैसा आता है, केंद्र का पैसा आता है तो वह किसी स्कीम के अंतर्गत आता है। आपने तो वर्ल्ड बैंक द्वारा दी गई 8.40 करोड़ रुपये की राशि को भी एक मुश्त में डाल दिया। जहां इच्छा करेगी वहां दे देंगे और जहां इच्छा नहीं करेगी वहां नहीं देंगे। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्कीमवाइज पैसा आता है। यह पैसा कोई लम्प्सम में नहीं आता। हम माननीय मुख्य मंत्री जी से और यहां बैठे अन्य मंत्रियों से एक बात पूछना चाहते हैं कि पेज नम्बर 288 पर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 45.34 करोड़ रुपये व 5.4 करोड़ रुपये यानि कुल मिलाकर 50.38 करोड़ रुपये की राशि एक मुश्त में क्यों रखी हुई है।

टी सी द्वारा जारी

15.03.2016/1450/TCV/DC/1

श्री महेन्द्र सिंह ----- जारी।

ाफिल्ड में हमारे जो एक्सियन, एस0डी0ओ0 और जे0ई0 है, उनको जब पूछते हैं कि "प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना" के अन्तर्गत जो हमारी सड़कें पड़ी हैं, उनमें आप काम क्यों नहीं करते है? तो वह एक ही बात कहते हैं कि काम कहां से करना है, इसके लिए पैसा ही नहीं हैं। पैसे के ऊपर कुंडली किसने मारी हुई है, पैसे के ऊपर कुंडली मारी हुई है वर्तमान की प्रदेश सरकार ने। इस पैसे को हम एक मुश्त रखेंगे और जहां इच्छा करेगी, वहां पैसा दे देंगे और जहां इच्छा नहीं करेगी वहां पर हम पैसा नहीं देंगे। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि इस प्रकार से काम चलने वाला नहीं है। जब धर्मपुर में बादल फटते हैं, किन्नौर में बादल फटता है या मनाली में बादल फटता है तो मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि फल्ड प्रौटैक्श के लिए जो स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से पैसा दिया जाता है, हम इस हाऊस के बीच में चिल्ला-चिल्लाकर मर गये, हमारे लोग वहां पर बे-घर हो गये, लोगों की ज़मीनें तबाह हो गई है। आपके विभाग के अन्दर एक डी0पी0आर0 बनकर तैयार है

'स्टैक' से अप्रूव हो चुकी है लेकिन आप भारत सरकार को नहीं भेज रहे हैं। माननीय मंत्री जी मैं आपके विभाग की कारगुजारी बताना चाहता हूं बाढ़ नियंत्रण में धर्मपुर को जहां सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, उसके लिए आप 6 लाख रूपये दे रहे हैं। जिस क्षेत्र में कोई नुकसान नहीं हुआ है आप उस क्षेत्र में 7 करोड़ 56 लाख रूपया चैनेलाईजेशन ऑफ पब्बर रीवर जिला शिमला के लिए दे रहे हैं। आप भगवान को याद करो, आखिरकार हम जो यहां पर चुनकर आये हुए हैं और जिसको यहां पर बहुमत मिलता है,उसकी सरकार यहां बनती और सरकार बनने के बाद अगर हम इस प्रकार का भेदभाव करेंगे तो यह भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। आने वाले दिन आपके अच्छे नहीं हैं। आपके अच्छे दिन बीत गये हैं। आपके अगले दिनों में आपको राहू, केतू और शनि की दशा बैठने वाली है और इन तीनों की दशा जब आती है तो आंकड़ा सिंगल डिजिट में रहने वाला होता है। वह डबल डिजिट में पहुंचने वाली नहीं होता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे लिए तो एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि मेरा लोक निर्माण का सर्कल पहले हमीरपुर था,फिर हमीपुर से बदलकर मण्डी कर दिया और फिर मण्डी से बदला अब जोगिन्द्र नगर कर दिया। जब मैं इस बजट बुक को पड़ रहा था, तो मैं ढूंढ

15.03.2016/1450/TCV/DC/2

रहा था कि डिमांड न0 32 में जो पैसा मेरे डिविजन को मिलना है, वह कहां है। माननीय अध्यक्ष महोदय,उन किताबों को बदलते-बदलते जब मैंने दिखा कि जोगिन्द्र नगर के सर्कल में डिमांड न0 32 में केवल मात्र 3 सड़कें हैं और एक-एक सड़क के लिए 2-2 लाख रूपये यानि कुल 6 लाख रूपये रखे गये हैं। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है, ढूंढ़ने पर पता चला कि कुछ पैसा हमारा हमीरपुर सर्कल में पड़ा हुआ है और कुछ पैसा मंडी सर्कल में पड़ा हुआ है। जिस सर्कल के बीच में हमें रखा गया है जैसे खच्चरों पर लादी जब बोझा लादता है और वह देखता है कि कहां इन-बेलैंस हो रहा है। उसी तरह से आप तो अपने सर्कल को बचाने के लिए धर्मपुर का प्रयोग करते हैं। मैंने तो पीछे भी माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा था कि तीन सर्कल तो हमने देखे लिए हैं अब चौथा सर्कल कहीं कांगड़ा की तरफ देखो ताकि हमारी पूरी परिक्रमा पूरी हो जाये और आपके दिल को तसली हो जाये। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं यह आपके लिए अच्छा नहीं

है। वन विभाग की बात करना चाहूंगा, वन विभाग में हिमाचल फॉरेस्ट इको सिस्टम क्लाईमेट प्रूफिंग प्रोजैक्ट मु0 310 करोड़ रूपये का है। दूसरा प्रोजैक्ट 'जाईका' का 10 जिलों में चलना है और यह मु0 1507 करोड़ रूपये का है। विश्व बैंक की "मध्यम हिमालय जलागम विकास परियोजना" 60 करोड़ की है। इसके अलावा कांग्रेस घास को खत्म करने के लिए पिछली साल 20 करोड़ रूपये रखा हुआ था और साथ में इको टूरिज्म पॉलिसी थी, वह भी वन मंत्री जी के हवाले की हुई थी। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जो वन मंत्री महोदय कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर हमने करोड़ों पौधे लगा दिए हैं। स्वां चैनेलाईजेशन के किनारे में वहां 12 करोड़ पौधे लगाए गये हैं।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी ।

15.03.2016/1455/RKS/DC/1

श्री महेन्द्र सिंह द्वारा... जारी

पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अरबों पौधे लगा दिए गए हैं। हम यह बात जानना चाहते हैं कि वह पौधे कहां लगे? क्या जीरो टोलरैंस वाली सरकार, पारदर्शिता वाली सरकार इसकी छानबीन करवायेगी? उन पौधों को ढूंढने के लिए हमें दिन में टॉर्च लेकर जाना पड़ेगा कि कहीं ऐसा पौधा तो नहीं है जोकि जमीन के नीचे पल रहा हो। हमें इस बात की शंका है कि जैसे मुंगफली और अदरक जमीन के नीचे लगता है उसी तरह से ये पौधे भी कहीं जमीन के नीचे तो नहीं पल रहे हैं? शायद वन मंत्री जी ने कोई नई तकनीक लाई हो, क्योंकि आप उस क्षेत्र से आते हैं, जहां जंगल ज्यादा होते हैं। उस नई तकनीक का फायदा पूरे प्रदेश को दिया जाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के अंदर हजारों नौजवान होम गार्ड के हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि होम गार्ड के जवानों को भी पुलिस के जवानों की तरह रेग्यूलर किया जाए। होम गार्ड के जवान उस जगह ड्यूटी करते हैं जहां पुलिस का जवान भी जाने के लिए तैयार नहीं होता है। उन्हें आदेश दिए जाते हैं कि फलां अड्डे, फलां चौराह पर सुबह 6 बजे खड़े हो जाना और रात को 12 बजे ड्यूटी ऑफ करना। आप कहते हैं कि

यह सरकार कर्मचारी हितैषी है। मेरे अनुसार अगर कोई कर्मचारी विरोधी सरकार है तो यह वर्तमान सरकार है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य बहुत समय हो गया, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, आप मुझे दो मिनट का समय दीजिए। खेल के बारे में आपने कहा कि हम मैडल जीत कर लाएंगे। ऑलम्पिक का मैडल लाएंगे, एशिया का लाएंगे, राष्ट्रीय स्तर का मैडल लाएंगे। आपने मैडल की राशि को दो गुना कर दिया है। मैडल की राशि तो बढ़ा दी लेकिन जो खेल विभाग का बजट है उस पर आपने कैंची फेर दी है। उस बजट को 25 करोड़ रूपए से घटाकर 15 करोड़ रुपए कर

15.03.2016/1455/RKS/DC/2

दिया गया है। धर्मशाला के स्टेडियम में क्रिकेट मैच होने जा रहा था। उस क्रिकेट मैच का फायदा हिमाचल प्रदेश को होन वाला था। इस मैच को देखने के लिए प्रदेश के लाखों नौजवानों ने चाहा था कि हम विश्व दर्शन के रूप में, जो विश्व से खिलाड़ी आएंगे, उनके खेल को देखेंगे, उनकी प्रतिस्पर्धा को देखेंगे। आपने जान-बूझकर यहां से मैच के स्थान को बदल दिया। पर्यटन की दृष्टि से यह हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा धक्का है। इसका सीधा आरोप मैं वर्तमान सरकार पर लगाता हूं।

आप महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं(घंटी..)। आपने पुलिस विभाग में, फिमेल हैल्थ वर्कर और नर्सिंग में आरक्षण देने की बात की। अगर आप महिला वर्ग के इतने शुभ चिंतक है तो आप इसको चिन्हित क्यों कर रहे हैं कि हम फलां-फलां पोस्टों में आरक्षण देंगे? आप ऑवरऑल यह कहिए कि जितनी भी पोस्टें निकलेगी हम महिलाओं के लिए 10 परसेंट, 20 परसेंट, 30 परसेंट या 40 परसेंट आरक्षण देंगे। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया मैं आपका आभारी हूं, धन्यवादी हूं।

मैं स्टोक्स जी का बहुत आदर करता हूं लेकिन आपको जो लिखित आंकड़े दिए हैं, वे आंकड़े जिस किसी भी अधिकारी ने दिए हैं आप उस अधिकारी को हमारे सामने लाओ और उससे यह पूछो कि आई.पी.एच. विभाग में 27,000 में से कितने लोगों को आपने नौकरी दी

है। दूसरी बात यह है कि प्रदेश में बेरोजगारों के लिए वर्तमान सरकार को जो बजट में प्रावधान करना चाहिए था उसमें कोई भी प्रावधान बेराजगारों के लिए नहीं किया गया है। इस बजट में जो भेदभाव किया गया है वह विशेषकर ऑपोजिशन के क्षेत्र के लोगों के साथ किया गया है। भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने जो अरबों रुपया इस प्रदेश के लिए दिया है, उन योजनाओं का भी इस बजट में अगर कहीं जिक्र होता तो मैं समझता कि एक बहुत अच्छी बात होती।

श्री एस.एल.एस द्वारा जारी

14.03.2016/1500/SLS-AG-1

श्री महेन्द्र सिंह ...जारी

इससे लगता कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश की मदद कर रही है। नेरचौक में ESI Medical College चलाने के लिए (घंटी) इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। (घंटी)

सर मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

Speaker: Not to be recorded. I will stop it now.

श्री महेन्द्र सिंह : हिमाचल प्रदेश में जो 3 मैडिकल कॉलेज खोलने की बात है उसके लिए इस बजट में कोई भी प्रावधान उसके लिए नहीं है।...(व्यवधान)...

Speaker: Not to be recorded.

श्री महेन्द्र सिंह : इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

जयहिंद।

14.03.2016/1500/SLS-AG-2

अध्यक्ष : मैं इस माननीय सदन की सहमति लेना चाहता हूं कि अभी हमारे पास केवल 120 मिनट हैं जबकि अभी बोलने वाले बहुत से माननीय सदस्य हैं। अगर आप जल्दी-जल्दी बोलेंगे और ठीक बोलेंगे तो 10-10 मिनट का समय मिलेगा अन्यथा बाकियों को वंचित करना पड़ेगा। आप जैसे चाहेंगे, हाऊस वैसे चलेगा। ...(व्यवधान)... अगर सभी ने आधा-आधा घंटा बोलना है तो समय नहीं होगा; फिर केवल 3 सदस्य ही बोल पाएंगे। ...(व्यवधान)... आप अपने आप पर कंट्रोल रखकर बोलिए ताकि मुझे बार-बार घंटी न बजानी पड़े; यह अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए आपको समय का ख़याल रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सभी लोग बोलें तो आपको संक्षेप में बोलना पड़ेगा।

अब श्री कर्ण सिंह, माननीय सहकारिता मंत्री चर्चा में भाग लेंगे।

14.03.2016/1500/SLS-AG-3

Cooperation Minister: Respected Hon'ble Speaker, Sir, इस माननीय सदन में जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट पेश किया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। I am not going to praise the Budget just for praising or butter my Chief Minister and the Government. The very fact is that the Budget presented by the Hon'ble Chief Minister is not an election oriented Budget. All sections of the society have been covered for the welfare of the people of Himachal Pradesh. I believe in talking facts. और मेरी आदरणीय सदस्यों से प्रार्थना है कि अगर आपने क्रिटिसाईज करना है, okay. Fine. लेकिन जो अच्छी बात है, उसकी प्रशंसा कीजिए। Give us suggestions. We will take of your suggestions. You should appreciate good points. That is my request. I don't believe in contradictions. जो बोलता है, it is his own view, but public knows better. I will never go personal nor lie. I will speak about facts. I will start with my department so that the whole House knows of the department. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा I will speak to the point.

Hon'ble Chief Minister has given me the responsibility of Ayurveda and Cooperation honouring Banjar Constituency with Cabinet rank for the first time.

The entire district Kullu is grateful with the blessings of the Hon'ble Chief Minister and cooperation from my officers. We want Himachal Pradesh to be known as Ayurveda State like Kerala. पहले केरल शिक्षा के क्षेत्र में आगे आता था but we want कि टूरिज्म और आयुर्वेद में नाम आए। We are full of herbs. इतनी हमारी जड़ी-बुटियां हैं, but these are not being known to the public the way of their use. I am thankful to the Hon'ble Chief Minister for announcing budget allocation of Rs. 250 crores for the Ayurveda Department.

14.03.2016/1500/SLS-AG-4

In the Budget presented by the Hon'ble Chief Minister, as I have said, every section of the society including employees, youth, senior citizen, agriculturist, horticulturist etc. has been taken care of. Numerous incentives have been proposed for boosting agriculture and horticulture. मंत्री जी यहां बैठी हैं I Overall, the Budget is growth oriented. I would like to thank the Hon'ble Chief Minister for proposing increase in Vidhayak Nidhi from Rs. 75 lacs to Rs. 1 crore, as appreciated by you also. It will accelerate the developmental activities especially in rural areas.

We want to start Panchkarma in all the District Hospitals and dispensaries. In most of the districts, we have this facility, but we want to do it

Continued by AG in English . . .

15/03/2016/1505/RG/1

Cooperation Minister Continued . . .

all over the world, allopathy is necessary where required, but people are moving towards ancient area - ayurveda, reason being कि जहां क्योर होते हैं। We have AYUSH at the Centre. I did attend the seminar of all the Ministries there.

We have four herbal gardens. One more is on the way for sanction plus collection centres for herbals in Kullu, Shimla, Mandi, Chamba, Kinnaur, Lahaul & Spiti and wherever prescriptions are required.

I had the honour of meeting His Holiness Dalai Lamaji at Dharamshala and got the knowledge of Tibetan medicines and treatment also. We have taken up the matter for inclusion of one member in AYUSH, National Council and Hon'ble Chief Minister has approved Tibetan Doctors as per qualification required for the same. Similarly, in Cooperation, I alongwith departmental officers met the Hon'ble Union Minister and put the demands of the State and DPRs are given. It will also be done shortly.

Hon'ble Chief Minister's priority is to fill up the posts which are vacant. करीब 350 डॉक्टर्ज के पद खाली हैं and 550 Pharmacists के. ये पद अब से खाली नहीं है, it is a continuing process. कोई रिटायर होता है, कोई प्रमोट होता है but we are trying कि इन पदों को जल्दी से भरा जाए। 108 पद डॉक्टर्ज की और 150 posts are being filled up through H.P. Public Service Commission and Subordinate Services Selection Board. We are also considering 50 per cent batchwise and 50 per cent through Commission so that ये पोस्ट्ज जल्दी भरी जाएं ताकि डॉक्टर्ज और फार्मासिस्ट्ज की कमी न रहे।--(व्यवधान)--मैं सरकार की तरफ से बोल रहा हूं। We are considering. Proposals for opening of integrated 50 bedded hospital, training centre and herbal garden in the State have been prepared and are being taken up with the Government of India. Very shortly, we are proposing Bajaura as a centre in Kullu for 50 bedded hospital. Besides this, Sidha System

15/03/2016/1505/RG/2

is being introduced in the State from the next year for which proposal is being taken up with the Ministry of AYUSH, Government of India.

A proposal to start 2nd phase of ICDPs in District Solan and Mandi has been moved to NCDC for approval whereas implementation of three new ICDPs in the Districts of Kangra, Kullu and Shimla have been started. I would like to thank the Hon'ble Chief Minister for opening 2nd Degree College at Gara Gusheni, earlier it was in Banjar, and third is proposed for Sainj with Rs. 5 crores advance for the building. I think Banjar is the only Constituency where three colleges will be there. Nowhere else is there. पीछे जो काम हुए हैं, मैं हाई स्कूल कलवारी या अन्य की बात करूं, मिडिल स्कूल की बात करूं, तीन साल में जितने भी खुले हैं और सबसे बड़ी बात Agnishaman at Larji. It was very necessary और माननीय मुख्य मंत्री जी जब दौरे पर आए थे, he announced alongwith the college plus two schools at Raila, Deohari, Paliach, Shangarh and Manglore; Najan, Majhan, Shilli, Katora, Deothal and Bahu as High Scools; and Bhupan, Narwali, Jesta, Chuara and Ruar as Middle Schools. I would like request to Hon'ble Chief Minister कि जब इसी सैशन में शुरू होने हैं, तो कृपया इनकी नोटिफिकेशन जल्दी हो जाए, तो जो लोग या जनता इन्तजार कर रही है उनको इनका फायदा मिले। I am thankful to the Hon'ble Chief Minister that on the genuine public demand and interest, इनसे एक डेलीगेशन भी मिला था, he has agreed in principal जो हमारा पी.डब्लू.डी. डिवीजन -1 है कुल्लू में, that covers 90 per cent of my area और डिवीजन कुल्लू में है उसको बन्जार शिफ्ट किया जाए। No financial implication is involved.

Continued by MS in Hindi . . .

15/03/2016/1510/MS/AS/1

सहकारिता मंत्री जारी---------

ऑफिस के लिए बिल्डिंग है और XEN के रहने के लिए भी बिल्डिंग है so it should be done in public interest. सीमिलरली पालीभाग का डिवीजन-2 एट शमशी, यह कुल्लू में नहीं है बल्कि शमशी में है। सेम केस है। उसमें कोई पैसा नहीं लगना है। this division may be shifted to Larji जहां बिल्डिंग उपलब्ध है। इसके अलावा, मुझे खुशी है कि थलौट में

बिजली का डिवीजन खुला लेकिन मेरे दो सब-डिवीजन उसमें मर्ज कर दिए गए। अब जैसा आप जानते हैं कि थलौट नेशनल हाइवे के बाहर रह रहा है। नेशनल हाइवे दूसरी तरफ से आएगा। तो वहां हमारे लोगों को दिक्कत है। It is a general problem. थलौट में डिवीजन खुला अच्छी बात है लेकिन लोगों की दिक्कतों को देखते हुए यहां लारजी में भी बिल्डिंग उपलब्ध है यह खोला जाना चाहिए। माननीय परिवहन मंत्री जी अभी सदन में बैठे नहीं हैं। अब बंजार में बसें भी बढ़ गई हैं। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं लेकिन वहां पर एक सब-डिपो की जैनुअन डिमाण्ड है। उसको भी मेरी सरकार से विनती है कि इसको देख लिया जाए। उसी प्रकार सब्जी मण्डी पीछे धमोठी में खुली है जिसके लिए स्वर्गीय डब साहब ने 8 बिस्वा जमीन दी। उसकी साथ लगती जगह में फॉरैस्ट की नर्सरी है। हम चाहते हैं कि यह जगह सब्जी मण्डी के नाम हो जाए। In lieu of that एस0डी0एम0 ने भी मौका किया और हमने भी किया, उनको 10 बीघा जमीन दी जाएगी ताकि सब्जी मण्डी हमारी ढंग से चले।

अब अंत में मैं टूरिज्म पर बात करूंगा। यहां पर टूरिज्म की बहुत सम्भावना है। But this area has to be developed. मैं केरल की ही बात नहीं कर रहा हूं बल्कि लोग स्वीटजरलैंड को भी भूल जाएंगे। I am thankful to the Hon'ble Chief Minister to announce, offering five sites including Shoja, in my constituency, to the private sector for developing tourism activities. Hon'ble Chief is taking care of it, but Tourism Department and HPTDC have to take it on priority. Places like Diyar, Garagusheni, Deori, Shangar, Larjee Dam. मुख्य मंत्री महोदय ने मौका देखा है, this area Tirthan is not for trout fishing और जो डैम साइट है it is an idle for water sports and tourism वहां बोट क्लब बनना चाहिए ताकि हम टूरिस्ट्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकें।

15/03/2016/1510/MS/AS/2

यहां फिश की भी बात कर रहे हैं। एक फिश फार्म नागणी में है। वहां पर इस फिश फार्म को नया बनाया गया है। उसकी बिल्डिंग बन गई है जिसका उद्घाटन तत्कालीन सांसद रानी प्रतिभा सिंह ने किया और उस वक्त के मंत्री श्री हर्ष महाजन भी थे। लेकिन आज की

तारीख में इतना पैसा खर्चने के बाद Its not functional. The Department of Fisheries is sleeping. क्यों इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपने खड़ा किया? आप उसमें पानी तक नहीं दे पा रहे हैं? कैसा उसका डिजाइन बनाया? This has to be taken care of और एक बात मैं कह रहा हूं this is first time in India that with the efforts of the Hon'ble Chief Minister, the affected people of Sainj Valley under Hydel Project, Parbati, have been given regular job by the NHPC in the 1st Category to 18 people and in the 2nd Category, 608 families have been allowed a sort of pension, as per daily wage rates of Centre for 2000 days i.e. for five years. थर्ड कैटेगरी में 1000 फैमिलिज हैं। I talking facts, कर्ण सिंह न झूठ बोलता है न बोलूंगा। इस सरकार की पिछले तीन सालों की उपलब्धियां सबके सामने हैं।

जो पंचायती राज की बात कर रहे हैं। अभी हमने एक सम्मेलन बंजार में किया, जहां पर प्रधान से लेकर, पंच से लेकर और बी0डी0सी0 मैम्बर्ज सहित 350 से ज्यादा प्रतिनिधि आए। मेरी 53 पंचायतों में से 45 प्रधान मेरे विश्वास के चुनकर आए। उसमें 1000 से ज्यादा लोग थे।

ये मैंने तीन साल की उपलब्धियां छापीं हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं (कागज दिखाते हुए) कि मैंने क्या-क्या कार्य किए हैं क्योंकि I am answerable to my public. जो लोग वहां आए थे, ये उनकी वहां की तस्वीरें हैं।

अध्यक्ष जी, अभी यहां टूरिज्म की भी बात आई। जैसे भाई गोविन्द जी ने भी कहा,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

15.03.2016/1515/जेएस/एएस/1

सहकारिता मंत्रीः-------जारी-------

पीछे जो घटना घटी 8 इंजीनियर लड़के गुम हो गए थे। मैं बधाई देता हूं मुख्य मंत्री जी को, एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को कि उनको सही सलामत ले कर आ गए। लेकिन मेरा सुझाव रहेगा कि जो ऐसे टूरिस्ट आते हैं, ट्रैकिंग पर जाते हैं they should register themselves. कहां उनको ढूंढे उनका कोई पता ही नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष जी,

अभी आपने पूरा एक घंटा डॉ0 बिन्दल जी को दे दिया, पौना घंटा आपने दूसरे माननीय सदस्यों को दे दिया और मैंने तो अभी 15 मिनट भी नहीं बोला है। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

15.03.2016/1515/जेएस/एएस/2

अध्यक्षः अब श्रीमती सरवीन चौधरी जी चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती सरवीन चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वर्ष 2016-17 का बजट प्रस्तुत किया है, उन्होंने कहा है कि यह उनका 19वां बजट है। जिस तरीके से इस बजट को शब्दों, आंकड़ों के मायाजाल में बुन कर मकड़ी के जाले की तरह चतुराई से पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आदमी के शब्द नहीं बोलते उसका समय बोलता है। इस उम्र के 83वें पड़ाव में उन्होंने इस बजट को मकड़जाल में जनता को भ्रमित करने का, उनको फसाने का पूरा प्रयास किया है। इस बजट में महिलाओं के लिए, मैं यहां पर कांग्रेस के सदस्यों को कह रही हूं कि उन्होंने इस बजट में महिलाओं को पूरी तरह से निराशाजनक बजट दिया है। उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया है। यह युवाओं को भ्रमित करने वाला और बेरोजगारों को हताश करने वाला बजट है। जिस तरीके के साथ बेरोजगारी भत्ते की बात आप लोगों ने कही थी तो निश्चित रूप से यह हताशा भरा बजट है और यह बजट की किताब हम सबको दी गई है। इसी तरह से दूसरे सभी वर्गों को रेवड़ियां दिखाने का काम किया गया है। एक तो होता है रेवड़ियां बांटने का लेकिन आपने सिर्फ दिखाई है। बजट लिखने वालों ने और बजट पढ़ने वालों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि रेवड़ियां कहां से आएगी? पैसा कहां से आएगा उनको खरीदने के लिए और उसका जिक्र करना इस बजट में वे भूल गए हैं? कर्ज़ के बोझ के तले दबा ये प्रदेश कैसे इस बोझ को सह पाएगा? मुख्य मंत्री जी ने बजट के पहले पन्ने में पंचायत चुनावों का जिक्र किया उन्होंने 28,288 पंचायत प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, ऐसी फिगर बताई है। आम नागरिक ने बड़ी शांतिपूर्वक चुनाव करवाए। यह सही है कि जब आम नागरिक कुछ करता है तो वह शांतिपूर्वक ही करता है। कल को बोलेंगे कि सांसद/विधायक आए हैं इसलिए अपनी पीठ थपथपाई। वह तो उतने ही आने हैं जितने पंचायतों के नम्बर थे। इसमें नई उपलब्धी उनकी नहीं रही। लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठता है कि क्या पंचायत चुनाव इससे पहले नहीं हुए? क्या कोई हिंसात्मक कुछ होता रहा, कोई खून-खराबा हुआ, जो इस सरकार के

कारण चुनाव शांतिपूर्ण हो गए? मुझे लगता है कि यह मुख्य मंत्री जी का माईंड सैट दर्शाता है कि

15.03.2016/1515/जेएस/एएस/3

उनके दिमाग में यह पहले से ही घूम रहा था कि हिमाचल प्रदेश असुरक्षित है, पीसफुल नहीं है। धर्मशाला के बारे में यहां पर जिस तरह से हमारी पार्टी के सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह जी ने कहा कि इतना बड़ा वर्ल्ड कप मैच उसमें सुरक्षा प्रदान करने में मुख्य मंत्री और उनकी सरकार नाकाम रही है। इसलिए उनका माईंड सैट ऐसे था कि यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ कमी है। हिमाचल प्रदेश की छवि न केवल हिमाचल में बल्कि पूरे विश्व में, भारतवर्ष में भी हमारी छवि खराब हुई है। मैं, मुख्य मंत्री पर आरोप लगाती हूं कि इस तरीके से अगर वे कम्पेयर करते वैस्ट बंगाल के मुख्य मंत्री का, उस महिला ने भी कितने अच्छे से कहा कि हमारे यहां मैच खेलने आए और हम पूरी सुरक्षा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि आप भी कांगड़ा से हैं और मुझे लगता है कि इस तरीके से धर्मशाला का वहां पर मैच न होना हमारे हिमाचल का 20 साल पीछे जाना है और 20 साल हिमाचल पीछे चला गया।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

15.03.2016/1520/SS-DC/1

श्रीमती सरवीन चौधरी क्रमागतः

इंटरनेशनल मैप पर हमारा नाम खराब हुआ है। मैं इस सरकार के मुख्य मंत्री पर आरोप लगाती हूं कि ये कांगड़ा विरोधी हैं। टूरिज्म की दृष्टि से भी यहां पर नुकसान हुआ है। हिमाचल के धर्मशाला में हम तो कहां बड़ी फ्लाईट्स की बात करते थे, इंटरनेशनल मैप पर हमारा नाम था, मैं यहां मानती हूं कि उनका अनुराग जी के साथ मतभेद और मनभेद दोनों है। इसका पता, इस घटनाक्रम से पता लग गया। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसे सभी पसंद करते हैं। अगर कलकत्ता में मैच होता है तो कोई बात नहीं। हम शहीदों का हमेशा सम्मान करते हैं। कलकत्ता में भी शहीद होंगे। शहीद कोई एक जगह या प्रदेश का नहीं है और जितने भी सैनिक हैं वे पूरे भारतवर्ष के हैं। मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, इसको मैं

सरकार की सबसे बड़ी अचीवमैंट कह सकती हूं कि हिमाचल को 20 साल पीछे ले गए। हिमाचल का नाम इंटरनेशनल मैप से गायब करना और टूरिज्म का नुकसान करना, इनकी उपलब्धि है और वह भी किसी की पीठ थपथपा रहे थे, उन पीठ थपथपाने वालों से भी मैं टूरिज्म के बारे में कहना चाहती हूं कि ये टूरिज्म की गाड़ी घुमाते हैं। टूरिज्म का फायदा उठाते हैं और यहां टूरिज्म को ही पीछे किया है। टूरिज्म का बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी और मुख्य मंत्री जी ने किया है। इससे आगे मैं यह कहना चाहूंगी कि इसके लिए देवभूमि इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। आपकी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। --(व्यवधान)-- संजय जी, मैं आपके बारे में आ रही हूं। मैं आपको भी आज सुनाऊंगी।

मुख्य मंत्री जी ने अपने 19वें बजट की बात कही है और इस 19वें बजट को पेश करते हुए उनको अपने आपमें इंसानियत याद आ गई। अपनी पहचान बताने लग गये और उनके मन में देवभूमि के लिए कुछ करने का अहसास व अरमान पैदा हो गया। क्योंकि अभी तक तो उन्होंने कहा कि जितना जीना था मैं अपने लिये जिया हूं। अब मेरे मन में देवभूमि के लिए कुछ अरमान जागे हैं। मैं इसमें कहना चाहूंगी कि it is too late for Sh. Virbhadra Ji. इसी तरह से वे यहां सोच रहे होंगे, अपने आपमें जब आत्ममंथन कर रहे होंगे और कह रहे होंगे - "ज़रा आहिस्ता चल ये जिन्दगी" क्योंकि वे उम्र के 83वें पड़ाव में पहुंच गये हैं। उनकी लम्बी उम्र हो, उसके लिए हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन वे मन-

15.03.2016/1520/SS-DC/2

मन में सोच रहे होंगे - "ज़रा आहिस्ता चल ये जिन्दगी, कुछ कर्ज़ चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द मिटाने बाकी हैं और कुछ फर्ज़ निभाने बाकी हैं।" क्योंकि हिमाचल प्रदेश कर्जों के बोझ में दबा हुआ है। इसमें लोन के ऊपर लोन लेकर सरकारें चल रही हैं। मेरे से पहले वक्ताओं ने इस बात को बड़ी डिटेल में आंकड़ों के साथ यहां पर रखा है। इसलिए मुख्य मंत्री जी को इस प्रदेश के कुछ कर्ज़ भी अभी उठाने हैं और जो दर्द इंटरनेशनल मैप से हिमाचल को पीछे करके दिया है उस दर्द को भी मिटाना होगा तथा जो फर्ज़ इस प्रदेश के लिए उनके रह गये हैं उसको वे जल्दी पूरा कर लें क्योंकि समय बीतता जा रहा है and he is too late for all this.

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह मैं यह कहना चाहती हूं। संजय जी, ज़रा सुनिये। समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को मिलते हैं। क्योंकि होता यह है कि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। इस तरीके से मुख्य मंत्री जी की असमंजश वाली स्थिति यहां पर पैदा हुई है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं अपने बजट भाषण के ज़रिये उन्होंने विपक्ष पर निराधार आरोप लगाये हैं और अपने निजी मामलों का हवाला भी दिया है। सदन में और हिमाचल के लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की है जो एक कमज़ोर व्यक्ति करता है। उन्होंने इस बजट में अपने निजी मामलों का हवाला दिया। इसका बजट से क्या लेना-देना था? सबके केसिज़ हैं। बहुत सारे लोग केसिज़ भुगत रहे हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी-अपनी तकलीफें हैं। लेकिन यह बजट में भी दे दिया। उन अधिकारियों पर भी मुझे हैरानी है कि इसको भी इस बजट में लिख दिया।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से पूरा-का-पूरा बजट केन्द्र सरकार की योजनाओं पर आधारित है।

जारी श्रीमती के0एस0

15.03.2016/1525/केएस/डीसी/1

श्रीमती सरवीन चौधरी ____जारी---

26270 करोड़ में लगभग 17132 करोड़ केन्द्र का योगदान है। केन्द्र की स्कीमों को नए नामों का अमलीजामा पहना कर हिमाचल की जनता को गुमराह किया गया। इस सरकार ने इस बजट में 31 मार्च, 2015 तक प्रदेश के ऊपर 35151 करोड़ रु0 का कर्ज है और इस वर्ष का कर्ज अगर जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 42 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा। 42 हजार करोड़ के अलावा 3400 करोड़ केवल कर्जे में ही ब्याज देना पड़ेगा। कर्जों के ऊपर ही पैसा दे दिया जाएगा मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि पहले योजना आयोग के तहत केन्द्र पैसा देता था और अब बन्द कर दिया है। उन्होंने बजट में कहा है कि योजना आयोग को बन्द कर दिया है इसलिए भ्रमित करने की कोशिश की गई है । उन्होंने कहा है कि तब भी मेरी सरकार वर्ष 2016-17 में 5,200 करोड़ रु0 की वार्षिक योजना का प्रस्ताव रखती है तो यह 5200 करोड़ की अगली योजना किस तरीके से प्रस्तावित हो गई है? यह पैसा कहां से

आएगा? क्या उनके हाथ में कुबेर का खजाना लगेगा? मैं पूछना चाहती हूं । अगले ही पैरा में केन्द्र सरकार और उसका नीति आयोग, जिस भाजपा सरकार ने योजना आयोग की जगह बनाया है उसका इस बजट स्पीच में अगले पैरा में धन्यवाद भी किया है। सभी केन्द्रीय योजनाओं में 90:10 के अनुपात में सहायता मिल रही है और मुझे लगता है कि इन आंकड़ों को this is called heights of confusion, कि कैसे भी, किसी भी तरीके के साथ इसको लिख दिया गया है। 11,978 करोड़ रु0 की लागत का बजट विश्व बैंक और बाह्य सहायता से चल रहा है। प्रदेश का अपना क्या है, यह कोई नहीं जानता। अध्यक्ष महोदय, बजट में एक ही रामबाण औषधि का अविष्कार सरकार ने किया है केन्द्र की स्कीमों को मुख्य मंत्री जी ने अपने नाम कर दिया है । हम सभी के ध्यान में यह बात है कि अटल आवास योजना को राजीव आवास योजना के नाम से, पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान बागवान समृद्धि योजना को वाई.एस.परमार किसान स्वयं रोज़गार योजना जो 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार की योजना है, उसका

15.03.2016/1525/केएस/डीसी/2

भी नाम बदल दिया। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना सैंटर गवर्नमैंट की योजना है इसमें भी 90:10 की रेशो है, इसको भी मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम दे दिया गया। प्रधानमंत्री कृषि योजना जो 90:10 की रेशो में है उसमें भी अपने ही नाम लगा दिए। हमारी सरकार ने, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने अटल वर्दी योजना शुरू की तो यहां पर महात्मा गांधी योजना आ गई। मुख्य मंत्री जी ने सोचा मैं पीछे रह गया 10+1, 10+2 के बच्चों को वर्दी देनी है तो उसमें मुख्य मंत्री वर्दी योजना जोड़ दूं तो इस तरीके से सारा मिलाने की कोशिश की गई। यहां पर मुख्य मंत्री जी ने मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना की बात की है क्योंकि बंदरों और आवारा पशुओं से तो सरकार निज़ात नहीं पा सकी और गांव के लोगों की वह समस्या लगातार बढ़ती जा रही है तो नया फंडा इन्होंने किया कि हम सोलर लाईटों के माध्यम से या इलैक्ट्रिक करंट के माध्यम से फैंसिंग कर देंगें। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह रीपरकशन है इसमें कोई लीगल इश्यू तो नहीं है? क्या उस करंट से किसी जानवर या इन्सान को खतरा तो नहीं है? क्या यह प्रैक्टिकल चीज़ है या नहीं क्योंकि जहां इलैक्ट्रिक करंट आएगा उसको मॉनिटर कौन करेगा? सोलर लाईट से उसमें करंट आएगा या इलैक्ट्रिक करंट आएगा और जिस तरह का यहां पहाड़ी क्षेत्र है उसके ऊपर

फैंस लगाना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है लेकिन सरकार ने अगर कुछ किया है तो अगले तीन महीने के बाद, अभी मौनसून सत्र आएगा, इसकी प्रोग्रैस रिपोर्ट सरकार को देनी पड़ेगी । केवल कृषकों को लुभाने की बात नहीं है कि इलैक्ट्रिक फैंसिंग होगी ।अगर उसमें इलैक्ट्रिसिटी है तो यह बहुत खतरनाक है। कोई बच्चा भी वहां जा सकता है इस चीज़ की ओर भी अधिकारियों को ध्यान देना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री श्री सुजान सिंह पठानियां जी से कहना चाहूंगी कि सोलर लाईट के बारे में आजकल गांव में लोगों में एक क्रेज़ हो गया है। हमें लोग कहते हैं कि मैक्सिमम सोलर लाईट दे दो लेकिन सोलर लाईट छः महीने, एक साल या अधिकतर दो साल चलती है और उसके बाद

15.03.2016/1525/केएस/डीसी/3

बन्द हो रही है। मैं जानना चाहती हूं कि इसके बीच में उसको मोनिटर कौन करता है, उसकी रीपेयर का क्या प्रोसिजर है? लोग आते हैं सोलर लाईट ही मांगते हैं और विधायक सोलर लाईट्स दे रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता को हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आज प्रदेश में जो भी सोलर लाईट लग रही है मैक्सिमम दो साल से ज्यादा वह नहीं चल रही है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

15.3.2016/1530/av/ag/1

श्रीमती सरवीन चौधरी------- जारी

विभाग को इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। (---घंटी---) अध्यक्ष महोदय, आपने बाकियों को बहुत समय दिया है, मैं चाहती हूं कि आप मुझे थोड़ा और समय दें। यहां पर एल0ई0डी0 की बात हुई और उसके लिए केंद्र ने पांच बल्ब देने की बात कही है। अच्छा होता सरकार लोगों को मुफ्त बल्ब देती जिस प्रकार से माननीय धूमल जी की सरकार ने अपने समय में एल0ई0डी0 के मुफ्त बल्ब दिए थे। आप जरा इस बात पर गौर करो कि आज हम जहां पर इलैक्ट्रिसिटी पर 380 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। आप अगर बल्ब देंगे तो सरकार को प्रति वर्ष के हिसाब से 110 करोड़ रुपये की बचत होगी। 380

करोड़ रुपये की सब्सिडी में से 110 करोड़ रुपये कम कर दें तो फिर भी सरकार को 270 करोड़ रुपये का फायदा होता है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आप इस बात को केबिनैट में लेकर जाएं और एल0ई0डी0 बल्ब मुफ्त उपलब्ध करवाये जाएं।

मुख्य मंत्री जी ने यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही है और कहा है कि संजौली में एक हैलीपेड बनेगा। अच्छी बात है, आपने कांगड़ा में तो टूरिज्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। पिछले साल के बजट में मुख्य मंत्री जी ने हैलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की घोषणा की थी जबकि इस बार उन्होंने हैलीपेड बनाने की बात कही है। मुझे समझ नहीं आता और यह कहां तक प्रैक्टिकल है? जब हैलीपेड ही नहीं है तो हैलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का पिछले बजट में क्या औचित्य था? अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी कनफ्यूज करने वाली स्टेटमैंट है और आप लोग पर्यटन को बढ़ावा देने की कितनी चिन्ता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहां पर आदर्श विद्यालय स्थापित करने की बात की गई। आधुनिक तकनीक से ढांचा बनाने की बात की गई, शिक्षा सम्मान की बात की गई। कई जगह एक क्लास में एक-एक, दो-दो बच्चे पढ़ रहे हैं। वे अपनी क्लास में पास हो गये तो उसको सौ प्रतिशत रिजल्ट माना जा रहा है तथा शिक्षकों का सम्मान व साथ में

15.3.2016/1530/av/ag/2

एक साल की ऐक्सटैंशन देने की बात कही गई है। क्या यह पोसिबल है? यह पोसिबल नहीं है। एक साल की ऐक्सटैंशन भी दे देंगे, सम्मान भी दे देंगे और कहीं चाहे बच्चा एक हो, दो हो या तीन हो; इस बारे में कोई कंडिशन नहीं लगाई गई है। हमारी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर जगह देकर सेंट्रल युनिवर्सिटी को ऐस्टेब्लिश किया। अब आपकी सरकार को बने तीन-साढ़े तीन साल हो गये हैं मगर आप उसके लिए जगह ही उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं तो शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात हम कैसे कर सकते हैं।

इसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है। यहां पर जब एम0सी0आई0 की टीम आती है तो डॉक्टर्ज की इधर-उधर पोस्टिंग करके दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और एम0सी0आई0 के नार्म्ज की तलवार हमेशा हिमाचल प्रदेश के ऊपर लटकी रहती है। फिर आप कहते हैं कि things do not happen, things are made to happen. यह आपकी स्पीच में है। When it comes to future, वास्तविकता की बात करें क्योंकि हैलीपेड बना

नहीं और हैलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की बात कर रहे हैं। उसके लिए मैं कहना चाहती हूं कि there are three kinds of people, first those who let it happen; second those who make it happen; and third those who wonder, what happened? इस सरकार की ये कंडिशन्ज हैं। इनको यही पता नहीं है कि पहले हैलीपेड बनना है या हैली सर्विसिज शुरू करनी है। यह कांग्रेस पार्टी की सरकार की हर क्षेत्र में गुणवत्ता लाने की बात है। Government lacks vision, foresight, planning and execution. इसी के बीच कहीं की ईंट और कहीं का पत्थर लगाकर के भानुमति का कुनबा बना दिया है।

Speaker: How much time would you like now? अभी बोलने वाले और बहुत लोग है।

श्रीमती सरवीन चौधरी : माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी बाहर चली गई हैं। पहले तो वे आंकड़े ही गलत बोल रही थी मगर मंत्री होते हुए हमने उनको टोका नहीं। मंत्री जी इधर-उधर की बात कर देती है, खुद भी बीमार थी और उन्होंने यहां पर पीलिया के संदर्भ में कोई बात नहीं की। उन्होंने यहां पर जो आंकड़े पढ़े उनकी आयु को देखते हुए मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगी। स्वास्थ्य के

15.3.2016/1530/av/ag/3

क्षेत्र में मैं यह कहना चाहती हूं कि यहां पर आज सबसे ज्यादा जरुरत डायलाइसिस सैंटर की है। मैं मानती हूं कि इसके लिए कोशिश हुई है। शिमला में हुई है तथा धर्मशाला के हॉस्पिटल में प्राइवेट डायलाइसिस सैंटर चल रहे हैं। मगर मरीज बहुत ज्यादा है। मैंने कल टांडा मैडिकल कॉलेज में तीन डॉक्टर्ज से फोन करके पूछा कि एक इमरजैंसी है और एक व्यक्ति का डायलाइसिस करवाना है। वहां से फोन पर तीनों डॉक्टर्ज ने कह दिया कि जो डायलाइसिस करता है वह व्यक्ति डेढ़ महीने छुट्टी है और यहां पर डायलाइसिस नहीं हो रहा है। यह सत्य है कि टांडा में डायलाइसिस नहीं रहा है और यह कोई शिकायत की बात नहीं है। मुझे लगता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी गाड़ी करकें जालन्धर, होशियारपुर, पठानकोट जाकर अपना डायलाइसिस करवा रहे हैं और हिमाचल में किडनी फैल्योर के बहुत

टी सी द्वारा जारी

15.03.2016/1535/TCV/AG/1

श्रीमती सरवीण चौधरी ----- जारी।

चांसिज़ हो गये हैं और मैं तो यह कहना चाहूंगी कि इसके लिए विशेष ध्यान दें । पी.डी.एस. में हम जो तेल सप्लाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तेल सबसे बड़ी बीमारियों का कारण रहता है। इसलिए उसकी क्वालिटी भी चैक करनी चाहिए। माननीय मंत्री जी क्वालिटी ऑफ ऑयल ही उचित मूल्य की दुकानों में आना चाहिए ताकि बीमारियां कम हो सकें। फिर मुख्य मंत्री जी पारदर्शिता की बात कहते हैं लेकिन अभी तक तो ये पारदर्शिता ला नहीं पाये है और चेहते संत्रियों के बारे में मैं क्या कहूं, उनकी जेबों के बारे में मैं, कुछ कहना नहीं चाहती हूं। आप सब उससे अवगत है, वे सब क्या कर रहे है। हारे हुए व्यक्तियों को सी0एम0 साहिब ने जो शक्तियां लीज़ पर दे रखी है और आपने फरमाया the secret of getting ahead is getting started. तीन वर्षों में आपकी गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हुई तो आप क्या धक्का स्टार्ट हैं। अध्यक्ष जी, पहले चांदी के चमचे होते थे,लेकिन आज के इस कांग्रेस के सीज़न में इन कांग्रेस के चम्मचों की चांदी है। आपको पता है कि सरकार ने इनको अपनी कैबिनेट में भी क्या-क्या दिया है। लेकिन इतना समय नहीं है कि इसका उल्लेख हम यहां पर कर सकें। अध्यक्ष महोदय एक सैकिंड और लूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। श्री महेन्द्र सिंह जी ने यहां पर जिस तरीके से बहुत सुन्दर बात कही है कि सरकार में रहे जो एम0एल0ए0 उनकी प्रायोरिटी की बात नहीं हो रही है। कल यहां पर श्री संजय रतन जी उछल रहे थे। श्री संजय रतन जी क्या आपके यहां कोई डि-नोटिफिकेशन हुई है? आपके यहां से कोई ऑफिस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हुआ है। जबकि हमारे यहां यह मज़ाक बनकर रह गया है। हमारे खौली फेज़ का शिलान्यास प्रो0 धूमल जी ने किया था, आज अधिकारियों ने मुझे कागज़ तक नहीं दिए कि किस डेट को यह शिलान्यास हुआ था। लेकिन मुझे यह याद है और इसके सारे डॉकुमैंट्स मैंने अपने पास रखे हैं।

Speaker: No more recording please. I have given you enough time. You see, everybody has to speak. आप क्या चीज एडवोकेट कर रहे हैं? किस चीज़ को एडवोकेट कर रहे है? (Interruption) Won't you like to speak? आप मुझे लिखकर दे

दें कि और कोई भी बजट पर बात नहीं करेगा। मैं इनको सारा टाईम दे देता हूं। आप सारे लिखकर दे दो। I have to oblige everybody. आप क्या सिफारिश कर रहे हो, क्या आप

15.03.2016/1535/TCV/AG/2

नहीं बोलेंगे? I will cut down the time of others. इनसे पूछ लीजिए अगर बाकी नहीं बोलना चाहते हैं, तो मैं इनको बोलने देता हूं। आप दो घंटे बोलिए लेकिन मैं बाकी को नहीं बोलने दूंगा। You are taking time of others also. इसके बाद मैं किसी भी मैंबर को नहीं बोलने दूंगा। । आप बोलना चाहते हैं, बाकियों को भी बोलने दीजिए। This is wrong.

श्रीमती सरवीण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहती हूं कि एम0एल0ए0 प्रायोरिटिज़ की प्रोपर इंवैस्टीगेशन होनी चाहिए और उन ऑफिसर्ज़ को पूछना चाहिए जो तीन-तीन साल की विधायक प्राथमिकताएं हैं उसमें कोई काम नहीं हुआ है, पैसा आना तो दूर की बात है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि खौली फेज़-॥ का शिलान्यास प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने किया था और आज उसका पत्थर भी तोड़ दिया गया है। उसके हमें अधिकारियों ने पेपर नहीं दिये लेकिन उसकी शिफ्टिंग तीसा में कर दी गई है। क्या शाहपुर के लोगों के साथ यह अन्याय नहीं है। खौली फेज़-॥ प्रोजैक्ट का जो ऑफिस था उसको शिफ्ट कर दिया गया है। शाहपुर में खौली फेज़-॥ बना था उसके प्रोजैक्ट के कारण गांव की सड़कें बननी थी और कहते हैं कि क्वैश्चन लगता है हैल्थ का और पहुंच जाते हैं एम0डी0एम0 ऑफिस। मैं यहां पर इतना कहना चाहती हूं कि जो अधिकारी इन्विटेशन काडर्ज छपवाते हैं, उन अधिकारियों के ऊपर भी समय आने पर गाज़ गिरेगी जो मुख्य मंत्री के साथ चेयरमैंनों के नाम छापते हैं। पट्टिकाओं के ऊपर भी उन चेयरमैंनों के नाम लिखे जा रहे हैं। आप मुझे यह बताईये कि यह सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है। माना कि मैं कांगड़ा के 13 निर्वाचन क्षेत्रों में एक अकेली भाजपा की विधायक हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारे नियम आप ताक पर रख दें। जो काम 70 परसेंट पूरे हो चुके हैं, उनके माननीय मुख्य मंत्री शिलान्यास के फटे लगा रहे हैं और

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी ।

15.03.2016/1540/RKS/AS/1

श्रीमती सरवीन चौधरी द्वारा... जारी

मुख्य मंत्री जी अभी यहां पर बैठे नहीं है, मैं उनसे यह कहना चाहूंगी कि हाल ही में मैंने दो पुल तैयार करवा दिए हैं। ये पुल जब मैं पिछली सरकार में मंत्री थी उस समय के सैंक्शन थे। ये पुल बंदला नाला और झूलार नाला पर हैं, मोर्च घड़गूं जहां पर 374 लाख रुपए के पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं अगर आप बीच में वहां जाएं तो वहां पर भी अपना फट्टा लगाकर के आएं । शाहपुर में विधायक प्राथमिकता के साथ इस तरह से भेदभाव हो रहा है। यह सदन मुझे आज बताएं कि विधायक प्राथमिकता में विधायक को पूछना तो दूर की बात है परन्तु अपने चेहतों के नाम लिखवाना कहां तक उचित है? 3 वर्षों में पानी की स्कीमज, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग में कुछ काम नहीं हुआ है। स्कूल और बाकि चीजों को तो आप छोड़ दीजिए। यह सारे काम हमारे कहने से तो होंगे ही नहीं । प्लानिंग ऑफिसर को भी उन कॉलमों को निकाल देना चाहिए जिस पर काम नहीं होता। कम-से-कम आपके यहां बिजली पानी, सड़कों का तो ध्यान रखा जाता होगा। परन्तु हमारे यहां पर 3 वर्षों में कुछ भी काम नहीं हुआ है। कांग्रेस गवर्नमेंट is at zero in Shahpur. अध्यक्ष महोदय, किसी को तो हिमाचल निर्माता के नाम से जाना जाता था। यह सब जानते हैं कि हिमाचल के निर्माता डा0 यशवन्त सिंह परमार जी हैं। यह सब जानते हैं कि पानी वाला मुख्यमंत्री कौन था, सड़कों वाला मुख्य मंत्री कौन है और आज के मुख्य मंत्री जी को शाहपुर में फट्टों वाला मुख्य मंत्री कहा जाता है। मैं यह नया नाम देना चाहती हूं। फट्टों वाले मुख्य मंत्री जी को विपक्ष के विधायकों का भी ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हिमाचल की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। अध्यक्ष,मैं एक अंतिम लाइन कहना चाहूंगीः

"समय बहा के ले जाएगा नाम और निशान इनके,

कोई हम में रह जाता, कोई अहम में रह जाता है॥"

15.03.2016/1540/RKS/AS/2

इसलिए अहम और हम को कम करें। आपके पास समय कम है, आपकी सरकार की छुट्टी होने वाली है। इसलिए जो आपके पास समय बचा है उसको अच्छे कामों में लगाओ। इस बजट का मैं बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूं। अध्यक्ष जी आपने समय दिया, आप हमारे कांगड़ा क्षेत्र से हैं, हमें समय दे दिया करें, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः हमारे पास केवल 75 मिनट हैं और बोलने वाले अभी 10 वक्ता हैं। आप नहीं बोलना चाहते हैं तो अपना समय किसी दूसरे वक्ता को दे दीजिए। इसमें परेशानी यह है कि जो बाकि लोग बोलने वाले हैं उनको भी समय चाहिए। You are not the only person कि आपको स्पेशली ज्यादा समय दिया जाए। आप सदन में फैसला कर लो जैसे आपकी सहमति होगी मैं, उस तरह से सदन को चला दूंगा। But I don't have to shout at you.

15.03.2016/1540/RKS/AS/3

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों पर आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है उसे मुझे विकासोन्नमुख बजट कहते हुए भी कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा बजट में हर वर्ग का चाहे वह किसान हो, बागवान हो, कर्मचारी हो, बेरोजगार हो या युवा हो सबका ख्याल रखा गया है। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सामाजिक सुरक्षा पैंशन को अगले 5 वर्षों में 450 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए बढ़ाने का वायदा किया था। परन्तु माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी के कुशल नेतृत्व में इस लक्ष्य को केवल 3 वर्षों में ही पूरा कर लिया गया। जो कि अपने आप में एक सराहनीय कदम है।

श्री एस.एल.एस द्वारा जारी

श्री बलबीर सिंह वर्मा ...जारी

माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में 80 वर्ष की आयु से अधिक के बुजुर्गों को बिना किसी आय सीमा के सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 1100 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपया किया गया है जो कि एक अद्भुत कदम है। इसी तरह 70 वर्ष की आयु से अधिक के अपंग व्यक्तियों को पैंशन भी बिना किसी आय सीमा के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 1100 रुपये की है जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने सत्ता संभालते ही बेरोजगार युवकों को कौशल विकास भत्ता योजना प्रारंभ की और इस योजना के अंतर्गत पिछले 3 वर्षों में लगभग एक लाख युवा लाभान्वित हुए हैं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की इस लोकप्रिय सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पिछले 3 सालों में लगभग 4 लाख से अधिक स्मार्ट कार्ड वितरित किए हैं ताकि गरीब व बेसहारा लोग स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का पूर्ण लाभ उठा सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्य मंत्री महोदय व सरकार के अथक प्रयासों से हिमाचल के जिला चम्बा, हमीरपुर तथा सिरमौर में 3 नए चिकित्सा महा विद्यालय स्वीकृत हुए हैं जो कि अपने आप में एक सराहनीय कदम है।

पिछले 3 वर्षों में माननीय राजा साहब की सरकार ने राजीव गान्धी अन्न योजना के अंतर्गत राज्य के 37 लाख लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की है जिन्हें 3 किलोग्राम गेहूं दो रुपये की दर से एवं 2 किलो चावल तीन रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हर महीने प्रदान किए जा रहे हैं। सभी BPL परिवारों को सस्ते दामों पर 35 किलोग्राम राशन प्रति माह दिया जा रहा है जो कि अपने आपमें एक उदाहरण है।

अध्यक्ष महोदय, राजा साहब की सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पिछले 3 वर्षों में लगभग 1000 से अधिक नए स्कूल खोले या स्तरोन्नत किए। इसी तरह पिछले 3 वर्षों मे सरकार द्वारा 28 नए डिग्री कॉलेज खोले गए। साथ ही फाईन

आर्ट कॉलेज भी खोला गया ताकि प्रदेश के युवा इस क्षेत्र में भी ज्यादा-से-ज्यादा लाभ उठा सकें।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह 130 से अधिक नए स्वास्थ्य संस्थान या तो खोले गए या उनका दर्ज़ा बढ़ाया गया ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों में 24 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या आई.टी.आई. तथा दो नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं ताकि गरीब-से-गरीब बच्चे भी इनमें ट्रेनिंग लेकर रोज़गार कमा सके।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दैनिक दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 180 से बढ़ाकर 200 रुपये की गई है जो कि अपने आपमें एक उदाहरण है।

राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने पिछले 3 वर्षों में 7 राजस्व सब-डिविजन तथा 31 तहसीलें व उप-तहसीलें प्रदेश के दूर-दराज व बैकवर्ड एरिया में खोली हैं ताकि लोगों को राजस्व से संबंधित कार्य के लिए दूर न जाना पड़े। यह कार्य भी राजा साहब ने लोकहित में किए हैं जो कि अपने आपमें सराहनीय कदम हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 2016-17 के बजट में प्रत्येक विधायक को उनके विधान सभा क्षेत्र में विकास योजनाओं के अनुमोदन के लिए विधायक क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.00 करोड़ रुपया किया गया है जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इसी तरह स्वैच्छिक अनुदान राशि को 4.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 5.00 लाख रुपया किया है जिसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से राजा साहब का आभार प्रकट करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजा साहब के कुशल एवं प्रभावशाली नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों में कृषकों को विभिन्न प्रकार की योजनाओं में लाभ पहुंचाए गए हैं जिसके फलस्वरूप कृषकों की मेहनत को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है तथा

जनवरी 2016 में प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिसमें एक करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है जो कि प्रदेश के लिए गौरवपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 2016-17 के बजट में एक नई योजना मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना को चलाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत कृषको बाड़ लगाने के लिए 7 परसैंट तक सहायता दी जाएगी जो कि अपने आपमें बहुत ही बड़ा कदम है जिसके लिए राजा साहब ने 2016-17 के बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार में यह योजना गरीब कृषकों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और कृषक लोग अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचा सकेंगे।

जारी ...श्री गर्ग जी

15/03/2016/1550/RG/DC/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा-----क्रमागत

अध्यक्ष महोदय, राजा साहब ने बजट 2016-17 के अन्तर्गत पशु-पालकों के लिए एक नई योजना 'उत्तम चारा उत्पादन योजना' के नाम से शुरू की है जिसमें पशु-पालकों को चारा व भूसा काटने के लिए बेहतर उपकरण खरीदने पर 50% उपदान देने का प्रावधान किया है जोकि गरीब पशु-पालकों के लिए भविष्य में एक बड़ी राहत होगी।
अध्यक्ष महोदय, माननीय राजा साहब द्वारा खेतीहरों के लिए वर्ष 2016-17 के बजट में जैविक खेती करने के लिए एक नई योजना 'एकीकृत विस्तृत कार्य योजना' का प्रावधान किया है। इससे खेतीहरों, बागवानों को जैविक खेती करने में सहायता मिलेगी और वे अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने में सक्षम होंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 2016-17 के बजट में कृषकों को 'राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना' को चालू रखते हुए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है जोकि एक स्वागत योग्य कदम है। इसमें कृषकों को 80% सब्सिडी प्राप्त होगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राजा साहब द्वारा वर्ष 2016-17 के बजट में सेब एवं आम की फसल पर 'Weather Based Crop Insurance Scheme' को जारी रखते हुए 15 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है जोकि लोगों के लिए फायदेमंद है। मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से राजा साहब का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह आगामी सात वर्षों में विश्व बैंक द्वारा 1,115 करोड़ रुपये से वित्तपोषित 'हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना' को कार्यान्वित करने के लिए भी मैं व्यक्तिगत रूप से राजा साहब का तहेदिल से आभारी हूं और इसके साथ ही राजा साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने कृषकों और बागवानों को पॉवर स्प्रेयर, पॉवर टिलर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2016-17 के बजट में प्रावधान किया है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा आवारा पशुओं को आश्रय तथा चारा प्रदान करने के लिए गैर सरकारी संस्थाओं एवं पंचायतों को वर्तमान में गौ-सदनों को सुदृढ़ करने तथा नए गौ-सदन के लिए जो आवाहन किया है वह अत्यन्त

15/03/2016/1550/RG/DC/2

महत्वपूर्ण है जिससे न केवल गौ की रक्षा होगी बल्कि आवारा पशुओं से कृषकों की खेती बचाने में भी बड़ी सहायता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राजा साहब द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या पर गौर करते हुए एक नई योजना का आरम्भ करने की घोषणा की गई है और जो पंचायत आवारा पशुओं से पूर्णतः मुक्त होगी, उसको 'पंचायत पशुधन पुरस्कार योजना' के अन्तर्गत पांच लाख रुपये का ईनाम दिया जाएगा जोकि अपने आप में एक स्वागत योग्य कदम है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों में माननीय मुख्य मंत्री के मार्ग-दर्शन से खुले में मलविसर्जन मुक्त करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है तथा सरकार के प्रयासों से मार्च, 2017 तक खुले में मलविसर्जन मुक्त करने हेतु 'स्वच्छ हिमाचल, सुन्दर हिमाचल' को पाने में हम सक्षम होंगे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वर्ष 2016-17 से 'मुख्य मंत्री आवास योजना' के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है जिसमें सामान्य वर्ग के बी.पी.एल.

परिवारों को भी सम्मिलित किया है और वर्ष 2016-17 में 25 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। वर्ष 2016-17 में ही विभिन्न आवास योजनाओं में 97 करोड़ रुपये की लागत से 12,000 आवासों का निर्माण किया जाएगा जोकि अपने आप में सराहनीय कदम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2016-17 के बजट में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी क्रमवार बढ़ौत्तरी की गई है और बजट में इसके लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जोकि अपने आप में स्वागत योग्य कदम है।

अध्यक्ष महोदय, राजा साहब ने वर्ष 2016-17 के बजट में जिस भी कृषक की फसल खराब होती थी उसको 50% के स्थान पर 33% किया गया है अर्थात अब 50% फसल क्षतिग्रस्त होने के स्थान पर 33% फसल के खराब होने पर मृत व्यक्तियों के परिवारों को डेढ़ लाख रुपये की जगह चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी जिसके लिए मैं राजा साहब का धन्यवाद करता हूं।

15/03/2016/1550/RG/DC/3

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं कि विधान सभा सदस्य यानि विधायक प्राथमिकता के अन्तर्गत भी अब हैण्ड पम्प लगवा सकते हैं और माननीय मुख्य मंत्री ने इसके लिए वर्ष 2016-17 के बजट में 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है जोकि अपने आप में स्वागत योग्य बात है।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और

एम.एस. द्वारा जारी

15/03/2016/1555/MS/AG/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी---------

प्रदेश के दूर-दराज़ के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक अहम भूमिका है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह भी बहुत ही

सराहनीय कदम है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां शून्य उत्सर्जन वाली बिजली की बसें चलेंगी, जिससे हिमाचल का पर्यावरण साफ-सुथरा रहेगा, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभारी हूं। प्रदेश के सभी बस अड्डों में राजा साहब की सरकार द्वारा बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसके लिए अगले वित्त वर्ष में 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभारी हूं कि वर्ष 2016-17 के लिए "मुख्य मंत्री सड़क योजना" नामक एक नई योजना का प्रावधान किया गया है जिससे गांव-वासियों को अंतिम छोर तक सड़क से जोड़ना आसान हो जाएगा और अगले वित्त वर्ष हेतु 50 करोड़ रुपये के आबंटन के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष जी, सरकारी स्कूलों में अभी तक केवल 10वीं तक की कक्षा के विद्यार्थियों को ही वर्दी प्रदान की जा रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी का आभारी हूं कि इन्होंने नये वित्त वर्ष में "मुख्य मंत्री वर्दी योजना" नामक नई योजना का प्रावधान किया है जिसके अंतर्गत जमा दो के 1 लाख 34 हजार विद्यार्थियों को वर्दी प्रदान की जाएगी। माननीय राजा साहब आपके इस कदम से गांव के गरीब लोगों को बहुत फायदा मिलेगा।

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर के मेलों की अनुदान राशि को क्रमशः 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार, 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख और एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का बजट में प्रावधान किया है, यह भी स्वागत योग्य है।

15/03/2016/1555/MS/AG/2

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय राजा साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि राज्य के सभी व्यक्तियों को सस्ती तथा न्याय-संगत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए इन्होंने "हिमाचल प्रदेश युनिवर्सल हैल्थ प्रोटैक्शन स्कीम"
का वर्ष 2016-17 के बजट में प्रावधान किया है जिससे हिमाचल अपने सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।

इसी तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने आयुर्वेद संस्थानों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु 250 करोड़ रुपये का प्रावधान नये वित्त वर्ष में किया है जोकि स्वागत योग्य है।

राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने जुलाई, 2015 से "बेटी है अनमोल योजना" के अंतर्गत पहली से जमा दो तक पढ़ने वाली कन्याओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है जोकि स्वागत योग्य है। इसी तरह से "मुख्य मंत्री कन्यादान योजना" के अंतर्गत पहले विवाह अनुदान तभी दिया जाता था यदि वर हिमाचली हो। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बजट में प्रावधान किया है कि यदि हिमाचली लड़की किसी बाहर के राज्य के लड़के से विवाह करती है तो भी उसे अनुदान दिया जाएगा तथा अनुदान राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये किया गया है। यह भी बहुत ही काबिले-तारीफ है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष जी, राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशनों में सी0सी0टी0एन0एस0 लागू करने वाला हिमाचल देश का प्रथम राज्य बन गया है जिसके लिए राजा साहब धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह से राजा साहब के प्रयासों से राज्य में शिमला के समीप राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, यह भी बहुत ही काबिले तारीफ है।

15/03/2016/1555/MS/AG/3

मैं माननीय राजा साहब का गृह रक्षकों के दैनिक मानदेय को 280/-रुपये से 350/-रुपये करने के लिए भी धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरे चौपाल चुनाव क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में बहुत सारी नई योजनाएं स्वीकृत की हैं जिनमें बहुत सारे अस्पताल, तहसीलें, स्कूल, थाने, ट्रांसपोर्ट डिपो और अभी हाल ही में होमगार्ड की कम्पनी भी इसी बजट में हमें दी है। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने हमें

अग्निशमन केन्द्र का भी चौपाल के लिए प्रबंध किया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का समस्त चौपाल की जनता की तरफ से दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से,

अध्यक्षः माननीय सदस्य जल्दी समाप्त कीजिए। आपने बहुत समय ले लिया है।
श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष जी, अभी मुझे बोलते हुए सिर्फ 16 मिनट हुए हैं।
अध्यक्षः बाकी माननीय सदस्यों ने भी तो बोलना है।

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मेरा चुनाव क्षेत्र बहुत ही दूर-दराज़ वाला चुनाव क्षेत्र है और वह क्षेत्र बहुत वर्षों से विकास की दृष्टि से वंचित था।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

15.03.2016/1600/जेएस/एजी/1

श्री बलवीर सिंह वर्माः----**जारी**-------

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा कि बहुत सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं और बहुत सारे कार्य अभी हमारे अधूरे हैं, जिसके लिए मैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि नेरवा और चौपाल में हॉस्पिटल के लिए जो बिल्डिंग्ज बननी है वे जल्दी से जल्दी उन दो हॉस्पिटल की बिल्डिंग्ज बनें। सी0एच0सी0 कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर, कुपवी में जिसकी बिल्डिंग बननी है वह भी जल्दी से जल्दी बनें। पी0एच0सी0 झीना, पी0एच0सी0 नोराबोरा, पी0एच0सी0 गुम्मा, पी0एच0सी0 देवत, पी0एच0सी0 बम्टा, पी0एच0सी0 बसाधार और पी0एच0सी0 पुलवाल की जो बिल्डिंग्ज बननी है वे भी जल्दी से जल्दी बनें। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि जो हमारे चुनाव क्षेत्र के लिए जो सैंज से फिरेज़पुल के लिए सड़क जा रही है वह बहुत ही तंग है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अभी हाल ही में उसके लिए पैसे दिए हैं। 10 किलोमीटर डबल लाईन के लिए दिए हैं। मैं आग्रह करूंगा कि उसको सेंज से फिरेजपुल तक 90 किलोमीटर के लिए एक मुश्त पैसे का प्रावधान किया जाए। उसमें जो लैंड है वह पहले से ही पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग में 20 किलोमीटर लगी हुई है। उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर माननीय मुख्य मंत्री

जी उसके लिए जल्दी से जल्दी प्रावधान करेंगे तो जो हमारे दूर-दराज़ क्षेत्रों में बहुत सारी एक्सिडैंट्स होते हैं और जो वह हमारी सड़क है बहुत ही तंग है उसको ठीक करने से उसमें एक्सिडैंट नहीं होंगे। मैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जो हमारे 66 के0वी0 लाश्टाधार और देवत में बन रहा है उसको प्रोग्रैसिव किया जाए क्योंकि हमारे वहां बिजली की बहुत समस्या है। जैसे ही हमारे वहां बर्फ गिरती है,जैसे ही हमारे वहां बरसात में तूफान आता है, उससे पूरे चौपाल चुनावक्षेत्र में बिजली बन्द हो जाती है। उसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस 66 के0वी0 को कम्पलीट किया जाए और साथ ही साथ जो 33 के0वी0 कुपवी में जो कि अंडर कन्स्ट्रक्शन है उसको भी जल्दी से जल्दी कम्पलीट किया जाए। हमारे नेरवा में ट्रांसपोर्ट डिपू माननीय राजा वीरभद्र सिंह और आदरणीय श्री बाली जी ने दिया है

15.03.2016/1600/जेएस/एजी/2

उसके लिए वहां बसें तो मिल गई हैं मगर उन बसों को रखने का हमारे पास प्रावधान नहीं है। उस बस अड्डे का जल्दी से निर्माण किया जाए। नेरवा कॉलेज की बिल्डिंग बहुत सालों से अधूरी है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने हाल ही में अभी 4 करोड़ रूपए का प्रावधान किया था फिर भी वह बिल्डिंग कम्पलीट होने के लिए उसमें और पैसे की जरूरत है। मैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी उसको पूरा करने के लिए उसके लिए पैसे का प्रावधान किया जाए। हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग सराहां में है वह बिल्डिंग 20 साल पहले जली थी आज तक वह स्कूल प्राईवेट बिल्डिंग में चल रहा है। उसको भी जल्दी से जल्दी बनाने का प्रावधान किया जाए। चौपाल में एक नया कॉलेज वर्ष 1998 में माननीय मुख्य मंत्री ने दिया था। उसके बाद जो गवर्नमैंट आई उसने उस नोटिफिकेशन को विद्ड्रा किया। मैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि चौपाल कॉलेज को जल्दी से जल्दी दिया जाए। उप-तहसील नेरवा को तहसील बनाया जाए। बी0डी0ओ0 ऑफिस कुपवी में दिया जाए। थानादेहा में दिया जाए। एक पी0एच0सी0 हमें बलगहार में मिलनी चाहिए। मेरी दो पंचायतें ऐसी हैं जो किरन और टिल्लर है जो कि उत्तरांचल के बॉर्डर में है वहां पर अभी तक हमारे रास्ता भी नहीं है, सड़क तो बहुत दूर। मैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जो किरन और

टिल्लर पंचायतें हैं जहां पर अभी तक एक भी फुट सड़क नहीं बनी हुई है उन दोनों पंचायतों में जल्दी से जल्दी सड़क का प्रावधान किया जाए। उसकी डी0पी0आर0 बन गई है। लोगों ने उसके लिए गिफ्ट डीडज़ दे दी है। अब सिर्फ एफ0सी0ए0 केस बनना है। एफ0सी0ए0 का केस जल्दी से जल्दी बनाने का प्रावधान किया जाए।

हसरतों को दिल में दबाकर जीते हैं राजा साहब,

आप गरीबों को हसांकर जीते हैं, ज़माना क्या लूटेगा खुशियां आपकी,

आप खुद अपनी खुशियां दूसरों पर लूटा कर जीते हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

15.03.2016/1600/जेएस/एजी/3

अध्यक्षः अब श्री महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया आप संक्षेप में बोलें। थोड़ा बोलें लेकिन बढ़िया बोलें।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जब बीच में घण्टी बजती है तब दिल के तार टूट जाते हैं। इसलिए 15 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा ज्यादा से ज्यादा लगेंगे तो 18 मिनट लगेंगे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

15.03.2016/1605/SS-AG/1

श्री महेश्वर सिंह क्रमागतः

अध्यक्ष महोदय, जो वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस माननीय सदन में 8 मार्च, 2016 को रखे हैं, मैं आपकी अनुमति से उसके सन्दर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से योजना का आकार बढ़ा है और पिछले वर्ष की तुलना में 400 करोड़ रुपया अधिक है। लेकिन एक चिन्ता का विषय है कि ऋण बढ़ता जा

रहा है। 2015 में यह ऋण बढ़कर 35.51 करोड़ रुपया हो गया। दूसरी बात, मैं आरम्भ में कहना चाहूंगा, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह जी ने इस सदन में किया। यह जो लमसम प्रोविजन की प्रवृत्ति है यह निरन्तर बढ़ती जा रही है और यह स्वस्थ परम्परा नहीं है। जब बजट अनुमान में सारी स्कीमों का उल्लेख आता है तो यह जानना हमारा अधिकार है कि हमारी अमुक योजना पर कितने रुपये खर्च होंगे और कभी-कभी यह जो लमसम योजना की प्रवृत्ति है यह एक किस्म से ऐच्छिक निधि के रूप में बांटी जाती है। इसलिए मैं सरकार के वित्त मंत्री/मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रवृत्ति को रोक कर कहीं इमरजैंसी में लमसम प्रोविजन रखना है तो वह समझ में आता है। जब ये (श्री महेन्द्र सिंह) मंडी के आंकड़े दे रहे थे तो शायद यह भूल गये कि कुल्लू भी उसी जोन का अभिन्न अंग है। अगर आपको मार लगी है तो निश्चित रूप से हमको भी लगी है। इसलिए मैं इस बात का विरोध करता हूं।

महोदय, जहां तक विधायक की विकास निधि का संबंध है निश्चित रूप से उसको 75 लाख रुपये से एक करोड़ रुपया करना सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और जो हमारी ऐच्छिक निधि है उसमें भी वृद्धि हुई है। अब वह पांच लाख हो गई, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

महोदय, फूड गारंटी की बात कही गई है और उसमें 210 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, आपको भी स्मरण होगा कि पिछली बार जब यह चर्चा हो रही थी तो मैंने आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाया था कि हमारे कई दुर्गम क्षेत्र हैं। वहां खाद्य की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको डिपो तक पहुंचाने का किराया सरकार वहन करती है। क्या कारण है कि जो दुर्गम क्षेत्र हैं न तो वहां

15.03.2016/1605/SS-AG/2

गैस एजैंसी है और मेरे क्षेत्र में ऐसे-ऐसे गांव हैं जैसे कि रसोल, ग्राण, मलाणा इत्यादि जहां पर भरी हुई सिलैण्डर के 400 रुपये लगते हैं अगर पीठ पर उसको उठाना पड़े। क्या हमको इस प्रकार की सुविधा घरद्वार तक मिलने का अधिकार नहीं है? उस वक्त मंत्री जी ने कहा था कि आने वाले वर्ष से पहले इन दुर्गम क्षेत्रों में गैस एजैंसी खुल जायेगी। सारे में तो छोड़ दीजिये एक भी गैस एजैंसी नहीं खुली। कहीं नहीं खुली। फिर कैसी सुविधा आई है, ये पैसे किस चीज़ पर खर्च हुए हैं, यह समझ में नहीं आता।

पैरा-21 से 34 तक किसानों को दी जाने वाली सुविधा की चर्चा है। महोदय, एक बात की प्रसन्नता है कि सरकार/मुख्य मंत्री जी ने एक बात को स्वीकार किया है कि जहां किसान आज मौसम में तबदीली को झेलता है, प्राकृतिक आपदाओं को झेलता है वहां अगर सबसे बड़ा नुकसान उसकी फसल को कोई चीज़ पहुंचा रही है तो वह जंगली जानवर और आवारा पशु पहुंचा रहे हैं। इस बात को इन्होंने स्वीकार किया है कि जो अब तक के कार्यक्रम हुए कि वे इतने काफी नहीं हैं कि इस पर नियंत्रण हो सके। उन्होंने एक बात कही है, मैं उस बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि जहां तक ये आवारा पशु हैं यह लोगों की अपनी पैदा की हुई समस्या है। सही मायने में हिमाचल में कहीं आवारा पशु नहीं हैं। लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए उन पशुओं को बेसहारा कर दिया जो आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। निश्चित रूप से गौसदन आज की आवश्यकता है। जो आवारा हो चुके हैं उसके लिए तो गौसदन एक प्रावधान हो सकता है

जारी श्रीमती के0एस0

15.03.2016/1610/केएस/एएस/1

श्री महेश्वर सिंह जारी----

लेकिन आगे से पशु आवारा न हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? निश्चित रूप से समय आ गया है कि पशु धन की भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जन्म और मृत्यु के रजिस्टर बनने चाहिए और जो व्यक्ति इसका अनुसरण न करें उसको सजा होनी चाहिए, जुर्माना होना चाहिए । यह आवश्यक है, जैसे कहा गया कि पशु गोदे जाएंगें, आईडैंटिफिकेशन बन जाएगी और जो पंचायत इस प्रकार के गोदने में और अपनी पंचायत को आवारा पशुमुक्त करने में सफल होगी, प्रति ब्लॉक उनको सम्भवतः पांच-पांच लाख रु0 ईनाम दिया जाएगा, यह एक अच्छी योजना है। जहां तक करंट छोड़ने की बात कही है, 60 प्रतिशत अनुदान देने की बात कही कि किसान अपने खेत में बाड़ लगाए, यह भी स्वागत योग्य निर्णय है लेकिन वह करंट कितना हो, उसको नियंत्रित करने की जरूर आवश्यकता हो क्योंकि ऐसा न हो कि वे बेचारे उसी में फंस कर मर जाए। यह टैक्नीक है और यह नई विधि है, इसका मैं स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पैरा-23 में बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन हेतु 80 करोड़ रु0 तक रखे गए हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उन्नत किस्म के बीज मिलते हैं लेकिन जो इनको देने की वर्तमान प्रक्रिया है, लोग बेचारे डिप्टी डायरैक्टर के ऑफिस में जाते हैं, वे कहते हैं कि नहीं ब्लॉक में जाओ। ब्लॉक में कृषि विभाग का व्यक्ति बैठा है, वह देगा लेकिन जब वहां जाते हैं तो ताला लगा हुआ मिलता है इसलिए मेरा सुझाव है कि जब सरकार ने सब्जी मण्डियों का निर्माण किसानों के लिए किया है, क्यों नहीं वहीं कृषि विभाग का एक व्यक्ति बैठता ताकि किसानों को वहीं पर बीज उपलब्ध हो जाए? यह सारा घपला इसलिए होता है कि कमजोर वर्ग के लिए 50 प्रतिशत सबसिडी इसमें है इसलिए वे ताला लगाकर भाग जाते हैं। मुझे इस बात की आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस पर जरूर अमल होगा।

अध्यक्ष महोदय, आगे मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि सब्जी मंडियों में नए यार्ड बनेंगें। यहां पर सम्बन्धित सी.पी.एस. महोदय बैठे हैं, नोट कर लें लेकिन जितनी

15.03.2016/1610/केएस/एएस/2

अंधेर नगरी इनकी सब्जी मण्डी में है, वह कहीं और नहीं मिलेगी। आनन्द है, सरकार का पैसा वहां किस बेदर्दी से खर्च होता है, इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। मार्किट कमेटी के चेयरमैन मज़े से घूम रहे हैं । सभी नियमों को ताक पर रख कर काम करते हैं। क्या सरकार सोई हुई है? क्या इस बात पर अभी तक आपने कोई नोटिस नहीं लिया? अध्यक्ष जी, मैंने आपसे आग्रह किया है कि इस पर नियम 130 के अंतर्गत बड़ी चर्चा करेंगे ताकि सारी बातें आपके समक्ष आएं। पैरा-24 में चारा उत्पादन की बात कही गई है। अच्छी बात है और चारा उत्पादन के लिए 5 करोड़ रु0 रखे गए हैं जिसमें 50 प्रतिशत सबसिडी है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा संख्या -42 में कहा गया था वन विभाग द्वारा हैक्टेयर में उन्नत किस्म के चारे का पौध रोपण किया जाएगा। इसके साथ यह भी कहा गया कि 1300 हैक्टेयर भूमि पर जो लेंटीना घास है, इसको उखाड़ दिया जाएगा। इसके लिए 13 करोड़ का प्रबन्ध होगा। हम जानना चाहते हैं कि कहां पर वह घास उखाड़ा गया? यह तो भगवान ही जानता है क्योंकि इस माननीय सदन के सभी सदस्य उससे अनभिज्ञ हैं। कहां पर वह चारा लगा, वह भी भगवान ही जानें। कहीं ऐसा न हो, होते-होते यह देश भी

बिहार की तरह चारे के घोटाले में फंस जाए। इसलिए इस बात के पूरे आंकड़े यहां पर आने चाहिए और मैं तो अध्यक्ष जी से निवेदन करुंगा कि यहां पर कोई न कोई समिति बनाकर भेजनी चाहिए । कहीं ऐसा न हो कि जैसे बिलासपुर में कल बताया गया कि पेड़ का सर्वाइवल रेट 75 से 80 प्रतिशत तक है। अगर बिलासपुर जैसे सूखे क्षेत्र में 80 प्रतिशत है तो हमारे क्षेत्र में जहां बर्फबारी होती है वहां तो 120 प्रतिशत होना चाहिए। यह सत्य से दूर की बात कही गई है जिसकी छानबीन करना आवश्यक है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

15.3.2016/1615/av/as/1

श्री महेश्वर सिंह------- जारी

कृषकों के लिए पोलीहाउस की बात कही गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले साल जो बर्फबारी और वर्षा हुई उसमें हमारे दुर्गम क्षेत्रों में लगे सारे-के-सारे पोलीहाउसिज तबाह हो गये। यहां पर बैठे ग्रामीण विकास मंत्री जी मेरी बात पर सहमति प्रकट कर रहे हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। मगर एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसने बीमा करवाया हो और उसको एक भी पैसा मिला होगा, यहां पर कृषि मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। जिन्होंने बीमा करवाया था उसको भी कुछ नहीं मिला तथा जो प्राकृतिक आपदा की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से पैसा आया उसके अंतर्गत भी किसी पोलीहाउस के लिए पैसा नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस बारे में हमारी तरफ छानबीन कर लें। पैरा संख्या 31 पर पावर स्प्रेयर और पावर टिल्लर पर सब्सिडी देने का प्रावधान है जिसको आगे भी जारी रखेंगे। मगर मैंने देखा है कि जो इस पावर टिल्लर को चलाना नहीं जानता उसके लिए यह घातक सिद्ध हो रहा है। पहले कृषि विभाग उनको पावर टिल्लर चलाना सिखाने का कोई प्रबंध करें। कई अपनी टांगे तोड़कर बैठ गये और अब क्लचिज पर चल रहे हैं। बाकी इस पर जो सब्सिडी की बात है तो पिछले साल जितने भी पावर टिल्लर दिए उसके लिए कुल्लू जिला में अभी तक एक को भी अनुदान नहीं मिला है। सब्सिडी पार्ट के लिए ऐनश्योर कीजिए कि वह समय पर मिलना चाहिए। पैरा संख्या 31 से 38 तक नये गोसदन खोलने की चर्चा की गई है। मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं इस पर पहले ही बोल चुका हूं। अगर आपकी अनुमति हुई तो जब नियम 130 के अंतर्गत इस पर

चर्चा का अवसर मिलेगा तो उस समय चर्चा करेंगे। मैं यहां पर ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पैरा संख्या 48 में कहा गया है कि बी0पी0एल0 सूची से अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने हेतु विशेष अभियान चलाया जायेगा। मगर जब कल इस बारे में प्रश्न आया था तो ग्रामीण विकास मंत्री जी ने माननीय मुख्य मंत्री की इस घोषणा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि यह तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सर्वे हो चुका है। मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात

15.3.2016/1615/av/as/2

पर पुनः विचार करें। आप इसके लिए स्पैशल अदालत बनाइए। जो आप कहते हैं कि एस0डी0एम0 के पास जाओ, वह डेट देते हैं और उनके ऑफिस में आने-जाने का इतना किराया लग जाता है कि बी0पी0एल0 परिवार अपने कान पकड़कर भाग जाता है। इसलिए यह होना चाहिए और इसकी आवश्यकता है। पैरा संख्या 54 में शहरी विकास विभाग के अंतर्गत अमृत योजना का सूत्रपात करने की बात कही गई है। यह योजना अटल जी के नाम से शुरू हुई है तथा यह भारत सरकार की योजना है। इसमें न केवल शिमला म्युनिसिपल कार्पोरेशन बल्कि इस योजना के अंतर्गत कुल्लू शहर भी आया है और वहां पर पहली किस्त पहुंच गई है जिसके लिए मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

पैरा संख्या 60 में भूमिहीनों / गृहहीनों को भूमि देने की बात कही गई है मगर इस बात को सुनते-सुनते दो साल बीत गये हैं। अभी तक एक भी भूमिहीन और गृहहीन को जमीन नहीं मिली। कहा गया कि इस साल अंतिम रूप दिया जायेगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे ताकि ऐसे लोगों को इनसाफ मिले और वे अपना आशियाना बना सके। यहां पर एक बात कही गई है और मैं इसका स्वागत करता हूं। जहां पर गृह निर्माण के लिए अनुदान देने का प्रावधान है इसमें मुख्य मंत्री जी ने एक ऐडिशन की है कि जो सामान्य वर्ग के लोग है उनको भी अब लम्प्सम प्रोविजन रखा है ताकि उनको भी लाभान्वित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त विद्युतीकरण की बात की गई है। सारा सदन इस बात को जानता है कि जितने लकड़ी के पोल लगे थे तथा जितने ट्रांसफॉर्मर ऑगमैंट होने हैं तथा जो आपकी सप्लाई तार है; इन सब चीजों की ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्गति है।

टी सी द्वारा जारी

15.03.2016/1620/TCV/DC/1

श्री महेश्वर सिंह--जारी।

एक तार पर 4-4 मीटर जोड़े हुए हैं और कभी-कभी आग भी लग रही है। इसलिए यह आवश्यक है और इसमें इस बार प्रावधान किया गया है लेकिन एक बात आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कि जहां तक ये छोटी-छोटी चीजें कंडक्टर,तार और मीटर वायर,खरीदने का सवाल है, जब 3-3 जगह जोन बने हैं और आपके चीफ इंजीनियर बैठे हैं तो इसको सैंट्रेलाईज क्यों किया है। बिजली विभाग में कोई भी ठेकेदार जाने को तैयार नहीं है क्योंकि मैटेरियल मांगते-मांगते उसकी टांगे थक जाती है। कहते हैं कि ऊपर से अभी आना है। यहां तक कि एक मफ़ होता है, जिसमें पोल खड़ा किया जाता है। अगर मफ़ तक खरीदने की नीचे पॉवर नहीं हैं तो यह पैसा कैसे युज़ होगा। इसलिए जब आपने वहां इंजीनियर्ज रखे हैं तो उन पर विश्वास करिए। यहां पर रेट कांट्रैक्ट करिए और फिर वह खरीदेंगे। अध्यक्ष महोदय, पैरा- 85 से 89 तक में लोक निर्माण विभाग का जिक्र किया गया है। अब लोक निर्माण विभाग में मैंने पिछली बार भी एक बात कही थी कि निश्चित रूप से सड़कों की लम्बाई बढ़ी है लेकिन गुणवत्ता घटी है और उस गुणवत्ता की जब मैंने चर्चा की थी तो मुख्य मंत्री जी धर्मशाला सैशन में नाराज हो गये थे। लेकिन मुझे प्रसन्नता है जब वह मंडी के दौरे में गये और जब बल्ह की हालत देखी तो तब उन्होंने कहा कि जो इसके लिए जिम्मेवार है, उसको डिमोट कर दूंगा। अगर एक्सियन है तो एस0डी0ओ0 बना दूगां और अगर एस0डी0ओ0 है तो जे0ई बना दूंगा। यह कहना पड़ा क्योंकि सड़कों की हालत सचमुच दयनीय है। एक अच्छा स्टैप सरकार ने लिया है, कहा है कि एक अधिकारी को क्वालिटी कंट्रोल को देखने के लिए नियुक्त किया है। भगवान करें कि जो अभी का मापदण्ड है, मैटलिंग, टारिंग, सोलिंग उसमें वृद्धि करें। आज तो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें भी ऐसी हो गई है, जहां ट्रैफिक जाम नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात इस सैशन के प्रारम्भ

में हमने प्रश्न के माध्यम से उठाई थी कि जो ये फोरलेन का काम हो रहा है या जो विभिन्न कंपनियां केबल ले कर रही है, इन्होंने इस सड़क का सर्वनाश कर दिया है तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि पीछे गलती की होगी और यहां से निर्देश दिए थे कि अब 250 मीटर से ज्यादा नहीं खोदा जाएगा। पहले उसको ठीक किया जाएगा फिर अगला 250

15.03.2016/1620/TCV/DC/2

मीटर खोदा जाएगा। लेकिन अब तो 250 मीटर के स्थान पर अढ़ाई-अढ़ाई किलोमीटर खोद दिया है और सड़कों की बुरी हालत हो गई है। जो सड़कों से जाते हैं उनको पता है। एक और सदन की जानकारी के लिए कहूंगा मैंने पता किया और उन्होंने कहा कि जो सड़कें उखड़ेगी, उसका मुआवज़ा मिलेगा और सड़कें ठीक होगी। आपकी जानकारी के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सरकार ने एग्रीमेंट दे दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में हम यह सुविधा चाहते हैं और सड़क की रिपेयर हम खुद करेंगे। फिर वह पैसा कहां से आएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा जब वह जवाब देंगे तो इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें उखड़ी है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? महोदय, आपने मुझे समय दिया अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात आई0एंडपी0एच0 मिनिस्ट्र ने कही थी कि बजट है सब कुछ है, मैं मानता हूं। लेकिन जो विभाग का स्वास्थ्य है वह ठीक नहीं है। जिस विभाग में फिटर न हो, जिसमें पलम्बर न हो तो विभाग कैसे चल रहा है। एक जल रक्षक की बात आई थी आपके माध्यम से मैंने यही मंत्री जी से पूछा था मंत्री जी यह जल रक्षक जो होगा वह तो आई0एंडपी0एच0 विभाग का नहीं होगा। वह तो पंचायत का है। वह तो रैंच चलाना जानता नहीं है, वह पानी क्या ठीक करेगा? तो उन्होंने कहा कि महेश्वर जी अभी तक तो मेरी समझ में भी नहीं है कि वह क्या करेगा? शायद अब समझ में आ गया हो। क्या माननीय मंत्री जी उसके कार्य से संतुष्ट है? मेरा सुझाव रहेगा कि आप कोई रैंच घुमाने वाला बैलदार/फिटर दे दीजिए और जो यह जल रक्षक है, इनको कम्पलैंड अटेंडेट रखिए। ताकि विभाग की शिकायतें दर्ज करें और उसमें ये सक्षम होंगे और फिर निश्चित रूप से पंचायतें इनको पैसे देगी। इस तरह का परिवर्तन करना होगा।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी ।

15.03.2016/1625/RKS/DC/1

श्री महेश्वर सिंह द्वारा... जारी

अन्यथा पानी की स्कीमें नहीं चलेगी। गर्मी आ रही है, पीने के पानी के लिए इस बार बुरी हालत होने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

15.03.2016/1625/RKS/DC/2

अध्यक्षः श्री कुलदीप कुमार जी।

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, आज आपने अंततः मुझे समय दे ही दिया।

अध्यक्षः धीरज का फल मीठा होता है।

श्री कुलदीप कुमारः आगे- आगे देखिए कितना मीठा होता है। 8 मार्च, 2016 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी का यह 19वां बजट है। इस बजट में उनके तजुर्बे का प्रतिबिम्ब सामने नजर आता है। जो उनका as a Finance Minister पुराना तजुर्बा है उससे हिमाचल की जनता को फायदा हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने लगभग साढ़े तीन घंटे का मिरकल बजट पेश किया । यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुख्य मंत्री जी में अभी भी इतना स्टैमना है कि अगले दस सालों के लिए भी आपको पटखनी जरूर लगाएंगे। मैंने कई सालों से कई बजट सुने हैं, पढे हैं। परन्तु यह बजट बहुत शांत और संतुलित पेश हुआ है। इसमें जो शेयर-शायरी की बात है, एक शेयर से सम-अप होता है

"कह दो अंधेरों से कहीं ओर घर बना लें,

हिमाचल प्रदेश में रोशनी का सैलाब आया है।"

हिमाचल प्रदेश में रोशनी का सैलाब आया है। आपको यह सैलाब नजरी नहीं आएगा। क्योंकि आपकी आंखों की रोशनी हमें लाना पड़ेगी। शायद आपके आंखों की रोशनी कम हो गई होगी। उसका भी हमको इंतजाम करना पड़ेगा। इस बजट में हर वर्ग का चाहे वह मजूदर, किसान, महिला या नौजवान वर्ग है, सब वर्गों के लिए यह बजट रोशनी लेकर आया है। हिमाचल प्रदेश की जनता इससे खुश है माननीय प्रतिपक्ष के नेता जो मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, इस बजट में उनको कोइ कंक्रीट

15.03.2016/1625/RKS/DC/3

आलोचना नहीं मिली है। इन्होंने केवल आलोचना के लिए आलोचना की है। इस बजट पर शायद ये भी एक-डेढ़ घंटा बालें, पर उसमें मुझे इनका कोई कनक्रीट जवाब या सुझाव नजर नहीं आया।

श्री एस.एल.एस द्वारा जारी

15.03.2016/1630/SLS-AG-1

श्री कुलदीप कुमार ...जारी

एक-दो सुझाव उन्होंने ज़रूर दिए। वह चाहे पुलिस की बात थी या उनकी सैलरी की बात थी। उसके बाद वरिष्ठ सदस्य माननीय महेन्द्र सिंह जी और हमारी बहन, महिला सदस्य सरवीन चौधरी जी बजट पर बोलते-बोलते क्रिकेट के ऊपर चले गए। जब यहां बजट की चर्चा हो रही है तो उसमें क्रिकेट कहां से जा गई? क्रिकेट में इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। ये भूल गए कि माननीय अनुराग ठाकुर ने ही एक बार कहा था कि बम्ब और बॉल एक साथ नहीं चल सकते। बाद में उनको पता नहीं क्या हो गया कि जब पाकिस्तान और इंडिया का टी-20 मैच आया तो उनकी स्टेटमैंट बदल गई। अब पता नही बीच में क्या बात हुई जबकि यह उनकी अपनी स्टेटमैंट थी।...(व्यवधान)... वह भी इंटरनेशनल सीरिज की ही बात थी। ...(व्यवधान)... वर्ल्ड कप की बात है तो वह हो रहा हैं। इस समय यहां पर शहीदों के सम्मान की बात थी। आपने माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए कहा कि प्रदेश को पीछे ले गए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश का मान-सम्मान बढ़ाया है। मुझे अफसोस है कि मेरी बहन सरवीन जी भी एक फौजी अधिकारी की धर्मपत्नी है, इनके पति ब्रिगेडियर हैं

लेकिन इन्होंने भी शहीदों के सम्मान की बात नहीं की। हमारे शहीदों के ऊपर गोलियां चली और नौजवान शहीद हुए। मैं कल NDTV पर चर्चा सुन रहा था। इनके एक MP कीर्ति आजाद जी हैं। वह क्रिकेट जगत से आते हैं। ...(व्यवधान)...वह आपके MP हैं। आप वर्तमान की बात करो। ...(व्यवधान)...अब आपको क्या तकलीफ़ हुई? उन्होंने स्वयं कहा। फिर हिमाचल से बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो पूर्व मुख्य मंत्री रह चुके हैं, श्री शांता कुमार जी ने भी इसका विरोध किया। सबसे पहले उनके विरोध करने की बात है। लेकिन जहां तक कीर्ति आजाद जी की बात है, उन्होंने कहा कि एक तरफ तो पाकिस्तान हमारे नौजवानों पर गोली चला रहा है, दूसरी तरफ क्या हम मैच में तालियां बजाएंगे? यह शोभा नहीं देता। इस बात को आप भूल रहे हैं। एक तरफ हमारे नौजवान गोलियों से शहीद हो रहे हैं जबकि दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि वहां पर मैच में चौको-छक्कों पर तालियां बजाई जाएं। यह कैसे हो सकता है? खासकर अगर फौजियों की बात हो।...(व्यवधान)...अब आपको

15.03.2016/1630/SLS-AG-2

किस बात की तकलीफ़ हुई? जब आप बोल रहे थे, उस समय मैं नहीं बोला। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने शहीदों का मान-सम्मान रखा है और माननीय मुख्य मंत्री ने हिमाचल का भी मान-सम्मान रखा है। इनकी एक सहयोगी पार्टी शिव सेना ने भी माननीय मुख्य मंत्री की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि ऐसे देशभक्त होने चाहिए जिन्होंने हिमाचल और देश का मान-सम्मान रखा है। बात यही नहीं है। एक ओर हमारी दुशमनी चल रही है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम एक-दूसरे के साथ खेल खेलें, यह ठीक नहीं लगता। हमारी बहन सरवीन चौधरी जी बड़ी वरिष्ठ सदस्य है। उन्होंने कहा कि यह बजट महिला विरोधी है।

जारी ...श्री गर्ग जी

15/03/2016/1635/RG/AG/1

श्री कुलदीप कुमार-----क्रमागत

मैं बहिन जी से पूछना चाहता हूं कि ये पहले अपने केन्द्र के मोदी सरकार के बजट को जाकर देखें, उसमें महिलाओं के ब्यूटी पार्लर पर भी टैक्स लगाया गया है। अब केन्द्र सरकार महिला विरोधी है, वहां के बारे में तो ये बोलीं नहीं। यहां तो महिलाओं के लिए काफी योजनाएं चलाई हैं। इसलिए वहां जाकर आप कहिए कि महिला विरोधी तो केन्द्र सरकार है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बात कही, मुझे बहुत दुःख हुआ क्योंकि ये यहां पर बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी जो छठी बार मुख्य मंत्री बने हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता उनको हिमाचल निर्माता मानती है। पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास उनके नेतृत्व में हुआ। लेकिन इन्होंने उनको फट्टू बोल दिया। यह इनको शोभा नहीं देता, ये मंत्री रह चुकी हैं और इस सदन की वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्रीमती सरवीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरी स्पीच क्यों कोट कर रहे हैं इन्हें अपना भाषण देना चाहिए। कृपया मुझे भी बोलने दीजिए।

श्री कुलदीप कुमार : अब मेरा समय है, आप बोल चुकी हैं, अब मेरा समय है। जब ये बोल रही थीं, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने इनको कोई डिसटर्ब नहीं किया।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, क्या कोई ऑब्जेक्शनेबल प्वाइंट है?

श्रीमती सरवीन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इनके बाद मुझे भी बोलने का समय दीजिए।

श्री कुलदीप कुमार : हिमाचल की जनता मुख्य मंत्री को हिमाचल के निर्माता के रूप में मानती है। इनको तो उनका आभारी होना चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया इनको डिसटर्ब न करें, इनको बोलने दें, नहीं तो समय ज्यादा लगेगा। ये जो मरजी बोलें--(व्यवधान)----

15/03/2016/1635/RG/AG/2

श्री कुलदीप कुमार : चलिए, इनको ज्यादा तकलीफ हो रही है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी स्पीच कॉन्टीन्यु रखिए।

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में इस सरकार को बधाई देता हूं। इनके कुशल नेतृत्व में अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश को 'गुड गवर्नेन्स' में सैकण्ड प्राईज मिला है इसके लिए तो ये तालियां बजा दें। आप भी बजा दो, हिमाचल प्रदेश भी आपका है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी एवं इस सरकार को बधाई देता हूं। प्रदेश में वर्ष 2012-13 में पर-केपिटा इनकम 98,996/-रुपये थी जो वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में बढ़कर 1,30,067/-रुपये हो गई है। यह एक गुड गवर्नेन्स की बात होती है। इसके अलावा वर्ष 2014-15 में हमारे प्रदेश के हालात ऐसे थे, परन्तु विपरीत परिस्थितियों के मुताबिक प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया जिससे प्रदेश को मिलने वाला 3000 करोड़ रुपये खत्म हो गया। उसके बावजूद भी वर्ष 2016-17 में हमारी वार्षिक योजना 5200 करोड़ रुपये की माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश को दी है जो कि पिछले साल से 400 करोड़ रुपये अधिक है।

एम.एस. द्वारा जारी

15/03/2016/1640/MS/AG/1

श्री कुलदीप कुमार जारी---------
इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। इसके साथ-साथ जो गुड गवर्नेंस की बात है। जो राष्ट्रीय वृद्धि दर है, वह 7.6 प्रतिशत है लेकिन हिमाचल प्रदेश की वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत है। यह भी सरकार के कुशल नेतृत्व की बात है। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 में जो पिछला घाटा 12.69 करोड़ रुपया आ रहा था, वह अब क्लोजिंग में भी 12.69 करोड़ रुपये का ही आ रहा है। यह बड़ी कुशलता की बात है कि घाटा बढ़ा नहीं है बल्कि वही घाटा आगे कैरी फारवर्ड हुआ है।

यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कहा कि रेवड़ियां बांटी गईं और कुछ ने कहा कि पैसा कहां से आएगा? आपको पैसे की बहुत चिन्ता है। वह पैसा तो पेज-64 के ऊपर सामने लिखा हुआ है कि व्यय किए गए प्रति 100रुपये पर सैलरी में 28.98, पैंशन पर 12.89 और ब्याज पर 10.43, लोन रि-पेमैंट के ऊपर 6.84 तथा डवलपमैंट पर 40.86 प्रतिशत है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट को सारे वर्गों ने सराहा है। हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां पर लगभग 90 प्रतिशत लोग कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं। मेरे साथी माननीय सदस्य हर बजट सत्र में चर्चा लाते थे कि बंदरों, आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। यहां तक कि हमारे बहुत से किसानों ने फसल बीजना ही छोड़ दिया था और खेत बंजर पड़ गए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने "मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना" इस प्रदेश के लिए चलाई। किसान पहले इनसे बहुत दुःखी थे और यहां तक कहते थे कि जो सरकार इसका प्रबंध करेगी, वह सरकार दूसरी बार सत्ता में आ जाएगी। अब मुख्य मंत्री जी ने बंदरों का भी इंतजाम कर दिया, आवारा पशुओं का भी इंतजाम कर दिया और जंगली जानवरों का भी इंतजाम कर दिया है। अब आप दुबारा उसी तरफ बैठेंगे और सरकार दुबारा पांच साल के लिए सत्ता में आएगी।

यहां पर बाड़ लगाने के लिए (घण्टी) बजट में आवारा पशुओं तथा बंदरों के लिए बाड़ लगाने की बात की गई है और बाड़ लगाने के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है जोकि बहुत ही सराहनीय बात है। मुझे

15/03/2016/1640/MS/AG/2

बहुत दुःख हुआ जब माननीय नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात का विरोध किया कि यह कोर्ट का मामला हो जाएगा और दूसरे सदस्यों ने भी विरोध किया। शायद आपको यह जानकारी नहीं है कि वैसे तो तारों के पास जंगली जानवर जाते ही नहीं हैं लेकिन यदि तारों में करंट दिया गया हो और बंदर को इसका पता लग जाए तो सारे बंदर वहां से भाग जाते हैं। बंदर उन तारों के नजदीक भी नहीं आते हैं। हमारे यहां कई जगह लोगों ने तारें लगाई हुई हैं और उनमें करंट भी छोड़ा हुआ है। मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि अब सरकार ने 60 प्रतिशत सब्सिडी बाड़ लगाने के लिए दी है जोकि बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए किसान लोग भी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ एक "पंचायत पशुधन पुरस्कार योजना" चलाई है जिसके तहत जो दो पंचायतें ऐसी होंगी जहां पर कोई आवारा पशु नहीं होंगे, उनको 5-5 लाख रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। यह भी बहुत ही सराहनीय योजना है। इसके अलावा "वाई0एस0 परमार किसान स्वरोजगार योजना" के अंतर्गत पॉली हाउस लगाने की बात है और उसमें 111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह भी बहुत ही अच्छी बात है। हमारे गांव के कई नौजवानों ने पॉली हाउस लगाए हुए हैं जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ी है और उनका जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ है, यह भी सराहनीय कार्य है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

15.03.2016/1645/जेएस/एएस/1

श्री कुलदीप कुमारः-----जारी------

राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत जो छोटे-छोटे किसान जिनको सिंचाई की जरूरत होती है। फसलों को बीजने के लिए सिंचाई की बहुत जरूरत होती है। उसके लिए यहां पर 50 प्रतिशत सबसिडी का प्रावधान किया है। बोरवेल, लघु एवं मध्यम उठाऊ सिंचाई योजना, सतही कुओं एवं सतही बोरवेल, स्टोरेज़ टैंक के लिए, जल प्रवाह योजनाओ तथा पानी ढुलाई पाईप के लिए योजना इन सब के लिए 50 प्रतिशत सबसिडी का प्रावधान किया गया है। बहुत ही सराहनीय पग उठाया है। मैं, हैरान हूं, मेरी बहन, श्रीमती सरवीन चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि हमारे शाहपुर के साथ भेदभाव हो रहा है। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने 75 लाख से एक करोड़ रूपए विधायक निधि कर दी। आपने उसका भी धन्यवाद नहीं किया। आपने किसी में भी धन्यवाद नहीं किया। बहन सरवीन, शाहपुर से कहां भेदभाव हो गया? आपको भी एक करोड़ रूपया मिल रहा है। सबके साथ बराबर का मिल रहा है। आपके साथ कहां पर भेदभाव हो गया? सरवीन जी आप 40 मिनट तक बोली हैं और मैं भी 40 मिनट ही लूंगा। इसमें खास बात यह है कि हेंडपम्प लगाने के लिए भी विधायक निधि में शामिल किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन मेरे दोस्तों की ऐच्छिक निधि माननीय मुख्य मंत्री ने बढ़ाई, उसका भी इन्होंने धन्यवाद नहीं किया। उसको पांच लाख कर दिया और कोई धन्यवाद नहीं किया। पंचायत राज इन्स्टिच्युशन के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं,

उनका भी मान-सम्मान रखा गया। जिला परिषद के चेयरमैन का 6500 रूपसे से बढ़ा कर 8000 रूपये किया गया और वाईस चेयरमैन का 4500 से बढ़ा कर के 6000 रूपया किया गया। पंचायत समिति के चेयरमैन का 3500 से 5000 रूपये किया गया और वाईस चेयरमैन का 2400 से 3500 रूपये किया गया। प्रधानों का भी 2100 रूपये से 3000 रूपये किया गया और उप-प्रधानों का 1800 रूपये से 2200 रूपये किया गया। इसके लिए 1549 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया। इसके साथ-साथ लोकतंत्र को मजबूत करने

15.03.2016/1645/जेएस/एएस/2

के लिए जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए 130 करोड़ रूपए का बजट में प्रावधान किया गया। यह भी एक बहुत ही सराहनीय कदम माननीय मुख्य मंत्री जी ने उठाया है। मुख्य मंत्री आवास योजना में एक बहुत ही खास चीज़ है, जिसकी ये तारीफ भी नहीं कर पाए, पहले इंदिरा आवास योजना और राजीव गांधी आवास योजना चलती थी जिसमें शड्यूल कॉस्ट ओ0बी0सी0 के लिए और शड्यूल ट्राईब के लिए मकान मिलते थे। लेकिन अब प्रावधान किया गया है कि जनरल केटेगरी के जो बी0पी0एल0 के लोग होंगे उनको भी इसमें मकान मिलेंगे। यह भी एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिया है। इसके साथ-साथ मुख्य मंत्री वर्दी योजना का जो प्रावधान किया गया है उसके अंतर्गत प्लस-टू के बच्चों को भी वर्दी देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री का धन्यवाद करता हूं। टैक्निकल ऐजुकेशन जिसकी कि बहुत ही जरूरत है जिसमें टैक्निकल ऐजुकेट लोग हों इसके लिए भी 204 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। पैंशन योजना, जो कि एक सामाजिक सेवा है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

15.03.2016/1650/SS-DC/1

श्री कुलदीप कुमार क्रमागतः

सामाजिक सेवा के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी जाने जाते हैं। पहले 450 रुपये पैंशन होती थी, हमारे घोषणा पत्र में था कि 600 रुपये करेंगे, हमने तीन सालों से पहले-पहले वह 600

रुपये की और फिर 650 रुपये की। उसके बाद 70 परसैंट विकलांग और 80 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको 1100 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये पैंशन देने का प्रावधान किया। 45 वर्ष से कम उम्र की जो महिला विधवा होगी, जिसके एक या दो बच्चे होंगे, उनके लिए भी 1200 रुपये पैंशन देने का प्रावधान किया। जहां तक मजदूरों की बात है, मजदूरों के लिए दिहाड़ी बढ़ाई गई। उसे 180 रुपये से 200 रुपये किया गया और अब उनको पक्का करने की बात है। कर्मचारियों को एक जुलाई, 2015 से 6 परसैंट डी0ए0 देने का प्रावधान किया है। यहां मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए कुछ नहीं किया है। पंजाब और हरियाणा में 5 हजार और साढ़े 7 हजार रुपया आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। मेरे पास उनकी मांग आई है इसलिए उनके लिए भी इस बजट में कुछ-न-कुछ प्रावधान किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर बोल कर वाइंड अप कर रहा हूंः-

"छूं न सकूं आसमां तो कोई बात नहीं,
मुख्य मंत्री ने तो हिमाचल की जनता के दिलों को छू लिया है यह क्या कम है।"

यह बजट बहुत शानदार है। मजदूरों, किसानों और नौजवानों के हित का बजट है, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

15.03.2016/1650/SS-DC/2

अध्यक्षः श्रीमती सरवीन चौधरी जी, आप क्या बोलना चाहती हैं?

श्रीमती सरवीन चौधरीः अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मान्यवर कुलदीप जी ने मेरा नाम लेकर दो-तीन टिप्पणियां की हैं। फिर संजय जी नाराज़ हो जाते हैं कि ऐसा मत बोला करो। मेरे यहां पर 22 साल के बाद दोबारा रैस्ट स्टेडियम का फट्टा लग गया। मैं आज कुछ ज्यादा कड़वा नहीं बोली। अब 22 साल के बाद फट्टा लग गया और मैंने फट्टे वाला मुख्य मंत्री कह दिया तो आपको क्या ऑब्जैक्शन हुआ?

दूसरा, आपने कमैंट किया कि फौजी परिवार से है। मेरा पति, ब्रिगेडियर पवन कुमार एक इंफैंटरी सोल्जर है। फौज में उन्होंने इंफैंटरी में पूरी नौकरी की है वे भगौड़े नहीं

हैं दूसरों की तरह कि उन्होंने सर्विस पूरी की नहीं की। कलकत्ता में जाकर भी उनको (सत्तापक्ष को) मैच का विरोध करना चाहिए था अगर मैच का विरोध करना था। उन्होंने सिर्फ हिमाचल में विरोध किया। मैंने कहा कि एक सैनिक पूरे भारतवर्ष का होता है, वह एक गांव का नहीं होता है। आपने केवल वहां पर राजनीति की है। आपके तो चिन्तपुरनी तक होटल बुक थे। कितना नुकसान हुआ है इस मैच के न होने से? इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। आपने कभी इस बारे सोचा? आपने बड़ी तारीफों के पुल पिछले और अब के कार्यकाल के बांधे।

मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि यहां बजट एश्योरैंस की वैबसाइट है। स्पीकर साहब कहते हैं कि हमारे यहां ई-विधान हो गया। ई-विधान का क्या फायदा हुआ? अगर आप हिमाचल की बजट एंश्योरैंस की वैबसाइट पर जाएं तो वह खाली है। उसमें आज HPPLANNING.NIC.IN को चैक करना, उसमें एक भी पिछली एश्योरैंस सरकार की नहीं है और आगे सब्जबाग दिखा रहे हो, आप धन्यवाद कर रहे हो। अगर हमारी स्पीच पर कांग्रेस के लोग कटाक्ष करेंगे तो हम उसका डबल जवाब देना जानते हैं। इसलिए आप हमारी बातों पर कटाक्ष ज़रा ध्यान से सोच-समझ कर करना।

जारी श्रीमती के0एस0

15.03.2016/1655/केएस/डीसी/1

श्रीमती सरवीन चौधरी जारी----

हमें पता है हमारी जिम्मेदारी देश के लिए क्या है और सेना में क्या रही।

अध्यक्षः यह बहस कभी खत्म नहीं हो सकती। कुलदीप कुमार जी, अब काफी हो गया, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं सारे सैनिकों का सम्मान करता हूं और ब्रिगेडियर साहब का भी सम्मान करता हूं। मैंने कभी किसी फौजी को अपशब्द नहीं कहे। मैं सभी का सम्मान करता हूं। सरवीन चौधरी जी, आप अपनी मर्जी से जो बोलना चाहें, बोल लें लेकिन मैं सभी का सम्मान करता हूं।

15.03.2016/1655/केएस/डीसी/2

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, 8 मार्च, 2016 को इस माननीय सदन में मुख्य मंत्री जी ने अपना बजट भाषण दिया। यह बजट भाषण युवा विरोधी, किसान विरोधी, मज़दूर विरोधी, बागवान विरोधी, कर्मचारी विरोधी, अनुसूचित जाति- जनजाति विरोधी, महिला विरोधी, समाज के हर वर्ग का विरोधी बजट है। अभी मुझसे पहले श्रीमान कुलदीप कुमार जी, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, इनका जो बजट भाषण था, उसकी एक विशेषता रही वह यह रही कि वे इस माननीय सदन की महिला सदस्य श्रीमती सरवीन चौधरी जी को समर्पित रहा। इन्होंने अपना पूरा बजट भाषण बार-बार मेरी बहन सरवीन कहां है, सरवीन कहां है, थोड़ी देर बाद सरवीन जी जब बाहर से अंदर आ गई तो इनको लगा कि महिला सदस्य से पंगा ठीक नहीं लिया। अध्यक्ष महोदय, आज इनके बजट भाषण के बाद कुछ नई-नई जानकारियां भी हमें मिली। इन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने 19वां बजट पेश किया और इस साल का जो बजट है, ऐसा तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था तो फिर वर्ष 2013-14 और वर्ष 2014-15 में आप क्या बालते रहे? इन्होंने एक और बात कही, आज तक हम बचपन से जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमको एक बात बताई जाती थी कि हिमाचल के निर्माता डॉ0 यशवन्त सिंह परमार जी हैं। आज हमारी नॉलेज और बढ़ गई क्योंकि इन्होंने हमें एक और बात बताई कि हिमाचल के निर्माता राजा वीरभद्र सिंह जी है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक मिनट बैठिए। अभी पांच बज गए हैं। क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय बढ़ाया जाए या कल बोलेंगें? अभी दस आदमी और बोलने को हैं?

संसदीय कार्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, एक घण्टा बढ़ाने की पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति बनी है ।

अध्यक्षः ठीक है, अब इस माननीय सदन की बैठक आधे घण्टे के लिए अपराह्न 5.30 बजे तक बढ़ाई जाती है।

15.03.2016/1655/केएस/डीसी/3

श्री गोविन्द सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, अपनी बात प्रारम्भ करने से पहले लोकतंत्र पर इस देश के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि :

शासन के यंत्रों पर रखो आंख कड़ी,

छिपे अगर हों दोष उन्हें खोलते चलो,

प्रजातंत्र का क्षीर प्रजा की वाणी है,

जो कुछ हो बोलना अभय बोलते चलो

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

15.3.2016/1700/av/ag/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर------- जारी

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पर अभय होकर बोलने का रिवाज है क्योंकि मुख्य मंत्री जी यहां पर बात-बात पर भड़क जाते हैं। आगे रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि

प्रजातंत्र का वह जन असली मीत सदा टोकता जो शासन को,
लोकसत्ता को वह गाली है संगीत जो विरोधियों के मुख से झरती है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप भी थोड़ा सुनने की आदत डाले। इस माननीय सदन में अनेक विषयों पर चर्चा हुई है। यहां पर मुख्य मंत्री जी ने पैरा संख्या 5 में कहा है कि

मुझे जीना था जितना अपनी खातिर जी लिया मैंने,
जियूं देव भूमि की खातिर दिल में ये अरमान जिन्दा है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी बोले तो बोले पर बड़ी देर से बोले। इस प्रदेश के 6 बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं तथा दो बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और अब जाकर कहते हैं कि अब तक तो जिया अपने लिए लेकिन अब जियूंगा देव भूमि के लिए।

केंद्र सरकार नीति आयोग ने हिमालय पर्वतीय प्रदेशों की सभी केंद्रीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं को 90:10 के अनुपात से वित्त पोषित करने का निर्णय लिया है। मैं इसके लिए नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त आज की अखबारों में खबर छपी है कि नरेन्द्र मोदी की सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन के तहत दी जाने वाली संशोधित पेंशन राशि जो सर्विस और विकलांगता पाने वालों को ऐसे 2,21,224 पूर्व सैनिकों को उनके खाते में पहली मार्च को जमा करवा दी है। साथ में, यह भी कहा कि पारिवारिक पेंशन पाने वाले 1,46,355 पूर्व सैनिकों की बकाया राशि इस

15.3.2016/1700/av/ag/2

मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में जमा करवा दी जायेगी। इसके लिए हम नरेन्द्र मोदी जी के बहुत-बहुत धन्यवादी हैं। आपने आज इसके साथ एक और समाचार पढ़ा होगा। केंद्र सरकार ने यह कहा है कि देश में ट्रक ड्राइवर्ज के केबिन में अब ए0सी0 लगेगें ताकि ऐक्सिडैंट न हो। इस प्रकार केंद्र सरकार ने उन छोटे तबके के लोगों के बारे में भी सोचा है।

इस मान्य सदन में अनेक विषयों पर चर्चा हुई। मैं यहां पर पूरे प्रदेश की बात न करते हुए केवल कुल्लू-मनाली की बात करूंगा। मालूम नहीं कि मुख्य मत्री जी कुल्लू-मनाली के साथ सदा ही सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं। आज सुबह मैं किसी विषय पर बोल रहा था और उसका हिसाब-किताब तो हम कल चुकता करेंगे। यहां पर मुख्य मंत्री जी खड़े होकर बोले जिन 2000 टैक्सी ऑपरेटर्ज की यह सदस्य बात कर रहा है यह उसमें अपने आप पार्टी है। मैं पर्यटन नगरी से सम्बंध रखता हूं। हम इस सरकार से एक प्रश्न पूछते हैं कि आप भून्तर एयरपोर्ट का विस्तार कैसे करेंगे? भून्तर एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए हमारे लोक सभा के सांसद ने केंद्र सरकार को पूछा कि इसको बनाने के लिए कितनी धनराशि

खर्च होगी। केंद्र सरकार ने यह कहा कि जितना भी पैसे लगे हम देंगे लेकिन भूमि अधिग्रहण का कार्य तो प्रदेश सरकार को करना है।

(सभापति महोदया, श्रीमती आशा कुमारी पदासीन हुई।)

टी सी द्वारा जारी

15.03.2016/1705/TCV/AG/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर----- जारी।

आपने मेरे क्वैश्चन के उत्तर में कहा है कि वर्तमान में वहां 86 एकड़ जमीन है। इसके अतिरिक्त अगर बोइंग-180 सीटर उतारना है तो 350 बीघा भूमि और लगेगी, जिसमें 250 बीघा निजी भूमि लगेगी और 70 बीघा सरकार भूमि लगेगी। भूमि अधिग्रहण का जो धन है, वह प्रदेश की सरकार को देना है लेकिन प्रदेश की सरकार की कुल्लू-मनाली के लिए देने की मंशा नहीं है। इस तरह यह काम भी हमारा लेट होता जा रहा है। एक पर्यटक नगरी होने के नाते हमारी कुल्लू से मनाली सड़क पर्यटन का सीज़न प्रारम्भ होने वाला है। उसकी हालत खराब है हम लैफ्ट बैंक सड़क की बात करते हैं। आपने जवाब दिया कि यह 39 किलोमीटर लम्बी सड़क है। इसमें 13 कलवर्ट है और इसको डबल लेन करना है, लैंड एक्वाजिशन के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। लेकिन जितना भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में काम हुआ था उसके आगे आप कोई भी काम बढ़ा नहीं पाये हैं। सभापति महोदया, मनाली में टूरिज्म कौंसिल है। टूरिज्म कौंसिल के दोनों ओर टूरिज्म बैरियर है। सभापति महोदय, मैं एक बात आपके माध्यम से इस सदन में और कहूंगा। सरकार के मंत्री बैठे हैं, मुझे लगता है कि कुछ विषय तो वह हैं जिनके बारे में हम हमेशा बोलते हैं क्या लगता है कि सरकार के मंत्री और अधिकारी केवल मात्र सुनते हैं या जो इस मान्य सदन में हम कहते हैं क्या वह नीचे तक इंप्लीमैंट होता है? हमने एक बात कही थी कि हमारे लैफ्ट बैंक और राईट बैंक के दोनों ओर ग्रीन टैक्स बैरियर हैं। राईट बैंक का ग्रीन टैक्स बैरियर आलू ग्राउंड में है और लैफ्ट बैंक का प्रीणी में है लेकिन दोनों को वहां से बदले जाने की आवश्यकता है ताकि खुली जगह मिले और जो ग्रीन टैक्स बैरियर आपको प्रतिवर्ष करोड़ों रूपये की आय देते हैं, उन ग्रीन टैक्स बैरियर के पास ही सड़क की सबसे

खराब हालत है। यह भी कहा गया था कि ग्रीन टैक्स बैरियर के पास हिमाचली आर्कीटेक्ट के दो बहुत बड़े सुन्दर बैरियर बनेंगे। लेकिन उस दिशा में नही, ये बैरियर क्लॉक्स/जगतसुख से नीचे खुली जगह में बनने चाहिए। हिमाचल आर्कीटेक्ट के मुताबकि वहां पर अच्छा सुन्दर भव्य गेट बनना चाहिए था। दूसरी, बात यह ग्रीन टैक्स का जो पैसा है, इसके बारे में हाईकोर्ट ने कहा है कि यह बैरियर के ऊपर खर्च होगा। सड़क की हालत खराब है और पैसा पड़ा है, आप उस पैसे को खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहा था कि एक प्रयोग करो।

15.03.2016/1705/TCV/AG/2

लैफ्ट बैंक और राईट बैंक में प्रतिवर्ष एक किलोमीटर सी0सी0 करके देखो और अगर यह प्रयोग सफल होता है तो उसके दाएं-बाएं के क्षेत्र को भी सी0सी0 किया जाये ताकि सब जगह पर्यटकों को सुविधा मिले। मनाली नगर में माल रोड का शिलान्यास तत्कालीन मुख्य मंत्री प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने किया था, अब माल रोड बनकर तैयार हो गया। हमने कहा था कि पैसा हमारे पास है, मनाली नगर की सारी गलियां भी हिमाचल के लोकल पत्थरों से पक्का कर दो। सभापति महोदया, सीवरेज की बात करते हैं। मैं यहां पर वह बात कहूंगा जो मैं कहता हूं, बल्कि जो मुख्य मंत्री जी की घोषणाएं हैं। मुख्य मंत्री वर्ष 2013 में आए और यह कहा कि अब मनाली में आर्दश गांव से लेकर आलू ग्राउंड तक और लैफ्ट बैंक से जगतसुख तक इस सारे क्षेत्र को सीवरेज से जोड़ेंगे। 115 करोड़ रूपये की डी.पी.आर. हमने बनाकर तैयार कर दी है। दो साल से डी0पी0आर0 तैयार है, मुख्य मंत्री जी की घोषणा है लेकिन अब तक सरकार उसके लिए पैसों का प्रबंध कर नहीं पा रही है और वर्तमान में जो आपका सीवरेज का सिस्टम है, अभी 50 परसेंट सीवरेज की कनेक्टिविटी है तब् भी डबल भर चुका है। जब तक उसका प्रबंध नहीं होगा तो क्या होगा, उसके लिए पैसा आ नहीं रहा है। वही स्थिति कुल्लू और भुंतर शहर की है, जहां 30 परसेंट कनेक्टिविटी है। जब तक सरकार यह पैसा उपलब्ध नहीं करवाएंगी तब तक यह होने वाला नहीं है। मुख्य मंत्री भी अपनी घोषणाओं पर अमली-जामा पहना नहीं पा रहे हैं। एक प्रश्न मेरा और था कि मनाली के अन्दर जो कुड़ा संयत्र है, उसकी स्थिति क्या है? आपने जवाब दिया सन् 2000 में प्रारम्भ हुआ था और

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी ।

15.03.2016/1710/RKS/AS/1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर द्वारा... जारी

दूसरा कूड़ा संयत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। सन् 2000 से 2016 तक कितनी आवादी बढ़ गई, इसको बनाने की आवश्यकता क्यों नहीं है? कुल्लू जिला के अंदर प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी के समय में हम पोलिटेक्निक कॉलेज लेकर आए, नवोदय स्कूल लेकर आए। इस सरकार को भी प्रयास करना चाहिए की कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हमें मिले। हमने एक बात यह कही थी कि पर्यटन विभाग के नाम 15 मील में 113 बीघा भूमि है। कुल्लू-मनाली में जमीन की कमी है। हम किसी प्रोजैक्ट के विरोध में नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुल्लू, लाहौल-स्पिति, पांगी व भरमौर क्षेत्र तक जब कहीं रोड़ बंद होते हैं या अन्य कोई दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए हमें मैडिकल कॉलेज दिया जाए। हम इस मान्य सदन में हमेशा कहते थे कि इस भूमि को बचाकर रखो। जब आवश्यकता होगी तो यह भूमि मैडिकल कॉलेज के लिए प्रयोग की जाएगी। लेकिन सभापति महोदया, मुख्य मंत्री और मुख्य मंत्री जी के चंद चाटूकार लोगों के कारण आज वहां पर कुछ और बन रहा है। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। लेकिन कल आप कहेंगे कि भूमि कहां मिलेगी ?

वर्तमान में रोपवे के संबंध में मेरा प्रश्न था। एक रोपवे मैटिरियल पासेंजर रोपवे है। दुआरा गांव से लेकर मेहा और गवाड़ तक उसको बनाया जाना आवश्यक है। सभापति महोदया, जिस रोहतांग रोपवे की बात हम कर रहे हैं, वर्ष 2013 में इस मान्य सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अगर स्थानीय जनता इसके विरोध में है तो मैं इस रोपवे को बनने नहीं दूंगा। 15 दिन के बाद यह कैबिनेट में भी कैंसिल हो गया। मैं पलचान-रोहतांग रोपवे का विरोधी नहीं हूं। सभापति महोदया, मैं यह चाहता हूं कि वह भी बनें लेकिन उससे पहले वशिष्ट से भृगु जो रोहतांग से ज्यादा सुंदर जगह है, वहां से चन्द्रखणी, हमटा इन सबको क्यों नहीं शुरू किया जाता? जिसके कारण हजारों स्थानीय लोगों कि रोजी रोटी पर एकदम असर न पड़े। आपने कहा है कि पलचान से लेकर रोहतांग रोपवे का हमने टैंडर कॉल किया

15.03.2016/1710/RKS/AS/2

है। एक पार्टी आई और उसी पार्टी को आपने अवार्ड कर दिया। हमने कहा कि क्या ऐसे काम से पहले आप जन सुनवाई करते हैं? कहते हैं पहले सारी एन.ओ.सी., सारे काम हो जाएं उसके बाद जन सुनवाई करेंगे। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोग कोओपरेटिव सोसाइटिज बनाकर इन कामों को स्वयं भी तो कर सकते हैं। क्या आपने इसके लिए प्रयास किए? लेकिन कोई प्रयास नहीं किया गया। मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि सारे काम चौपट है, सब काम रूके पड़े हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में कुल्लू विधान सभा क्षेत्र का एक स्कूल है, डुघीलग, वहां पर एक ऐसे भवन में बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जिसको विभाग ने अनसेफ डिक्लेयर किया है। अनसेफ डिक्लेयर किया परन्तु डिसमेंटल नहीं किया गया। बच्चे उसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कल अगर कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेवार कौन है?

सभापति महोदया, अनेक विषय कहने को हैं। क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य हर तरफ से कुल्लू मनाली के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक बात उठी थी कि कुल्लू और मनाली के मध्य पतलीकूहल में अग्निशमन केंद्र होना चाहिए। इसके बारे में विभाग ने सरकार को पत्र भेजा। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आई है उसमें कुल्लू-मनाली के मध्य पतलीकूहल में यह अग्निशमल केंद्र निरस्त कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि फायर स्टेशन नहीं दिया जाएगा। आखिरकार यह सब क्या है?

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

15.03.2016/1715/SLS-AS-1

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर ...जारी

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मनाली के साथ एक और बड़ा अन्याय हो रहा है। अभी यहां पर जी.एस. बाली जी नहीं बैठे हैं। मैंने हिमाचल प्रदेश भर से जानकारी ग्रहण की। किसी भी डिपो की बसिज दूसरे जिले के लोकल रूट पर नहीं चलतीं। लेकिन यह हैरानी की बात है कि कुल्लू एच.आर.टी.सी. डिपो में एक तरफ तो

बसों की कमी है लेकिन हमारी 8 बसें दूसरे जिले के लोकल रूट पर चलती हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता लेकिन अगर वह बसें उन्हीं जिलों से चले तो 8 के स्थान पर हमारे भी 10 रूट चलेंगे। वह बसें बाहर चलती हैं जबकि बाहर की कोई बस कुल्लू के डिपो में नहीं चलती। यह बात सहकारिता मंत्री जी को भी भली प्रकार से ज्ञात है। मैंने कुल्लू के राईट बैंक और लैफ्ट बैंक का हिसाब-किताब मांगा था कि लैफ्ट बैंक के लोगों से कितना न्याय और राईट बैंक के लोगों से कितना न्याय हो रहा है। अगर राईट बैंक में मनाली से कुल्लू 100 बसें चलती हैं तो लैफ्ट बैंक में केवल 20 बसें चलती हैं। इसलिए इसमें जनसंख्या आधार पर कुछ किया जाए। इस प्रकार के अनेक भेद हैं।

मनाली के अंदर पी.पी.पी. मोड पर एक बस अड्डा बनना था। उसका वर्ष 2014-15 से एक ही जवाब मिल रहा है कि 1.0932 हैक्टेयर भूमि का चयन किया गया है लेकिन अभी तक इसकी फोरैस्ट क्लीयरैंस नहीं आ रही है। फिर कहते हैं कि इसको बनाएंगे, जबकि इसका भी वही हाल है। पतली कूहल में बस टर्मिनल बनना था। उसमें सन् 2012 से आपका उत्तर आ रहा है कि यह फोरैस्ट की ज़मीन है, इसके लिए भूमि स्थानांतरण का केस चला है और अभी तक वह भूमि स्थानांतरण नहीं हो पाया है, इसलिए अभी यह काम नहीं चला है। यानी कब-कब के कितने मामले लटके पड़े हैं। इन सबमें या तो सरकार की मंशा है कि यह सब-के-सब काम नहीं करने हैं,...(व्यवधान)...

Chairperson: Hon'ble Member please wind up.

15.03.2016/1715/SLS-AS-2

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर : सभापति महोदया, अंत में मैं दो-तीन बातें रखना चाहूंगा। 2010-11 में विधायक प्राथमिकता में मैंने कहा था कि पलचान से औट नदी की चैनेलाईजेशन करनी आवश्यक है। इसके लिए 1155 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. बनकर तैयार हो गई है। लेकिन प्रदेश सरकार गत 2 वर्षों से एक ही उत्तर दे रही है कि इसमें अभी पता नहीं कहां-कहां पर क्या चला है। एक हमारी और योजना लगभग 400 करोड़ रुपये की है - प्रीणी से लेकर बिजली महादेव तक सिंचाई योजना, जिसकी डी.पी.आर. भी लगभग 400 करोड़ रुपये की बनी है। लेकिन लगता है कि विभाग ने उसमें कोई कमी छोड़ी है। हमारे सब-के-सब काम इसी तरह लटके पड़े हैं।

सभापति महोदया, मैं इस माननीय सदन में इस बजट का तो विरोध करता ही हूं , लेकिन एक बात और करता हूं। यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो बातें बहुत बढ़िया की जिनके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। एक तो यह है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि को 75 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये किया। सभापति महोदया, ये पैसा विकास के कार्यों में लगता है। जन-प्रतिनिधि होने के नाते हम सब उसको लेकर जाते है और उससे जनता को सुविधा होती है। मैं आपके माध्यम से यहां पर निवेदन करूंगा, हमने सुना है कि दिल्ली में यह राशि 4.00 करोड़ रुपये है, उत्तराखंड में 3.00 करोड़ रुपये है। आपने इसे एक करोड़ किया है। आप अगर इसे डेढ़ करोड़ रुपये तक कर देते तो और भी अच्छा होता। इसके अलावा जो ऐच्छिक निधि की बात है,यह आपने प्रारंभ की है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। अभी 4.00 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक किया है। लेकिन एक बात आप सब जानते हैं कि ये पैसा किसी बीमार को हजार रुपया, दो हजार रुपया, पांच हजार रुपया होकर जाता है या कोई अग्निकांड से पीड़ित है, ऐसे व्यक्तियों के बहुत काम आता है। अगर इसे 4.00 लाख रुपये से 8.00 लाख रुपये करते तो अच्छा होता क्योंकि यह पैसा सीधे-सीधे ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास जाता है।

15.03.2016/1715/SLS-AS-3

माननीय सरवीन चौधरी जी यहां पर आ गई हैं। यहां पर संजय रतन जी भी हैं। संजय रतन जी भी हम सबकी बातों के बड़े वकील हैं औार इसके लिए मैं इनकी तारीफ़ करता हूं। मैं सरवीन जी से मज़ाक कर रहा था कि बाकी सबसे पंगा ले लो लेकिन संजय रतन जी को न छेड़ा करो। ये सबकी चिंता करते हैं। निश्चित तौर पर अच्छी बातों का हम स्वागत करते हैं।

अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि जो-जो बातें हम चाहे विधायक प्राथमिकता की मीटिंग्ज में या इस माननीय सदन में कहते हैं, क्या इस बात की कोई चैकिंग है कि इन बातों का नीचे अधिकारियों तक असर जाता है या यह केवल भाषणबाजी ही होती है।

इतना कहते हुए, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

सभापति : अब श्री नन्द लाल जी, माननीय मुख्य संसदीय सचिव चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नन्द लाल जी ...श्री गर्ग जी के पास

15/03/2016/1720/RG/DC/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री नन्द लाल) : सभापति महोदया, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिनांक 8 मार्च, 2016 को जो वित्तीय वर्ष 2016-17 का वित्तीय अनुमान इस सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदया, यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है यह अपने आप में एक इतिहास है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपना यह 19वां बजट इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया है। यह काफी डिटेल्ड बजट है जोकि लगभग साढ़े तीन घण्टे में यहां पढ़ा गया।

सभापति महोदय, despite constraints and cuts in the funds made available by the Centre, Hon'ble Chief Minister has presented a tax free budget. होता क्या है कि हर आदमी को उम्मीद होती है कि टैक्स पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और घर का खर्चा करने में दिक्कत आएगी। So this is supposed to be a tax free budget.कोई टैक्स इंपोज़ नहीं किया, उसके लिए भी हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं और पूरा हिमाचल उनका धन्यवाद करता है। जब टैक्स नहीं बढ़ेंगे, तो इनफ्लेशन पर भी चैक रहेगा। क्योंकि महंगाई बढ़ने के दो मेन फैक्टर्ज होते हैं, one is imposing the tax और दूसरा जो ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग है उस पर चैक न होना। एक है कि जब डिमाण्ड और सप्लाई का कोप नहीं करता तब महंगाई बढ़ती है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ये तीनों बातें ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही balanced and tax free बजट पेश किया। हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। सभापति महोदया, बहुत अच्छे सजेशन्ज ऐक्सपेक्टेड थे from our friends on the other side लेकिन कुछ ऐसा कंक्रीट नहीं लगा जिसमें कुछ अच्छा इनपुट हो, कोई अच्छे सजेशन हों, जोकि हमारी revenue receipt side है, expenditure side है उसमें कुछ अच्छे सजेशन्ज आते और बजट का एक अच्छा आनन्द मिलता, तो अच्छा होता। विपक्ष की तरफ से जो कम्पेरीजन करना शुरू

हुआ, स्टेट इकॉनॉमी का कम्पेरीजन हुआ, इन्होंने वर्ष 2001 से शुरू किया, बेहतर रहता कि ये वर्ष 2009-10

15/03/2016/1720/RG/DC/2

से शुरू करते और वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 के साथ कम्पेयर करते, तो स्टेट इकॉनॉमी का उनको अपने आप आइडिया हो जाता कि what is the factual thing. अच्छा, विपक्ष का जो रवैया रहता है कि प्रदेश में सारी प्रगति और विकास हो रहा है। एक अच्छा बजट है, हर क्षेत्र और हर सैक्टर के लिए एक बहुत अच्छा और balanced budget allocation of funds का इन्तजाम हुआ है मगर it is their compulsion कि उनको बजट के विरोध में कुछ-न-कुछ कहना ही है, तो उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब ये केन्द्र सरकार के बजट की बात करते हैं, any funds released by the Centre, उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि हिमाचल जैसे प्रदेश को जब तक केन्द्र से कोई फण्ड्ज का इन्तज़ाम नहीं होता, all hilly states for that matter, तो we cannot function. एक सिस्टम है कि जितनी भी सेन्ट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्ज हैं या हमारे प्रदेश में जो कुछ स्कीम्ज चलती हैं उनकी जो फण्डिंग होती है इसका एक शेयर होता है और केन्द्र एवं राज्य का अपना-अपना शेयर होता है उसके अनुसार ये स्कीम्ज इम्प्लीमेंट होती हैं। Thus, this is nothing new कि this time they have given this. यह उन्होंने दिया, यह उन्होंने दिया है। यह कोई नई बात नहीं है। यह एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर जो भी ग्रांट वहां से मिलती है या जो भी वहां से एड मिलती है, तो यह सरकार का अधिकार है। Because they have to claim it. ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात हो रही है। इसमें खुश होने की कोई बड़ी बात नहीं है। It is the Government who has to take up issues with the Central Government and whatever they get, it is their fundamental right.

एम.एस. द्वारा जारी

15/03/2016/1725/MS/DC/1

श्री नंद लाल (मुख्य संसदीय सचिव)जारी---------

सभापति महोदया, हम सब लोग जानते हैं कि बजट एक ऐसी स्टेटमैंट होती है जिसमें रेवेन्यु रिसीट और एक्सपेंडीचर का एक पूरा खाका बना होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वर्ष 2016-17 का बजट पेश किया है, उसमें टोटल जो रेवेन्यु रिसीट्स हैं It is estimated for about Rs.32372.76 crores इसी तरह से जो एक्सपेंडीचर है Rs. 32593.30 crores and opening deficit would be Rs. 1642.41 crores और डैफिसिट को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको बहुत बेलैंस किया हुआ है। उस तरफ से जो मेरे मित्र बोल रहे थे, they were mentioning कि फिगर्ज का जो एक आंकड़ा पेश किया जा रहा था कि इसके लिए वह गया, उसके लिए वह गया। It is a system. The economics has to be understood. यह बोलना कि इसमें इतना नहीं बचा, I am talking about the loans, advances and liabilities. They are piled up for years together, ये कोई वर्ष 2010-11 या वर्ष 2012 से शुरू नहीं हुआ है। It is piled up for the years together, तो चलता है। इसकी लायबिलिटी की पेमैंट को भी गवर्नमैंट रिलीज करती है। यह बात ठीक है कि आज वित्तीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इस बात को मानता हूं slowly with the passage of time things will improve. आज नेशनल इकॉनोमी को अगर आप देखेंगे, it is not in a very good condition, atleast for the last two years और हमारा हिमाचल का जो इकॉनोमिकल स्टेट्स है it is better than the Centre इसलिए मेरा यह कहना है अगर मैं नेशनल इकॉनोमी की बात कहूं तो वर्ष 2015-16 में एक्सपोर्ट that has declined to 75.6 %, तो नेशनल इकॉनोमी की अच्छी हालत नहीं है। जबकि क्रूड ऑयल के जो प्राइसिज हैं it has been reduced to 75%. 75 प्रतिशत इस क्रूड ऑयल की जो कमी आई तो इसमें कुछ नया देखने को नहीं मिला है। कोई इन्फ्लेशन में फर्क नहीं हुआ। देखिए, जब तेल की कीमतें कम होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी चीजों पर खर्चा कम होगा लेकिन महंगाई में कोई चीज नज़र नहीं आई। महंगाई की कमी रही। अभी केन्द्र सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री जी की यहां काफी तारीफ हो रही थी कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ और बड़ी भारी स्कीमें गिनवाई। हम तो यह

कहना चाहेंगे कि जो महंगाई है यह ऐसा इशू था during the Parliament Elections कि उस पर लोग वोट बटोरेंगे और

15/03/2016/1725/MS/DC/2

महंगाई का आलम आप देख रहे हैं। In last two years क्या देखने को मिला? दाल की कीमतों में बढोत्तरी है, इस बात को पूरा सदन जानता है। राजस्थान के अंदर that was the highest जो वहां दाल की कीमत थी जबकि वहां बीजेपी की सरकार है। तो जो वह दाल की कीमत थी that was supposed to be highest in the country. यह तो महंगाई का आलम है और बाकी चीजों में हमें क्या कमी दिखी? इसलिए ये सारी बातें कहना ठीक नहीं है। जब क्रूड ऑयल प्राइस में कमी होती है तो जरूर फिर कुछ-न-कुछ नया दिखना चाहिए था जिससे हमारी इण्डियन इकॉनोमी इम्प्रूव हो जाए। ग्रोथ रेट वर्ष 2015-16 में 7.6 प्रतिशत हुआ जबकि वर्ष 2014-15 में 7.2 प्रतिशत था। If you talk about the State economy, सभापति जी, जैसा मैंने शुरू में कहा कि जो हिमाचल की इकॉनोमी है; it is dependent on agriculture and horticulture.ये दो मेन इस तरह के सैक्टर्ज हैं जिससे हमारी इकॉनोमी पर बहुत बड़ा असर रहता है। सरकार के प्रयासों से हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों सैक्टर्ज में हिमाचल प्रदेश ने काफी प्रगति की है और किसानों के काम करने के तरीके में एक अच्छा जज्बा दिखा। पिछले तीन सालों में Himacal has emerged as the model of development for the hilly States in the country और ग्रोथ रेट has been estimated to 7.7% during 2015-16, against the National Growth Rate of 7.6 %. In that way our growth rate is better than the National Growth Rate. जहां तक पर-केपिटा इन्कम की बात है, सबने बजट भाषण के अंदर उसको पढ़ा होगा। जो पर-केपिटा इन्कम प्रदेश की होती है, वह एक इंडिविजुअल की जो आर्थिक स्थिति है उसको दर्शाता है। In Himachal It has improved. वर्ष 2013 में हमारी पर-केपिटा इन्कम 98996 था और अब उसको वर्ष 2015-16 में बढ़ाकर,

सभापति महोदया श्री जे0के0 द्वारा--

15.03.2016/1730/जेएस/एजी/1

श्री नंद लालः----जारी----------

सभापतिः माननीय सदस्य एक मिनट । माननीय सदन की बैठक साढ़े पांच बजे तक बढ़ाई गई थी। इनके बाद पांच वक्ता और हैं तो इस बारे में सदन की क्या मंशा है? आधा घंटा तक बढ़ाते हैं। ठीक है, 6.00 बजे तक सदन की बैठक बढ़ाई जाती है।

श्री नंद लाल (मुख्य संसदीय सचिव)ः सभापति महोदया, जैसे कि मैं यहां पर पर-केपिटा इन्कम की बात कर रहा था यह 1 लाख 30 हजार 67 हो गई । There is an increase of 31 per cent straight. सभापति महोदया, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक अच्छा विज़न व दूरदर्शिता इस बजट के अन्दर दिखाई है। जो UN ने एडॉप्ट किया था an agenda in September, 2015 for sustainable development to be achieved by all nations by 2030. इस बजट में आप सबने पढ़ा होगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वस्त किया है कि जो हिमाचल प्रदेश की सस्टेनेबल ग्रोथ हिमाचल प्रदेश की है उसका जो टारगेट है, उसकी मैक्सिमम चीजें करीब वर्ष 2022 तक उन्होंने कम्पलीट करने की बात कही जिसमें मुख्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि बी0पी0एल0 की जो परसेंटेज है इसको नीचे लाया जाएगा। 1.1 परसेंट से 2 परसेंट तक। यह बहुत बड़ी बात होगी । जो बी0पी0एल0 का दायरा है, पावर्टी लाईन से नीचे जो लोग हैं, वे सिर्फ स्टेट के अंदर दो परसेंट रहेंगें। Safe drinking water will be made available to all in the State. सबको मिलेगा। जितनी भी हमारी पंचायतें हैं वे सब के सब रोड़ज से कनैक्ट की जाएगी। इसी तरह से electric connections will be given to all the consumers. Infant Mortality Rate को रिड्यूस करके 35 per cent to 20 per cent per thousand, ये भी टारगेट रखा है। इस तरह की जो कुछ चीजें हैं उस ऐजैंडे के अन्दर हिमाचल स्टेट में जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कही है यह एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। जैसे कि enrolment of boys and girls will be 100 per cent in the schools. आज यह हालत है कि पूरे बच्चे स्कूल में जा नहीं सकते तो 100 per cent enrolment will be made in the schools by 2020. Similarly, enrolment in the colleges would be 29 to 36 per cent. और dropout को तो बिल्कुल ही कम करने का

यानि ज़ीरो लाने का उसमें बात कही गई है। यह एक सोच है, मिशन है। यह इस साल की बात नहीं है अगले आने वाले सालों में हिमाचल की क्या सूरत होगी ये उसमें दर्शाया है। सभापति महोदया, Planning Commission used to approve

15.03.2016/1730/जेएस/एजी/2

and substantially finance the State Plan. अब क्या हुआ कि वर्ष 2014-15 में हिमाचल गवर्नमैंट received around Rs. 2000/- crores under this Scheme अब यह नीति आयोग आया। उसके अन्दर there is a cut. A very important source of financing उसमें एक कट आ गया because of the NITI Ayog फिर भी जेन्यून प्लान जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, it is proposed for Rs. 5200/- crores for 2016-2017 in which there is an enhancement of Rs. 400/- crore from the earlier Plan. Out of the total outlay of Rs. 5200/- crores, Rs. 1300/- is proposed for Scheduled Caste Component Plan; Rs. 460/- crores for Tribal Sub Plan and Rs. 65/- crores for Backward Area Sub Plan. इसी तरह से सभापति महोदया, 90:10 की जो बात अभी चली हुई है जो कि सेन्ट्रल स्पोंसर्ड स्कीम के लिए, दूसरी स्कीम के लिए जो पैसा नीति आयोग से मिलना था after lot of persuasion made by the Hon'ble Chief Minister and the Government, इस तरह की जो स्कीमें हैं उसमें जो 90:10 का फायदा मिला है उसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री को मुबारकवाद देना चाहेंगे और धन्यवाद करना चाहेंगे कि यह जो 90:10 की पॉलिसी है इसमें हमारी डिफरैंट स्कीम्ज़ कवर हो रही हैं। सभापति महोदया, एक्सटर्नली एडिड जो प्रोजैक्ट्स हैं, this is a very useful to the economy of the Special Category States. आज के दिन में seven Externally Aided Projects are implemented in the State जिसमें पब्लिक वर्कस है, फोरैस्ट भी है, टूरिज्म है,एग्रीकल्चर है और यह करीब 11 हजार 978 करोड़ के करीब ये स्कीम्ज़ डिफरैंट सेक्टर्ज में हिमाचल के अन्दर चल रही हैं,

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

15.03.2016/1735/SS-AG/1

श्री नन्द लाल, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः

मैंने जैसे शुरू में कहा कि 31 मार्च, 2014 तक का स्टेट पर जो बर्डन है वह 35151 करोड़ का था। For 2017, interest outgo is likely to be Rs. 3400/- crores. जैसे मैंने कहा कि अभी यह पाइल अप नहीं हुआ, यह पुराना काफी सालों से इस तरह चल रहा है और इस लाइबिलिटी को धीरे-धीरे ठीक किया जायेगा।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा कि विधायक क्षेत्रीय विकास निधि एक करोड़ रुपये की है। हम सब लोग जानते हैं कि like in a particular sub division if there are 50 panchayats, तो 50 पंचायत में अगर आप दो-दो लाख से कोई छोटी-छोटी स्कीम करेंगे या कोई छोटा-सा सामुदायिक भवन हो या महिला मंडल का भवन हो, this cannot be done in Rs. 2/- or Rs. 3/- lacs. Now you will be in a position to at least provide Rs. 2/- lac to each panchayat having 50 panchayat in a sub division. इसके लिए हम माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहेंगे।

इसी तरह से जो विधायकों की डिस्क्रिशनरी ग्रांट थी उसको दो से चार और आज चार से पांच लाख रुपया किया, उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने घंटी तो बजा दी है परन्तु मैं इतना ज़रूर कहना चाहूंगा कि हर फील्ड में काम हुआ है। फूड सिक्योरिटी ऐक्ट के अंदर जो राजीव गांधी अन्न योजना थी उसमें we are the second in the country. अब बी0पी0एल0 कैटेगिरी के 37 लाख लोगों को इसका फायदा हो रहा है। पहले से ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो स्टेट सबसिडी स्कीम चली थी उसके अंदर 2007 में तीन दालें, दो तरह के तेल और आयोडीन नमक का प्रोविजन किया था। Every ration card holder is getting that. 35 किलो का राशन सब राशनकार्ड होल्डर्ज़ को मिल रहा है।

थोड़ा-सा मैं एग्रीकल्चर सैक्टर में कहना चाहूंगा। मैंने शुरू में ही कहा कि एग्रीकल्चर हमारी स्टेट की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इसमें हम सब को मालूम है कि हमारे गांव में रहने वाले जो 90 परसैंट लोग हैं उनका मुख्य पेशा एग्रीकल्चर

और होर्टिकल्चर ही है और स्टेट की इकोनॉमी पर एग्रीकल्चर की डिपैंडैंस बहुत रहती है। इसमें एक कृषि कर्मण अवार्ड जो जनवरी, 2016 में मिला है उसके लिए हम

15.03.2016/1735/SS-AG/2

सरकार/माननीय मुख्य मंत्री जी को मुबारकवाद देना चाहेंगे। इस तरह से बहुत-सी स्कीमें हैं। अभी थोड़ी बात चल रही थी कि गांव में लोगों ने फसलें बीजनी छोड़ दी हैं क्योंकि मंकी मिनेस है। फिर वाइल्ड एनीमल की तरफ से प्रॉब्लम होती है। एक बहुत अच्छी स्कीम, जो फैंसिंग वाली बात कही है, कुछ लोगों ने उसको भी पसन्द नहीं किया हो, मगर मेरा यह कहना है कि we have tried everything. मंकी मिनेस के खिलाफ हमने स्टरलाइजेशन सैंटर खोले। Culling/export का जो इश्यु सैंटर गवर्नमैंट से टेक अप करना था that has been taken up. मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रॉब्लम के लिए फैंसिंग एक अच्छा सोल्यूशन है and I am hopeful कि जो हमारा एग्रीकल्चर या होर्टिकल्चर सैक्टर है इसमें फैंसिंग के साथ लोग अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा पायेंगे और स्टेट की इकोनॉमी को बहुत बड़ा इजाफा मिलेगा। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 20 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया उसके लिए हम इनका धन्यवाद करना चाहेंगे।

बहुत सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के अंदर हैं। ऑर्गैनिक फार्मिंग की बात की। अब मैं थोड़ा-सा होर्टिकल्चर की बात करना चाहूंगा। हमारे प्रदेश के अंदर जो लोग हैं वे थोड़े से एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर की तरफ शिफ्ट हुए हैं in the last few decades क्योंकि 1950-51 में जो 792 हैक्टेयर में सेब उगाये जाते थे या हमारी फ्रूट क्रॉप होती थी अब इसका एरिया बढ़ गया है। It has gone to 2,22,352 acres. और फ्रूट प्रोडक्शन की मात्रा भी काफी बढ़ गई है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां अब जो एंटी हेल्ज़ नैट सब्सिडाइज्ड रेटस पर मिल रही है, कई लोग उसका भी विरोध कर रहे थे। मैं यह कहूंगा कि यह बड़ा फुलप्रूफ सिस्टम है। If you have the net on plant तो वह एलिंग से भी बच जायेगा और दूसरी तरफ पूरी प्रोटैक्शन देता है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सबसिडी का प्रोविजन रखा है उसके लिए हम बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। ज्यादा-से-ज्यादा

एरिया इस वित्तीय वर्ष में जो कवर करने का प्रोविजन रखा है उसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे। यह एक सोच है, it is a vision. एक और चीज़ है। एप्पल रिजुविनेशन स्कीम के अंदर जिस तरह से इटली और

जारी श्रीमती के0एस0

15.03.2016/1740/केएस/एएस/1

श्री नन्द लाल (मुख्य संसदीय सचिव) जारी----

नीदरलैंड से जो नए किस्म के प्लांट्स, स्पर वैरायटी जो हिमाचल के अंदर लाई जा रही है, यह अपने आप में एक वरदान होगा। अच्छी बात रहेगी कि जो प्लांट्स हैं, प्रोडक्शन है, altogether a different variety जल्दी पैदा होने वाले और कम एरिया कवर करने वाले हैं और उसकी मार्किट भी अच्छी रहेगी, यह बहुत अच्छा कदम है।

सभापति महोदय, कहने को तो बहुत कुछ है परन्तु मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हिमाचल के अंदर पिछले तीन सालों में जो भी किया गया, वह चाहे रोड़्ज़ कनैक्टिीविटी की बात हो, ऐजुकेशन की बात हो, हैल्थ की बात हो, हर क्षेत्र में बहुत कुछ किया गया है और मुझे उम्मीद है कि यह जो अभी बजट आया है, जिस तरह की बजट की एलोकेशन हुई है in different sectors of the of development मुझे विश्वास है कि हमारा प्रदेश बहुत आगे जाएगा । सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं इस बजट भाषण का पुरजोर समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

15.03.2016/1740/केएस/एएस/2

सभापतिः अब माननीय सदस्य नरेन्द्र ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगें।

श्री नरेन्द्र ठाकुरः सभापति महोदया जी, 8 मार्च को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया और जिस पर माननीय धूमल जी ने चर्चा आरम्भ की, उस पर बोलने का आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। 1427.87 करोड़ रु0 के घाटे के साथ इस साल का बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया। बहुत चर्चा हुई,

चर्चा जारी भी है लेकिन बजट में कुछ अच्छी बातें भी है। जैसे विधायक निधि एक करोड़ रु0 कर दी। डिस्क्रीशनरी ग्रांट पांच लाख रु0 कर दी लेकिन जो इस बजट में सबसे बड़ी खामी है, जिसके बारे में अभी तक सत्ता पक्ष बिल्कुल चुप है कि हमारे स्टेट की जो वित्तीय स्थिति है, 1427 करोड़ रु0 का जो घाटा चला हुआ है, उसकी भरपाई कैसे हो? हमारी वित्तीय स्थिति कैसे स्ट्रोंग हो, इसके बारे में बहुत कम चर्चा सुनने को मिली। खजाना खाली है, जेबे हमारी खाली हैं और उनके भरने की कोई उम्मीद नहीं है और न ही इस बजट में कोई ऐसा प्रावधान है। हमें बार-बार परसुएड करते हैं और हर बार यह पोजिशन आती है कि आप भी हमारे साथ केन्द्र में चलो और कुछ पैसा वहां से लाओ। हिमाचल राज्य की पोजिशन भिखारियों की तरह हो गई है और एक कहावत है कि एक शहर में कोई 40-45 के करीब भिखारी थे । वे इकट्ठे रहते थे और सुबह वे भीख मांगने जाते थे और शाम को जब इकट्ठे हो कर आते थे और जितनी भिक्षा लाते थे, इकट्ठे बैठकर उसका डिनर कर लेते थे। कई बार भिक्षा बहुत कम आती थी तो उन्हें भूखे भी सोना पड़ता था और कई बार बहुत ज्यादा आ जाती थी तो वे मौज-मस्ती करते थे, होटलों में चले जाते थे। लीगली और इलिगली सब कुछ करते थे और दूसरे दिन फिर वैसा ही रूटीन शुरू हो जाता था। वही पोजिशन आज हिमाचल सरकार की है। यहां पर भारी-भरकम संसदीय सचिव बना दिए हैं, भारी-भरकम मंत्रिमण्डल है और चेयरमैनों की तो गिनती ही नहीं है और एक-एक चुनाव क्षेत्र में दो-दो चेयरमैन हैं। सभी के पास लग्ज़री गाड़ियां हैं। पूरा स्टाफ है, काम कुछ नहीं है और टी.ए. डी.ए. का मेरे हिसाब से महीने का, इस बारे में एक बार विधान सभा में प्रश्न का जवाब भी आया था, एक-एक चेयरमैन को दो-दो लाख, तीन -तीन लाख महीने का टी.ए.डी.ए. मिल जाता है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

15.3.2016/1745/av/as/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर------- जारी

बिना काम का और जितने भी चेयरमैन है। (---व्यवधान---) आप देखो तो जरा। मैं जो बोल रहा हूं फैक्ट्स पर बोल रहा हूं। (---व्यवधान---) आप पहले सुन तो लो। इतने ज्यादा चेयरमैन है कि मेरे ख्याल से सरकार को एक साल के अंदर उनकी एमीनिटीज को

पूरा करने के लिए करोड़ो रुपये खर्च करने पड़ते हैं। (---व्यवधान---) उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया और उसमें मुकेश अग्निहोत्री जी का भी बड़ा हाथ है। (---व्यवधान---) उन चेयरमैन्ज के ऊपर करोड़ो रुपये खर्च करने पड़ते हैं। खर्च करो और करना भी चाहिए। जब आप सैल्फ इंडीपैन्डैंट हैं और आपके पास ऐक्स्ट्रा मनी है तो आपका राइट बनता है कि आप बनाइए, चेयरमैन बनाइए जो मर्जी बनाइए। लेकिन जब आप अपना बजट 1427 करोड़ रुपये के घाटे के साथ पेश कर रहे हैं तो इसकी जरुरत नहीं है। आपको जापान का उदाहरण देता हूं। जापान पर जब आर्थिक संकट आया था तो उन्होंने एक प्रण किया था कि जब तक हम अपने आर्थिक संकट से नहीं उभर पायेंगे तब तक हम सरकार से कोई एमीनिटी नहीं लेंगे। यहां पर हमारी स्टेट की इतनी बुरी हालत है और स्टेट का दिवालिया निकल रहा है। यहां इतने सारे सी0पी0एस0, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बना दिए कि एम0एल0ए0 तो हमें कोई दिखता ही नहीं है। अब तो डिसकशन में भाग लेने के लिए कोई एम0एल0ए0 ही नहीं बचा, सारे-के-सारे लग्जुरियस गाड़ी में घूम रहे हैं। फिर कहते हैं कि आप स्टेट के गरीब लोगों के हित की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बल्कि आप तो इस स्टेट को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। आप भलाई की कोई बात नहीं कर रहे हैं और इसमें कोई झूठ नहीं है। (---व्यवधान---) बिल्कुल, मैं सहमत हूं। आप स्टेट को इंडीपैंडैंट बनाइए, इसकी आर्थिक स्थिति सुधारिए। हमें जो कंट्रीब्यूट करना होगा; हम करेंगे। मैं हाउस में ओपनली बोल रहा हूं। (---व्यवधान---) मैं अब इस स्टेट की फाइनैंशियल पोजिशन पर बोलना चाहूंगा। मैंने इस बार के डैफिसिट के बारे में कह दिया है। आपकी टोटल रिसीट्स 32372 करोड़ रुपये की है और खर्चा 32593 करोड़ रुपये है। इस साल का डैफिसिट 1642.41 करोड़ रुपये है

15.3.2016/1745/av/as/2

और इसमें 20 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी जो जायेगी। (---व्यवधान---) यह कोई मजाक वाली बात नहीं है। यह घाटा अगर इसी ढंग से बढ़ता गया तो विकास के कार्य कैसे पूर्ण होंगे?

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

यहां पर बिन्दल जी ने ठीक कहा और आप इस बारे में सोचिए। यह कोई मजाक की बात नहीं है।(---व्यवधान---) आप मेरी बात सुन लीजिए। आपका टोटल बजट का 29 प्रतिशत पे में चला जाता है। 14 प्रतिशत पेंशन में जाता है, 11 प्रतिशत ब्याज में जाता है और 5 प्रतिशत लोन को वापिस करने में चला जाता है। इस तरह से 60 प्रतिशत तो सीधा चला गया तथा बाकी 40 प्रतिशत ब्यूरोक्रैट्स और टैक्नोक्रेट्स की एमीनिटीज को पूरा करने में लग जाता है। आपके पास विकास के लिए सौ में से सिर्फ 13 प्रतिशत पैसा बचता है। उस 13 प्रतिशत में भ्रष्टाचार कितना प्रतिशत हो जाता है वह आप सबको पता है। हमने पिछले तीन वर्षों में देख लिया कि आपके पास विकास के लिए कोई पैसा नहीं है। आपने विधवा पेंशन 600 रुपये बढ़ा दी है (---व्यवधान---) साथ में आप यह भी कह रहे हैं कि एक विधवा को अपना परिवार चलाने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्या 1200 रुपये में एक विधवा औरत अपने परिवार को चला सकेगी? अगर दो टाइम चाय भी पीनी हो तो पूरे महीने में 1200 रुपये से वह खर्चा पूरा नहीं होगा। आपने 600 रुपये बढ़ा दी और बड़ी पीठ थप-थपा रहे हैं। मगर करे भी क्या, आप इसके अलावा कर भी कुछ नहीं सकते। आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप लोगों ने करना क्या है। जो छोटी-मोटी 50-100 रुपये की राशि बढ़ा रहे हैं आप उसके लिए बड़ी प्रशंसा ले रहे है। मैं यह कहता हूं कि आपकी हालत बहुत बुरी है। (---व्यवधान---) जब काला धन आ जायेगा। (---व्यवधान---) यह मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है,

टी सी द्वारा जारी

15.03.2016/1750/TCV/AG/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर -----जारी।

मोदी जी ने यह नहीं कहा है कि जो 15 लाख रूपये हैं वह आपकी जेब में डाल दिया जाएगा। मोदी जी ने यह कहा है कि अगर काला धन पूरा आ जाएगा तो डैवैल्पमेंट के लिए एक-एक के हिस्से में 15-15 लाख रूपया आएगा। उन्होंने आपकी जेब में डालने के लिए नहीं कहा है। (--व्यवधान ---) खाते तो जब "जन-धन योजना" आई तब खुले। "Argument for argument sake" नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्य श्री कालिया जी आप मेरे बात सुन लीजिए, ये आपको भी पता है कि कालाधन विदेशों में हैं और आपको यह

भी पता है कि यह कालाधन किसका है? वह वापिस आएगा, आप चिन्ता न करिए। माननीय मुख्य संसदीय सचिव (धर्माणी) जी का क्या कहना। कल जब ये बजट भाषण पर बोल रहे थे, तो मैं बड़ा हैरान था और मुझे तो यह पता नहीं लग रहा था कि धर्माणी जी ने अपनी पहचान भी चेंज कर दी है। ये धर्माणी जी की एक खासियत है कि ये सच को सच बोलते हैं। लेकिन जब कल ये बज़ट भाषण बोल रहे थे तो ये तो भूल ही गये कि ये धर्माणी बोल रहे हैं। मुझे भी शक हो गया कि यह धर्माणी नहीं बोल रहे हैं, कोई और बोल रहे हैं। बज़ट बुक में सब डेटे हैं, यह डैटे जो मैं पढ़ रहा हूं वह भी बज़ट बुक के ही डैटे है। हमारे रामपुर के माननीय विधायक एग्रीकल्चर के बारे में कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश देश की पहली स्ट्रेट है जिसके 90 प्रतिशत लोग रूरल एरिया में रहते हैं और 62 परसेंट रोजगार, एग्रीकल्चर से हिमाचल प्रदेश को मिलता है। अब डैटे देख लीजिए। पिछले साल 16.74 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन एग्रीकल्चर में हुआ था और इस बार 16.19 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। यह कम हो रहा है और जो हॉर्टिकल्चर है, इसमें 13.2 की कमी आई है। आपने इसको नहीं कोड किया कि यह जो कमी आ रही है इसके बारे में आपकी सरकार ने क्या किया? माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्र साहिब भी यहां बैठे हैं। इन्होंने कहा कि किसानों को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। वह दूसरी बात है। लेकिन जो कमी आ रही है, सरकार ने इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। ये कमी क्यों आ रही है, इसकी वज़ह क्या है? हाऊस में बार-बार डिस्कस हुआ है कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है, वह बंदरों और जंगली जानवरों की वज़ह से हो रहा है लेकिन सरकार ने पिछले तीन सालों से इनको कंट्रोल करने

15.03.2016/1750/TCV/AG/2

के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक आप इन चीजों से मुक्ति नहीं पाओगे, आपका एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर उत्पादन कभी नहीं बढ़ेगा। मैं कहता हूं कि इसके लिए आप बजट डाइवर्ट कर दो लेकिन इस समस्या से हमें मुक्ति दिलाओं ये मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी ।

15.03.2016/1755/RKS/DC/1

श्री नरेंद्र ठाकुर द्वारा... जारी

माननीय कृषि मंत्री जी 2001 में जो हिमाचल प्रदेश का टोटल जी.एस.डी.पी. था उसमें एग्रीकल्चर का 21 प्रतिशत हिस्सा था। आज यह 10 प्रतिशत रह गया है। इसका क्या कारण है? आप किसान है, आपको अवसर मिला है आप इसके ऊपर कुछ करिए। जो आपने खाद के ऊपर सब्सिडि दी है या एक के स्थान पर दो बोरियां दी है उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप इसके ऊपर विस्तार से सोचें कि हमारा एग्रीकल्चर, होर्टीकल्चर कैसे विकसित हो। सरकार की तारीफ करने से या मुख्य मंत्री जी की प्रशंसा करने से इन चीजों में बढ़ोतरी नहीं होगी। इन चीजों में तभी बढ़ोतरी होगी जब आप इस पर ईमानदारी से कार्य करेंगे। लोगों ने आपको चुनकर यहां भेजा है, आपके ऊपर विश्वास किया है इसलिए यह आपका कार्य है कि आपने इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट करना है।

सिंचाई के क्षेत्र में, मैं बात करना चाहता हूं। हमारी 53,604 बस्तियां है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 60 परसेंट बस्तियों को भरपूर पानी का प्रावधान कर दिया गया है। यह आंकड़े झूठे हैं। आप भी मान रहे हैं कि 40 परसेंट बस्तियों को हम अभी तक पूरे पानी का प्रावधान नहीं कर सके हैं। जो सरकार पीने के पानी का प्रबंध न कर सकें, उसके लिए प्रयास न कर सकें और कहते हैं कि हमने इरिगेशन में बहुत बड़ा कार्य किया। आप लोगों को सीवरेज का पानी पीला रहे हैं। आप कह रहें हैं कि हम हैण्डपम्प लगा रहे हैं। आप अभी तक प्रोपर पानी आम-आदमी को उपलब्ध नहीं करवा सके हैं। इससे बड़ी नाकामी सरकार की और कुछ नहीं हो सकती है। हमारी 5.83 लाख हैक्टेयर एग्रीकल्चर भूमि जोती जाती है। 20-25 परसेंट भूमि इरिगेशन के तहत आती है और बाकि सारी भूमि बंजर पड़ी हुई है। क्या इसके बारे में बजट में कोई प्रावधान है, नहीं है? आप बार-बार यही कह रहे हैं कि विधवा पैंशन बढ़ा दी गई, सब्सिडि दी गई या दिहाड़ी 20 रुपए बढ़ा दी गई। इसके अलावा बजट में कुछ और सुनने को नहीं मिल रहा है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप कितना समय लेंगे?

15.03.2016/1755/RKS/DC/2

श्री नरेन्द ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं 10-15 मिनट का समय लूंगा।

(मान्य सदन की बैठक 15 मिनट के लिए सांय 6.15 बजे तक बढ़ाई गई।)

श्री नरेन्द ठाकुरः जहां तक शिक्षा की बात है कुल प्राइमरी स्कूल 10,783,

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

15.03.2016/1800/SLS-AS-1

श्री नरेन्द्र ठाकुर ...जारी

मिडल स्कूल 2249, हाई स्कूल 880, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1610, कॉलेज 94 और इनके अलावा बी.एड कालेज तथा दूसरे संस्थान भी हैं। आपका शिक्षा का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप वर्दी मुफ्त में दे रहे हैं। ए.पी.एल. और बी.पी.एल. परिवारों के बच्चों को आप किताबें भी मुफ्त दे रहे हैं, खाना भी मुफ्त में दे रहे हैं। ...(व्यवधान)...यह अच्छी बात है लेकिन क्या कारण है कि इतने ज्यादा इंसैटिव्ज देने के बावजूद भी दिन-प्रतिदिन स्कूल खाली पड़ रहे हैं। मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूंगा। मेरा घर हमीरपुर से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां बीच में एक डी.ए.वी. स्कूल भी है जो 15 किलोमीटर की दूरी पर है। उनकी बसें प्रतिदिन आती हैं और वह सारे बच्चों को बसों में भरकर ले जाते हैं।...(व्यवधान)...बात सुन लो। मैं क्यों सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं? ...(व्यवधान)... आप मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं आपको उत्तर दूंगा। बीच में कोई 15-20 स्कूल आते हैं जिनके पास बच्चों को ले जाने का कोई आलटरनेटिव नहीं है। वह स्कूल खाली पड़े हैं। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा कि ऐसा क्यों है? शिक्षा के ऊपर सरकार का अधिकतर बजट खर्च हो रहा है। दिन-प्रतिदिन यह बढ़ ही रहा है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रकचर होने के बावजूद भी 40 प्रतिशत बच्चे प्राईवेट स्कूलों में जा रहे हैं। इसलिए अब क्वैंटिटी की ज़रूरत नहीं है। आप स्कूल खोलो। जहां ज़रूरत है आप खोलो, इसके लिए मना नहीं है। पर जब आपने इतने ज्यादा स्कूल खोल दिए हैं जो खाली पड़े हैं और वहां पर करोड़ों का बजट ख़र्च हो रहा है और इतने ख़र्च के बावजूद भी स्कूलों की स्ट्रैंथ

जीरो है तो क्या यह सही है, जबकि आप तालियां पीट रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा को इतना अपलिफ्ट कर दिया। स्कूल खुलने के बाद भी यदि खाली हैं तो क्या इससे आपकी शिक्षा बढ़ती हैं? आपका लिटरेसी रेट 83% है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनमें से 50% केवल अपना नाम लिखते हैं, वह पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए आज वक्त की पुकार है कि आप एक्सपर्ट बिठाइए और अगर ज़रूरी है तो आप प्राईवेट स्कूलों को फौलो कीजिए। आज 50-100 रुपया फीस देने से कोई नहीं कतराता। उस मुफ्त शिक्षा का क्या फायदा जिसे लेने के बाद भी आदमी अनपढ़ रह

15.03.2016/1800/SLS-AS-2

जाए। आपमें से कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होगा। प्राईमरी ऐजुकेशन, आठवीं या दसवीं तक ऐजुकेशन देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। घर में भी न बेटे तैयार होंगे और न बहुएं तैयार होंगी। अगर है तो मुझे उदाहरण दें। बोलने के लिए तो सब बोल लेते हैं। हमारे स्कूलों की ऐजुकेशन की बहुत बुरी दशा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि आप इसके ऊपर सीरियसली सोचें अन्यथा ऐसे स्कूल और कॉलेज खोलने का कोई लाभ नहीं है। वहां बच्चे नशेड़ी बन रहे हैं क्योंकि दसवीं या बारहवीं के बाद उनका भविष्य अंधकारमय है। आप पहली से इंगलिश लगा दीजिए। आप एल.के.जी. और यू.के.जी. क्लासें चलाइए। आपके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप जवाबदेही निर्धारित कीजिए और जो अध्यापक नहीं पढ़ाता है उसको दंडित कीजिए। आप नकल रोकने के लिए कदम उठाइए। आप मॉडल स्कूल बनाने का काम कीजिए और जो लोग ज्यादा पैसा ख़र्च कर सकते हैं उनके लिए अच्छी फीस निर्धारित कीजिए। वहां बच्चे पढ़ेंगे और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं कहता। सभी यही कहते हैं कि इतने स्कूल खोल दिए, ऐसा कर दिया। इस शिक्षा का कोई लाभ नहीं है। इसके लिए आपके द्वारा बैंच पीटने का भी कोई लाभ नहीं है।

जारी ...श्री गर्ग जी

15/03/2016/1805/RG/AG/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर-----क्रमागत

अध्यक्ष महोदय, आज माननीय परिवहन मंत्री जी यहां नहीं हैं, वे चले गए हैं। मेरे ख्याल से दो वर्ष में परिवहन विभाग का दिवालिया निकल जाएगा। अब आप सुनिए, यहां जब कोई इस विभाग का प्रश्न लगता है, तो इनका क्या हाल होता है? इनके कर्मचारी एवं पेन्शनर्ज सड़कों पर आ गए हैं। जो रिटायर हुए हैं हिमाचल पथ परिवहन निगम उनको 3-3 और 4-4 महीने से पेन्शन नहीं दे पा रहा है। आधी से ज्यादा नई बसें इनकी खड़ी हुई हैं। जो जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत नई बसें आई हैं वे आधी से ज्यादा इनकी खड़ी हुई हैं, कहते हैं कि इनके पास स्टाफ नहीं है। उनके पास ड्राईवर और कन्डैक्टर नहीं है। यहां मंत्री जी डींगे मारते हैं और फैक्ट्स को टविस्ट करने में बिल्कुल माहिर हैं। वे बसें खड़ी-खड़ी खराब हो रही हैं। उनका ही यह जवाब है, वह स्टाफ किसने भरना है, वे कंडैक्टर और ड्राईवर किसने भर्ती करने हैं? आधे से ज्यादा रूट्स बंद कर दिए गए हैं। क्या ऐसे परिवहन विभाग चलेगा? यदि स्टाफ नहीं भरा जाता है, तो किसी और के पास महक़मा दे दो। यहां बहुत बड़े ऐक्सपट्र्स हैं, कुछ और भी हैं। तो बार-बार यही है, रूट्स बंद हो रहे हैं, पूछते हैं कि क्या बात है? तो कहते हैं कि स्टाफ की कमी है। साढ़े तीन सालों में स्टाफ नहीं भरा गया, तो क्या अब डेढ़ साल रह गया है उसके बाद आप लोगों ने स्टाफ भरना है। बड़े रूट्स सब बंद हो गए हैं। इसलिए जल्दी-से-जल्दी स्टाफ की कमी को पूरा करिए। क्योंकि यह परिवहन विभाग आम जनता के साथ सीधे जुड़ा हुआ है। यदि इनसे नहीं चलता है, तो इसका टोटल प्राइवेटाइजेशन कर दो। लेकिन विधान सभा में आकर गलत फैक्ट्स कोट मत करिए। वॉल्वो बसें चला दी हैं, तो अच्छी बात है कि चला दी हैं। लेकिन जो आम बसें हैं अब जैसे हमीरपुर में कम-से-कम 20 बसें लगातार स्टाफ की कमी की वजह से खड़ी हैं। नगरोटा में रीजन बनाने की क्या जरूरत थी? एक रीजन बनाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च आता है। पेन्शन इनसे दी नहीं जा रही है और नगरोटा में रीजन बना दिया। नगरोटा के साथ ही धर्मशाला में पहले से ही रीजन है, देहरा में रीजन है, बैजनाथ में रीजन है, तो नगरोटा में क्यों रीजन बनाया? क्या सिर्फ नगरोटा ही रह गया था। बाकी जगह कुछ नहीं है। वहां रीजन बना दिया और वाहवाही लूट ली कि बाली साहब ने यहां

15/03/2016/1805/RG/AG/2

ट्रांसपोर्ट का रीजन बना दिया। बाकियों का बेड़ा गर्क कर दिया। यह तो परिवहन विभाग का हाल है।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सभी महक़मों में बुरी हालत है, लेकिन आज तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह जो बजट है इसमें प्रदेश की विकास की गति देने के लिए कुछ नहीं है, आम आदमी के कल्याण के लिए इस बजट में कुछ नहीं है, गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से निपटने के लिए कोई कदम इस बजट में नहीं उठाए गए हैं। अगर है, तो आप बता दीजिए। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए बजट में मामूली बढ़ौत्तरी की गई है जिससे इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। जैसे पिछले साल था, वैसे ही रहा है। कृषि और बागवानी के लिए जिन योजनाओं की घोषणाओं की गई है वे सभी पुरानी-की-पुरानी योजनाएं हैं। इनमें कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है। बजट के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। प्रति व्यक्ति ऋण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको कम करने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। इसलिए मैं इस बजट का बिल्कुल विरोध करता हूं। यह सभी के विरुद्ध है और आपके भी यह विरुद्ध है। आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक : 15 मार्च, 2016 **सचिव**